हरियाणा विधान सभा

की

कार्यवाही

6 जनवरी, 1975

खंड 1, अंक 4

अधिकृत विवरण

विशय सूची

सोमवार, 6 जनवरी, 1975

पृश्ठ संख्या

	तारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)1
	निमय 45 के अधीन सदन के पटल पर रखे गये तारांकित प्रश्नों के लिखित उत्तर	(4)38
	अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर	(4)49
	1969–70 के अनुदानों तथा विनियोजनों से अधिक मांगों का पेश करना	(4)75
	पटल पर रखे गए कागज–पत्र	(4)75
	राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा	(4)75

हरियाणा विधान सभा

सोमवार, 6 जनवरी, 1975

विधानसभा की बैठक, हरियाणा विधान सभा हाल, विधान भवन, सैक्टर 1, चण्डीगढ़ में 14.00 बजे हुई। अध्यक्ष (चौ. सरूप सिंह) ने अध्यक्षता की।

तारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Mr. Speaker: Question Hour.

Receipt of Scholarships

***1068. Sh. Dhaja Ram**: Will the Minister for Education be pleased to state the district-wise number of the student of 8th class in teh state who received the amounts as scholarship during the years 1972-73, 1973-74 and 1975-76?

State Minister for Education & Transport (Smt. Prasanni Devi): A statement is laid on teh table of the House.

STATEMENT

Name of District	No. of scholarships

	1972-73	1973-74	1974-75
Ambala	108	108	129
Karnal	194	194	98
Gurgaon	211	211	128
Rohtak	232	232	147
Hissar	164	164	133
Narnaul	59	59	85
Jind	46	46	63
Kurukshetra			82
Bhiwani			74
Sonepat			75

श्री धजा राम: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि वजीफा देने का क्राइटेरिया क्या है? किन–किन बातों को मदेनजर रखते हुए एक लड़के को वजीफा दिया जाता है?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): स्पीकर साहब, ये वजीफे सात प्रकार के हैं:–

(1) मिडिल स्कूल स्कालरशिप स्कीम (2) हाई स्कूल मैरिट स्कालरशिप (3) नेशनल स्कालरशिप स्कीम फार दि टेलेन्टिड चिल्डर्ज फ्राम रूरल एरियाज (4) स्टेट हरिजन वैलफेयर स्कीम फार

शिडयूल्ड कास्टस एंड बैकवर्ड क्लासिज (5) मैरिट स्कालरशिप फार हरिजन गर्ल स्टूडेंअस ठन 9, 10 एंड 11 क्लासिज (6) स्कालरशिप फार दी स्टडी आफ संस्कृत इन हाई/हायर सैकेन्डरी स्कूल्ज (7) ऐवार्ड आफ स्टाइपेंड टू डिनोटिफाईड ट्राइबल (विमुक्त जाति)।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1972–73 में कितनी हरिजन गर्ल्ज स्टूडेटस को वजीफा दिया गया?

श्री माडू सिंह मलिक: 150 को मिला है।

Sh. Gulab Singh Jain: Will the Minister for Education be pleased to state the amount for scholarship granted to each student under each category?

श्री माडू सिंह: स्पीकर साहब, 1972–73 में एक लाख ग्यारह हजार चार सौ तीस रूपया दिया गया है। पाँचवी जमात के स्टूडेंटस को दस रूपया महीना मिलता है, आठवीं जमात के स्टूडेंट को 15 रूपया वजीफा मिलता है। नेशनल स्कालरशिप टू दि टेलेन्टिड चिल्डर्न फ्राम रूरल एरियाज इसके अन्डर एक हजार रूपया साल का मिलता है। स्टेट हरिजन वैलफेयर स्कीम में आठ रूपया महीना स्कालरशिप और फीस माफ होती है। मैरिट स्कालरशिप टू शिडयूल्ड कास्टस गर्ल्ज स्टूडेटस को नौंवी क्लास में 20 रूपया, दसवीं में 25 रूपया और 11वीं में 35 रूपया महीना दिया जाता है। संस्कृत की स्टडी के लिए स्कालरशीप नौवीं और

दसवीं क्लास के लिए 10 रूपया महीना है। वैलफेयर आफ डिनोटिफाइड ट्राइबज (विमुक्त जाति) के लिए प्राइमरी में 2 रूपया, मिडिल में पांय रूपया, हाई/हायर सैकेन्डरी क्लासिज में 8 रूपया दिया जाता है। नान–बोरडर्ज के लिए और बोरडर्ज के लिए 17 रूपया, 25 रूप्या ओर 30 रूपया मिलता है।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करैंगे कि इस वक्त जो वजीफे की रकम दी जा रही है उसके रेट को बढ़ाने के ऊपर विचार करेंगे?

श्री माडू सिंह मलिक: स्पीकर साहब, यह रेट पिछले साल ही बढ़ाया गया है।

राव बंसी सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि 1973–74 में बोर्ड आफ ऐजूकेशन के मिडिल क्लासिज के रिजल्ट की परसेन्टेज क्या है?

श्री माडू सिंह मलिक: मिडल की बोर्ड की परीक्षा तो है ही नहीं।

चौ. मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए भी कोई वजीफे देने की स्कीम गवर्नमैंट के अन्डर कंसीड्रेशन है?

श्री माडू सिंह मलिक: एक्स सर्विसमैन के बच्चों के लिए इस समय कोई याजना नहीं है।

चौ. पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह वजीफा सभी हरिजन बच्चों को दिया जाता है या उनमें कोई छटंनी की जाती है?

श्री माडू सिंह मलिक: स्पीकर साहब, जिन बच्चों के मां बाप की आमदनी 4200 रूपए साल है उन हरिजन बच्चों को स्कालरशिप दिया जाता है।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महेादय के नोटिस में यह बात है कि हरिजन बच्चों को जो स्कालरशिप मिलता है वह मन्थली नहीं बल्कि साल के आखिर में दिया जाता है?

श्री माडू सिंह मलिक: स्पीकर साहब, पहले कुछ ऐसी बात थी कि फार्म देर से पहुंचते थे इसलिए देरी हो जाती थी लेकिन अब हमने एस.डी.ई.ओ. को अख्तियार दे दिया है। वे उनको वहीं से पैसा दे देते हैं।

चौ. मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इन सात केटेग्रीज के अलावा जो एक्स सर्विसमैन के बच्चे हैं उनको भी वजीफा देने की स्कीम स्टार्ट करेंगे?

श्री माडू सिंह मलिक: इस वक्त कोई विचार नहीं है।

श्री गुलाब सिंह जैन: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्कालरशिप का जो अमाउन्ट फिक्स किया हुआ है वह

उन बच्चों की एजूकेशन के लिए सफीसेन्ट है, क्या इस बात को गवर्नमेंट ने कंसीडर किया है?

श्री माडू सिंह मलिक: स्पीकर साहब, यह वक्त बे–वक्त रिवाइज होता रहात है पहले यह छह रूपया था अब उसको आठ रूपया कर दिया। हरिजन बच्चों की फीस माफ होती है और वजीफा अलग है।

चौ. पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस मंहगाई को देखते हुए 4200 रूपए की छूट की लिमिट को छह हजार या आठ हजार रूपए करने के लिए कोई प्रोपोजन है?

श्री माडू सिंह मलिक: स्पीकर साहब, अभी थोड़े दिन हुए हमने 1800 रूपए से 4200 रूपए की है।

Drought-Prone Areas of Districts Mohindergarh and Bhiwani

***1087. Rao Dalip Singh**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether the Government has proposed any special scheme for the drought-prone areas of Districts Mohindergarh and Bhiwani; and

(b) if the reply to part (a) above is in the affirmative, the total amount likely to be spent on the schemes and the time by which the said schemes are likely to be implemented?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) Yes.

(b) A statement is laid on the tabel of the house.

STATEMENT

Statement showing schemes for providing relief to drought-affected Districts of Bhiwani & Mohindergarh.

Sr. No.	Name of the Scheme	Name of the District	Amount (in Rs.)
	GENERAL RELIEF		
1	Subsidy on Gram Seed	Bhiwani	157834
		Mohindergarh	57290
2	Subsicy on transportation of fodder	Bhiwani	1200000
		Mohindergarh	550000
3	Fodder taccavi	Bhiwani	3600000
		Mohindergarh	1500000
4	Cash taccavi	Bhiwani	1800000
		Mohindergarh	1800000

5	Contingencies		Bhiwani	25000
			Mohindergarh	25000
	RELIEF WORKS			
6		Construction of additional minors on:-	Bhiwani	12500000
	(i)	Indira Gandhi Canal		
	(ii)	Birendra Naryan Chakravaty Canal Project		
	(iii)	Jui Canal Project		
7		Jawahar Lal Nehru Canal System	Mohindergarh	4000000
8		Bunds	Mohindergarh	1750000
9		Roads	Bhiwani	2800000
			Mohindergarh	1900000
10		Water Courses	Bhiwani	1110000
			Mohindergarh	150000
			(including Rohtak)	
			Total amount	34925124

The above-mentioned schemes are likely to be implemented by the 31st March, 1975.

राव दलीप सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि स्टेटमेंट में भिवानी में सीड क लिए 1 लाख 57 हजार और महेन्द्रगढ़ के लिए सिर्फ 57000 रूपया, भिवानी में सबसिडी आन ट्रांसपोरटेशन आफ फोडर के लिए 12 लाख रूपया, महेन्द्रगढ़ के लिए पांच लाख रूपया, फोडर तकावी में भिवानी के लिए 36 लाख रूपया और महेन्द्रगढ़ के लिए 15 लाख रूपया रखा है। इस फर्क का क्या कारण है?

Pandit Chiranji Lal Sharma: Mr. Speaker, this allocation was made on the basis of information that we collected from the Collector of each District and after taking into consideration the requirements also.

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि भिवानी डिस्ट्रिक्ट के लिए जो रूपए की ऐलोकेशन की है उसमें से कितना रूपया खर्च हो चुका है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, कई काम चल रहे है, सड़कों का काम चल रहा है, फोडर का काम है, तकावी का काम है, सीड तकावी का कमा है। कितना किस काम पर खच्र हुआ है यह इन्फरमेशन इस वक्त तो मेरे पास नहीं है। अगर आनरेबल मैम्बर अलग से नोटिस दें तो बताई जा सकती है।

राव दलीप सिंह: स्टेटमेंट में नेहरू कैनाल सिस्टम पर 40 लाख रूपया खर्च होना बताया गया है लेकिन गवर्नर ऐड्रैस में बताया गया था कि डेढ़ करोड़ रूपया खर्च करेंगे। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह फर्क क्यों है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, यह जवाहर लाल नेहरू कैनाल प्रोजैक्ट बहुत बड़ा प्रोजैक्ट है। फिलहाल इरीगेशन प्रोजैक्टस के अन्दर फैमिन रिलीफ फार ड्राउट अफेक्टिड एरियाज के लिए अढ़ाई करोड़ रूपया इयरमार्क किया है। वैसे नेहरू कैनाल प्रोजैक्ट तीस करोड़ रूपए से भी ज्यादा की स्कीम है। फैमिन के दौरान अढ़ाई करोड़ रूपया खर्च किया है, to give relief to the drought affected areas.

श्री के.एन.गुलाटी: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि ड्राउट अफेक्टिड एरियाज के लोगों को रिलीफ देने के अलावा जो पावर क्राइसिज है जिसके कारण मजदूरों के वेजिज पर फर्क पड़ा है तो क्या मजदूरों को भी रिलीफ देने की कोई स्कीम है?

Pandit Chiranji Lal Sharma: This suplementary does not arise out of this question.

मलिक सतराम दास बतरा: जो ड्राउट अफैक्टिड जिले हैं और उनमें लोगों को तकावी के रूप में फोडर तकसीम होना था। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि यह फोडर के

डिपो कहां–कहां हैं और कौन–कौन से जिले बाकी हैं जहां फोडर डिपो खुलने हैं?

Pandit Chiranji Lal Sharma: We have placed the grant at the disposal of the Deputy Commissioner in each District. They have made their own internal arrangements in each District.

श्री अमर सिंह: फैमिन रिलीफ के लिए जो पैसे की ऐलोकेशन हुई है वह बहुत कम है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि इस पैसे को और अधिक करने की कोई प्रोपोजल है?

Pandit Chiranji Lal Sharma: It was after a thoughtful consideration that Rs. 5 crores wer eearmarked for relief works upto 31st March, 1975. If the Government feels it necessary even after this period, Government will consider it.

चौ. मनफूल सिंह: सीरियल नम्बर 10 पर महेन्द्रगढ़ इन्कलूडिंग रोहतक के लिए एक लाख पचार हजार रूपया रखा है। क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि रोहतक के लिए सैपरेट कितना है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: इसके लिये हमारे पास फिगर्ज हैं। महेन्द्रगढ और रोहतक के लिये एक लाख पचार हजार दिया हुआ है। इसके लिये सैपरेट नोटिस दें तो हम अलग–अलग भी बता देंगे।

राव बंसी सिंह: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि फोडर किस रेटस पर खरीदा जाता है और किसानों को किस रेटस पर दिया जा रहा है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, जिस रेट पर हम फौडर खरीदते हैं उसमें ट्रान्सपोर्ट चार्जिज वगैरह मिलाकर, 19 या 21 रूपये क्विंटल के करीब पड़ता है और उसी हिसाब से हम किसान की दे रहे हैं।

राव दलीप सिंह: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने का कश्ट करेंगे कि हमारे यहां महेन्द्रगढ़ में भी एस.एफ.डी.ए. जैसी स्कीम चालू करने की सरकार की कोई योजना है?

कृशि मंत्री (चौ. भजन लाल): अध्यक्ष महोदय, इस वक्त एस.एफ.डी.ए. स्कीम तीन जिलों में चालू है। एक अम्बाला, दूसरा भिवानी और तीसरा गुड़गावं में।

चौ. पीर चन्द: अध्यक्ष महोदय, हिसार का सारा इलाका कहत की लपेट में आ गया है। वहां पर मजदूर बहुत दुःखी है। क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि सरकार ऐसे इलाकों में भी लोगों को रिलीफ देने का विचार रखती है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: स्पीकर साहब, डिस्ट्रिक्ट हिसार में जो 40 मील का ऐसा एरिया है, वहां पर रिलिफ का काम शुरू है।

राव बंसी सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताएंगे कि जो ड्राउट अफैक्टिड एरियाज हैं उनमें एस.डी.एफ.ए. वगैरह की कोई स्कीम लागू करने की सरकार के कोई योजना विचाराधीन है?

चौ. भजन लाल: अभी मैंने बताया था कि इस वक्त यह स्कीम अम्बाला, भिवानी और गुडगांव केवल तीन जिलों में चल रही है और जिलों में चालू करने के लिए भारत सरकार से इस स्कीम की मन्जूरी लेनी होती है। अब हम यह लिखकर भेजेंगे कि ड्राउट अफैक्टिड एरियाज में भी इन स्कीमज को चालू किया जाए। लेकिन जब तक उनकी मन्जूरी नहीं मिल जाती तब तक हम कोई निर्णय नहीं ले सकते।

चौ. दल सिंह: कया मंत्री महोदय यह बताने का कश्ट करेंगे कि जो ड्राउट अफैक्टिड एरियाज हैं उन में क्या–क्या रियायतें दी जाती हैं और कितनी सबसिडी दी जाती है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो इस क्वैश्यन से इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन मैं फिर भी बता देता हूं कि वहां पर 25 से 30 परसैन्ट तक सबसिडी देते हैं।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय यह बताने की कृपा करेंगे कि किन–किन रोडज पर काम शुरू हो गया है और कौन–कौन से वाटर कोर्सिज पर यह काम हो रहा है?

पंडित चिरंजी लाल शर्मा: अध्यक्ष महोदय, जहां–जहां रोडज इनकम्पलीट थीं, मैटीरियल वगैरह इधर–उधर पड़ा हुआ था,

उन रोडज को कन्सौलीडेट कर दिया गया है and it is very difficult to just tell off hand.

चौ. पीर चन्द: जैसा कि अभी मिनिस्टर साहब ने अपने जवाब में बताया कि 40 मील के एरिया के अन्दर रिलीफ का काम शुरू है तो क्या वे बताएंगे कि इस एरिया में कौन–कौन से गांव कहत की लपेट में आए हैं?

Mr. Speaker: This question does not arise.

Privately-run and Government Schools in Ambala District

***1101. Sh. Jagjit Singh Tikka**: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) the total number of privately-run and Government High and Higher Secondary Schools and Middle Schools in the Ambala District, Tehsil-wise, separately as on 31st October, 1974 mentioning the names of places where these are located; and

(b) whether the buildings of all the Government Schools have been taken over by the P.W.D. Department for maintenance, if not, the names of Schools whose buildings have not been taken over with the reasons therefor and the date by which these are likely to be taken over.

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीमती प्रसन्नी देवी):

(ए) विवर्णिकाएं 1 से 5 सदन की टेबल पर प्रस्तुत हैं।

(बी) नहीं। विवरणिका V1 जिसमें ऐसे स्कूलों के नाम दिये हैं जिनके भवन अभी नहीं लिए गये, सदन की टेबल पर प्रस्तुत है। स्कूल भवनों को अभी तक लोक निर्माण विभाग के रिकार्ड पर न लाए जाने का कारण आवश्यक औपचारिकताओं का पूरा न होना है। इस सम्बन्ध में कोई निश्चित तिथि नहीं दी जा सकती।

विवरणिका I

अम्बाला जिले के तहसीलवार अलग–अलग सरकारी एवं गैर–सरकारी उच्च, उच्चतर माध्यमिक तथा माध्यमिक विद्यालयों की 31.10.74 की कुल संख्या इस प्रकार है:–

	कालका		अम्बाला		नारायणगढ़		जगाधरी		कुल जिला अम्बाल		कुल
	सरकारी	गैर–सरकारी	सरकारी	गैर–सरकारी	सरकारी	गैर–सरकारी	सरकारी	गैर–सरकारी	सरकारी	गैर–सरकारी	
उच्चतर माध्यमिक विद्यायल	1	2	3		2		2	4	8	6	14
उच्च विद्यायल	5	3	26	32	20	3	22	19	73	57	130
माध्यमिक	2	3	23	5	25		16		66	8	74

विद्यायल											
कुल	8	8	52	37	47	3	40	23	147	71	218

विवरणिका I

विद्यालयों की सूची (सरकारी और गैर–सरकारी)

तहसील कालका

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यायल	
1	रा:उ:मा:वि: कालका।
राजकीय उच्च विद्यालय	
1	रा:उ:मा: पिंजौर।
2	रा:उ:वि: नानकपुर।
3	रा:उ:वि: वसोलान।
4	रा:उ:वि: राजीपुर झज्जरा।
5	रा:उ:वि: मल्लाह।
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	
1	रा:मा:वि: वार–गोदाम
2	रा:मा:वि: करनपुर

गैर सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	
1	हिन्दू कन्या उःमाःविः कालका
2	आर्य कन्या उःमाःविः कालका
उच्च विद्यायल	
1	एसःडीः कालका
2	जैनेन्द्र गुरूकुल पंचकुला
3	सिक्ख कन्या उःविः कालका
	माध्यमि विद्यालय
1	साकेत माःविः चंडी मन्दिर
2	एचःएमःटीः पिंजौर
3	भूपेन्दरा सिमेन्ट माःविः सूरजपुर मलाह

विवरणिका I

विद्यालयों की सूची (सरकारी और गैर–सरकारी)

तहसील अम्बाला

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यायल	
1	राःउःमाःविः बेहटा
2	राःउःमाःविः केसरी
3	राःउःमाःविः अम्बाला शहर
राजकीय उच्च विद्यायल	
1	राःउःविः बलदेव नगर अम्बाला शहर
2	राःउःविः देव समाज रोड अम्बाला शहर
3	राःउःमाःविःएमःटीः अम्बाला शहर
4	राःउःविः वल्लाना
5	राःउःविः वोह
6	राःउःविः वकनौर
7	राःउःविः बराड़ा
8	राःउःविः दुराना
9	राःउःविः धीन
10	राःउःविः अधोया

11	राःउःविः जनसूई
12	राःउःविः मुल्लान
13	राःउःविः नागल
14	राःउःविः नूरपुर
15	राःउःविः नन्योला
16	राःउःविः मोहरी भानोखेड़ी
17	राःउःविः पुजखेड़ा
18	राःउःविः धन्नारा
19	राःउःविः तन्दवाल
20	राःउःविः थामपुर
21	राःउःविः उगड़ा बाड़ा
22	राःउःविः उगाला
23	राःउःविः जफरपुर
24	राःउःविः बेहटा
25	राःउःविः बेहटा

26	रा:उ:वि: मुलाना (कन्या)
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	
1	रा:मा:वि: छपड़ा
2	रा:मा:वि: दुखेड़ी
3	रा:मा:वि: दानीपुर
4	रा:मा:वि: गोकलगढ़
5	रा:मा:वि: होली
6	रा:मा:वि: जलबेड़ा
7	रा:मा:वि: कालपी
8	रा:मा:वि: खुडा
9	रा:मा:वि: शहपुर
10	रा:मा:वि: सोंहटा
11	रा:मा:वि: सपेरा
12	रा:मा:वि: सामलहरी
13	रा:मा:वि: समबहलका

14	रा:मा:वि: सुलतानपुर
15	रा:मा:वि: टांडला
16	रा:मा:वि: थरवा
17	रा:मा:वि: नेहरादीन
18	रा:मा:वि: बबयाल (कन्या)
19	रा: कन्या मा: वि: पंजोखेड़ा
20	रा: कन्या मा: वि: राजोखेड़ी
21	रा: कन्या मा: वि: साहा
22	रा: कन्या मा: वि: सहपुर
23	रा: कन्या मा: वि: जलबेड़ा
गैर–सरकारी उच्च विद्यालय	
1	एस.डी. अम्बाला कैट
2	ए.एस. अम्बाला शहर
3	जी.आर.एस.डी अम्बाला शहर
4	खालसा अम्बाला शहर

5	एस.ए. जैन अम्बाला शहर
6	डी.ए.वी. अम्बाला छावनी
7	एस.डी. (चाकवाल) तोपखाना अम्बाला छावनी
8	खालसा अम्बाला छावनी
9	बी.डी. अम्बाला छावनी
10	सी.बी. अम्बाला छावनी
11	सी.आर दास बवयाल
12	आर्य मुल्लाना
13	एन.डी.एस.डी. और उ.वि.सेगती
14	एस.डी.उ.वि. बराडा
15	सोहन लाल कन्या, अम्बाला शहर
16	आई.सी.पी.ए.के. कन्या, अम्बाला शहर
17	देव समाज कन्या, अम्बाला शहर
18	पी.के.आर. जैन कन्या, अम्बाला शहर
19	जैराम दास आर्य कन्या, अम्बाला शहर

20	एल.एस.एस.डी. कन्या, अम्बाला शहर
21	एस.बी.एन. कन्या, अम्बाला शहर
22	आर्य कन्या बी.सी. बाजार, अम्बाला छावनी
23	हरगोलान कन्या, अम्बाला छावनी
24	सिक्ख कन्या, अम्बाला छावनी
25	सेवा समिति कन्या, अम्बाला छावनी
26	एल.डी. आर्य कन्या अम्बाला छावनी
27	एस.वी. कन्या, अम्बाला छावनी
28	एस.वी. कन्या टोपखाना, अम्बाला छावनी
29	एम.एल. आर्य कन्या, अम्बाला छावनी
30	जैन कन्या, अम्बाला छावनी
31	हर गोविन्द साहिब, अम्बाला शहर
32	कलगीधर कन्या, अम्बाला शहर
माध्यमिक विद्यालय	

1	पब्लिक कन्या मा.वि. बराड़ा
2	माडर्न मिडल बराड़ा
3	यूनाईटिड चर्च अम्बाला शहर
4	एस.ए.जैन मोडल अम्बाला शहर
5	पंचायत मनका मनकी

विवरणिका IV

तहसील नारायणगढ़

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यायल	
1	राःउःमाःविः नारायणगढ़
2	राःउःमाःविः शाहपुर नूरहद
राजकीय उच्च विद्यायल	
1	राःउःविः वदहोली
2	राःउःविः धरेरी कलां

3	राःउःविः बरवाला
4	राःउःविः वनन्दी
5	राःउःविः शवाना
6	राःउःविः जाटवार
7	राःउःविः खटोली
8	राःउःविः कोरवा खुर्द
9	राःउःविः मन्दना
10	राःउःविः मोरनी हिल्स
11	राःउःविः पथरेरी
12	राःउःविः राटैवाली
13	राःउःविः रायपुर रानी
14	राःउःविः रामगढ़
15	राःउःविः सरमान
16	राःउःविः सलेहपुर
17	राःउःविः नारायणगढ़ (कन्या)

18	राःउःविः रायपुर रानी (कन्या)
19	राःउःविः शहजादवाद (कन्या)
20	राःजे.बी.टी. नारायणगढ़
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	
1	रा.मा.वि. अकबरपुर
2	रा.मा.वि. भारोग
3	रा.मा.वि. भूरेवाला
4	रा.मा.वि. फतेहगढ़
5	रा.मा.वि. फिरोजपुर
6	रा.मा.वि. कोटाह
7	रा.मा.वि. गनेशपुर
8	रा.मा.वि. गदोली
9	रा.मा.वि. हंभोला
10	रा.मा.वि. कोट
11	रा.मा.वि. कोटला

12	रा.मा.वि. कक्कर माजरा
13	रा.मा.वि. कुराली
14	रा.मा.वि. कथेमा
15	रा.मा.वि. लाहा
16	रा.मा.वि. लहरपुर
17	रा.मा.वि. नामला
18	रा.मा.वि. रायवाली
19	रा.मा.वि. शाहजादपुर
20	रा.मा.वि. पंजालस
21	रा.मा.वि. टिकरहोली
22	रा.मा.वि. भरहल
23	रा.मा.वि. हमीदपुर
24	रा.मा.वि. बरवाला (कन्या)
25	रा.मा.वि. रामगढ़ (कन्या)
अराजकीय विद्यालय	

1	आदर्श कन्या जैन उच्च विद्यालय सदोहरा
2	हिन्दू ए.एस.एस. उच्च विद्यालय सदोहरा
3	एम.आर.एस.डी. उच्च विद्यालय शहजादपुर

विवरणिका v

तहसील जगाधरी

राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यायल	
1	राःउःमाःविः जगाधरी
2	राःकन्याःउःमाःविः यमुनानगर
राजकीय उच्च विद्यायल	
1	राःउःविः तालाकौर
2	राःउःविः मंडौली

3	रा:उ:वि: मेहलावाली
4	रा:उ:वि: कैम्प यमुनानगर
5	रा:उ:वि: खादरी
6	रा:उ:वि: दामला
7	रा:उ:वि: हरनौल
8	रा:उ:वि: नागल
9	रा:उ:वि: जगाधरी वर्कशाप
10	रा:उ:वि: शावापुर
11	रा:उ:वि: मुस्तफाबाद
12	रा:उ:वि: सरन
13	रा:उ:वि: लेदी
14	रा:उ:वि: छछरौली
15	रा:उ:वि: खिजराबाद (पूर्व)
16	रा:उ:वि: कोट कलसियां
17	रा:उ:वि: खांरवां

18	राःउःविः विलासपुर
19	राःउःविः कालावर
20	राःउःविः मुसीनवाल
21	राःउःविः छछरौली (कन्या)
22	राःउःविः विलासपुर (कन्या)
राजकीय माध्यमिक विद्यालय	
1	रा.मा.वि. हैबतपुर
2	रा.मा.वि. फतेहगढ़ तुम्बी
3	रा.मा.वि. फतेहगढ़
4	रा.मा.वि. जहपर
5	रा.मा.वि. कलानौर
6	रा.मा.वि. कपूरीकलां
7	रा.मा.वि. कुंजलकलां
8	रा.मा.वि. कुंजलजटां
9	रा.मा.वि. मुगलवाली

10	रा.मा.वि. मलीवपुर बंगर
11	रा.मा.वि. सयालवा
12	रा.मा.वि. परसुरा
13	रा.मा.वि. भंगगोल
14	रा.मा.वि. चुहारपुर कलां (कन्या)
15	रा.मा.वि. देवधर (कन्या)
16	रा.मा.वि. दादुपुर (कन्या)
गैर सरकारी विद्यालय	
उच्च माध्यमिक विद्यालय	
1	एस.डी.उ.मा.वि. जगाधरी
2	एम.एल.एम.उ.मा.वि. यमुनानगर
3	एस.जी.एन.के.उ.मा.वि. यमुनानगर
4	डी.ए.वि.उ.मा.वि. यमुनानगर
उच्च विद्यालय	
1	जनता मुस्तफाबाद

2	डी.ए.वि मुस्तफाबाद
3	जी.आर. आर्य बराड़ा
4	गुरू नानक खालसा जगाधरी वर्कशाप
5	हिन्दु कन्या जगाधरी
6	डी.ए.वी.उ.वि. जगाधरी वर्कशाप
7	गुरू नानक खालसा कन्या सन्तपुरा यमुनानगर
8	हिन्दु कन्या बुड़िया
9	गुरूकुल कन्या पाठशाला बुड़िया
10	डी.ए.बी. कन्या उ.वी. यमुनागर
11	एस.जी.एन. खालसा यमुनानगर
12	डी.डी. अग्रवाल जगाधरी
13	दयानन्द कन्या एम टी यनुनानगर
14	सरस्वती विद्या मन्दिर जगाधरी
15	विकेकानन्द उ.वि. यमुनानगर
16	विश्णु कल्याण उ.वि.कुराहड़ा साधेपुर

17	आर्य मॉडल शिक्षा पाठशाला यमुनानगर
18	डी.ए.बी. मिडल स्कूल आई.वी.आई. यमुनानगर
19	हरिनाम गुरांनवति मिडल स्कूल यमुनानगर

विवरणिका VI

उन विद्यालयों की सूची जिन के भवन अभी तक लोक निर्माण विभाग के रिकार्ड पर नहीं आये हैं।

तहसील अम्बाला

1	राजकीय उच्च विद्यालय नुरपुर
2	राःउःविः पंजोखरा
3	राःउःविः दुराना
4	राःउःविः जनसूई
5	राःउःविः बरारा
6	राःउःविः उगारावारा

7	रा:उ:वि: नुगल (हिसार रोड)
8	रा:उ:वि: धानुरा
9	रा:उ:वि: बुलाला
10	रा:उ:वि: बाकनौर
11	रा:उ:वि: उगाला
12	रा:उ:वि: वोह
13	रा:उ:वि: शाहपुर
14	रा:उ:वि: शाहपुर (कन्या)
15	रा:उ:वि: जलवेहरा
16	रा:उ:वि: सोंता
17	रा:उ:वि: धानीपुर
18	रा:उ:वि: छपरा
19	रा:उ:वि: कालपी
20	रा:उ:वि: जुन्डला
21	रा:उ:वि: सपेरा

22	रा:उ:वि: नेहरादेहरा
23	रा:उ:वि: पसीयाला
24	रा:उ:वि: मलखी
25	रा:उ:वि: सुल्तानपुर
26	रा:उ:वि: गोकलगढ़
27	रा:उ:वि: दुखेड़ी
28	रा:उ:वि: खुडा
29	रा:उ:वि: शाहा
30	रा:उ:वि: ववयाल
तहसील कालका	
1	रा.मा.वि. बसोलाम
2	रा.मा.वि. मल्लाह
3	रा.मा.वि. नानकपुर
4	रा.मा.वि. राज्येपुर
5	रा.मा.वि. वारगोदाम

6	रा.मा.वि. कालका
तहसील नारायणगढ़	
1	राजकीय उच्च विद्यालय वानोदी
2	राजकीय उच्च विद्यालय सालेहपुर
3	राजकीय उच्च विद्यालय रायपुर रानी (कन्या)
4	राजकीय उच्च विद्यालय मनढाना
5	राजकीय उच्च विद्यालय पथ्थरहेडी
6	राजकीय उच्च विद्यालय कुरमक खुर्द
7	राजकीय उच्च विद्यालय धनाना
8	राजकीय उच्च विद्यालय रामगढ़
9	राजकीय उच्च विद्यालय मोरनी हिल्लज
10	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोटला
11	राजकीय माध्यमिक विद्यालय फिरोजपुर
12	राजकीय माध्यमिक विद्यालय पंजलासा
13	राजकीय माध्यमिक विद्यालय भूरेवाला

14	राजकीय माध्यमिक विद्यालय भरौलरी
15	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गढी कटाहा
16	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कुराली
17	राजकीय माध्यमिक विद्यालय लहारपुर
18	राजकीय माध्यमिक विद्यालय लाहा
19	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गढ़ौली
20	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हामीदपुर
21	राजकीय माध्यमिक विद्यालय हंगोली
22	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रायेवाली
23	राजकीय माध्यमिक विद्यालय अकबरपुर
24	राजकीय माध्यमिक विद्यालय काठे माजरा
25	राजकीय माध्यमिक विद्यालय खतौली
26	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बरवाला (कन्या)
27	राजकीय माध्यमिक विद्यालय ककड़ माजरा
28	राजकीय माध्यमिक विद्यालय गनेशपुर

29	राजकीय माध्यमिक विद्यालय नागला
30	राजकीय माध्यमिक विद्यालय शाहजादपुर
31	राजकीय माध्यमिक विद्यालय टिक्कर हिल्लर्ज
32	राजकीय माध्यमिक विद्यालय भरगा
33	राजकीय माध्यमिक विद्यालय कोट
34	राजकीय माध्यमिक विद्यालय रामगढ़
तहसील जगाधरी	
1	राजकीय उच्च विद्यालय सरन
2	राजकीय उच्च विद्यालय सावापुर
3	राजकीय उच्च विद्यालय हरनौल
4	राजकीय उच्च विद्यालय कपुरी कलां
5	राजकीय उच्च विद्यालय भम्बोल
6	राजकीय उच्च विद्यालय धनौरा
7	राजकीय उच्च विद्यालय दयोधन
8	राजकीय उच्च विद्यालय फतेह पुमरी

9	राजकीय उच्च विद्यालय कलानौर
10	राजकीय उच्च विद्यालय खिजराबाद पूर्व (कन्या)

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री महोदया यह बताएंगी कि 147 स्कूलज में से जो 80 स्कूलज अभी गवर्नमैंट नेटेक–ओवर किये हैं, उनके गिर जाने का तो कोई खतरा नहीं है क्योंकि उनकी रिपेयर वगैरह किसी ने नहीं की हुई होगी? अगर बिल्डिंगे गिरने का कोई खतरा है तो क्या सरकार उनको शीघ्र ही टेक ओवर करने का विचार रखती है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: अध्यक्ष महोदय इसमें ऐसा है कि पंचायत का रेजोल्युशन आता होता है और भवन वगैरह को भी देखना होता है। मलकियत किस के नाम है ये कई ऐसी बातें हैं जिनको देखना पड़ता है। यह सारी चीजें देखने के बाद लोक निर्माण विभाग को लिखना पड़ता है तथा उसके बाद डी.पी.आई. की मन्जूरी लेकर टेक ओवर किया जाता है लेकिन जो स्कूलज पंचायतों के पास हैं, उनकी रिपेयर पंचायतें खुद करती हैं।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन हाई और मिडल स्कूलज को गवर्नमैंट ने अभी टेक ओवर नहीं किया और कानून के मुताबिक पंचाकतें

उनकी रिपेयर नहीं करवा सकती, तो इन केसिज में क्या कदम उठाये जाते है?

शिक्षा मंत्री (श्री माडू सिंह मलिक): ऐसे स्कूलों की रिपेयर पंचायतें भी करवा सकती हैं और वे स्कूल अपने फण्डज से भी रिपेयर करवा सकते हैं।

चौ. दल सिंह: क्या मिनिस्टर साहब यह बताने की कृपा करेंगे कि अगर जिला जींद में कोई प्राईवेट स्कूल ऐसा हो, जो ठीक तरह से रन करता हो और इस सिलसिले में गवर्नमैंट की सारी शतें भी पूरा करता हो तो ऐसे स्कूलज को गवर्नमैंट टेक ओवर करने के लिए तैयार है?

श्री माडू सिंह मलिक: नहीं जी।

चौ. फूलचन्द (मुलाना): क्या मिनिस्टर साहब यह बताएंगे कि जिला अम्बाला के अन्दर कुछ ऐसे मिडल स्कूलज हैं, जिनको पंचायतें चला रही हैं और उन्हौंने यह लिखकर भी दिया हुआ है कि हम इस स्कूल को चलाने की हैसियत में नहीं हैं तो क्या ऐसे स्कूलज को सरकार टेक ओवर करने के लिए तैयार है?

श्री माडू सिंह मलिक: इस वक्त सरकार का ऐसा कोई विचार नहीं है।

श्री गिरीश चन्द जोशी: क्या मिनिस्टर साहब यह फमाएंगे कि जो स्कूलज गवर्नमैंट ने पंचायतों से ले लिये हैं जैसा

कि एक स्कूल मेरे हल्के नांगल खंजूरी में है, और जिसकी अभी तक कोई मुरम्मत वगैरह नहीं हो पाई है, उसकी मुरम्मत करवाने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ताकि वहां पर बच्चे पढ़ सकें।

श्रीमती प्रसन्नी देवी: मैंने बताया कि जिन स्कूलज को पी.डब्ल्यू.डी. वाले ले चुके हैं उनके लिये वह खुद जिम्मेदार हैं। जो अभी रहते हैं उनकी देखभाल पंचायतें करती हैं। इसके इलावा कोई और केस मैम्बर साहेबान के नोटिस में हो तो मेरे नोटिस में लाएं, हम अवश्य कार्यवाही करेंगे।

Street Light onthe Mathura Road

***1092. Sh. K.N. Gulati**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the total amount deposited with H.S.E.B. by the Faridabad Complex for the street light on the Mathura Road from one Complex area to the other Complex area; and

(b) the time by which the work for the said purpose is likely to be started?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a) Rs. 1056394/-

(b) At present, there is an acute shortage of material. As soon as material becomes available the work will be started.

श्री के. एन. गुलाटी: क्या मिनिस्टर साहब यह बतलाने की कृपा करेंगे की मथुरा रोड की स्ट्रीट लाईट के लिए जल्द से जल्द कहीं न कहीं से मैटीरियल वगैरह का प्रबन्ध करके काम शुरू करवाया जाएगा?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: पोल्ज का डिवीजन सी. पी.डब्ल्यू.डी. वालों के पास होता है। इसका फैसला हो जाने के बाद ही हम मैटीरियल वगैरह लाएंगे और तभी काम शुरू करवाएंगे।

श्री के. एन. गुलाटी: क्या मिनिस्टर साहब बताएंगे कि कम्पलैक्स द्वारा पैसा जमा करवा दिया गया तो फिर देरी किस बात की है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, यह काम तो गवर्नमैंट आफ इंडिया का है।

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताने का कश्ट करेंगे कि यह रकम कब जमा करवाई गई?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: अप्रैल, 1974 में।

Buses Plying in the State

***1107. Sh. Girish Chander Joshi**: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) the total number of buses plying in the State at present together with their models and ages;

(b) whether the Government is considering to increase the number of buses, if so, their number;

(c) if reply to part (b) above be in the affirmative, the time by which the increase would be effected;

(d) the facilities, if any, being provided to the passengers travelling in the buses of the Haryana Roadways; and

(e) the facilities, if any, being provided by the Governmet to the workers of the Haryana Roadways?

शिक्षा एवं परिवहन राज्य मंत्री (श्रीती प्रसन्नी देवी):

(क) 1640 माडल	माडल अनुसार विवरण इस प्रकार से है बसों की संख्या
1966	14

1967	77
1968	145
1969	178
1970	288
1971	233
1972	239
1973	296
1974	170
कुल	1640

बसों की आयु अनुसार	बसों की संख्या
एक वर्श से कम	201
एक वर्श से अधिक दो वर्श से कम	314
दो वर्श से अधिक तीन वर्श से	200

कम	
तीन वर्श से अधिक चार वर्श से कम	228
चार वर्श से अधिक पांच वर्श से कम	220
पांच वर्श से अधिक 6 वर्श से कम	229
6 वर्श से अधिक 7 वर्श से कम	122
7 वर्श से अधिक 8 वर्श से कम	45
8 वर्श से अधिक	11
कुल	1640

(ख) जी हां। लगभग 150 गाड़ियां।

(ग) चालू वित्तीय वर्श के शेश महीनों में।

(घ) यात्रियों को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की जाती है:–

1. लगभग तमाम नगरों में हरियाणा परिवहन के तमाम सुविधा सहित बस अड्डे हैं।

2. यात्रियों को आरामदायक प्रतीक्षालय उपलब्ध हैं।

3. जहां पर बस अड्डे नहीं बनाये जा सकते वहां पर बस क्यू शैल्टर और अस्थाई बस अड्डे उपलब्ध किये जाते हैं।

(ड) हरियाणा परिवजन के वर्करज को निम्नलिखित सुविधाएं उपलब्ध की जाती है:–

1. बोनस के बदले अनुग्रह पूर्वक अनुदान (एक्सग्रेशिया)।

2. वर्श में दो परिवार पास।

3. गर्म तथा ठण्डी वर्दी जूतों सहित।

4. वर्दी धोने का भत्ता।

5. ओवर–टाईम भत्ता।

6. वरकमैन कम्पनसेशन एक्ट के तहत कम्पनसेशन (मुआवजा)।

7. पैमेन्ट आफ ग्रेचूएटी एक्ट के अधीन ग्रेचूएटी।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एक बस की एवरेज लाइफ कितनी है?

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): टाटा की बस की 6 साल और लेलैंड की 8 साल।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि क्या वर्कर्ज को प्रोवीडैंट फंड की सुविधा भी दी जाती है?

कर्नल महा सिंह: प्रोवीडैंट फंड सबको मिलता है इसलिये इसको छोड़ दिया गया था।

श्री गुलाब सिंह जैन: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि पिछले साल मैं ओवर टाईम का कितना एमाउंट दिया गया?

कर्नल महा सिंह: 1973–74 में 25 लाख 98 हजार रूपये ओवर टाइम अलाउंस की पेमैंट हुई।

चौ. दल सिंह: जैसे अभी मंत्री महोदय ने अपने जवाब में बताया कि 11 बसें ऐसी हैं जो 8 से 9 साल तक की पुरानी

हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उनमैं से कितनी लेलैंड हैं और कितना टाटा हैं?

कर्नल महा सिंह: ये सबकी सब बसें लेलैंड हैं।

मलिक सतराम दास बतरा: जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया कि इस साल में 150 नई बसैं और एड हो रही हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस साल रिप्लेस कितनी होने जा रही हैं?

कर्नल महा सिंह: यह सवाल बसों के एड करने का है, रिप्लेस करने का नहीं। इस वक्त तक 69 बसें हमारे पास आ चुकी हैं बाकी मार्च तक आ जाएंगी।

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदया बतायेंगी कि वर्कर्ज को जो वेजिज एक्ट के तहत सहूलियत दी जाती हैं उनके अलावा कोई और स्पैशल सहूलियत भी दी जाती है?

श्रीमती प्रसन्नी देवी: उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज रह ही नहीं जाती।

श्री गुलाब सिंह जैन: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 1973–74 में गवर्नमैंट ने वर्कर्ज को फैसिलिटी देने के लिये कितना खर्च किया?

कर्नल महा सिंह: मैंने ओवर टाइम का बताया कि 25 लाख 98 हजार रूपया था, एक्स ग्रेशिया पर 27 लाख 26 हजार और जो एम.पी.आर.एफ. है उस पर 2 लाख 89 हजार। इसके

अलावा यूनिफार्म वगैरह का एक वर्कर को करीब करीबा 250 रूपये सलाना दिया जाता है।

चौ. दल सिंह: जैसा मिनिस्टर साहब ने बताय कि यूनिफार्म के लिये जो पैसा दिया जाता है तो कया ड्राइवर्ज वगैरह यूनिुार्म को रैगुलरली पहनते हैं या नहीं?

कर्नल महा सिंह: पहले इसमें थोड़ी सी कमी थी लेकिन आजकल इस पर काफी जोर दिया जा रहा है और सबको मजबूर किया जा रहा है कि वे ड्रैस पहनें।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 1972–73 ओर 1973–74 में मैडिकल फैसिलिटी पर कितना कितना खर्च किया गया?

कर्नल महा सिंह: मैडिकल फेसेलिटी के आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है अतः इसके लिये अलग से नोटिस दें।

चौ. राम लाल वधवा: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि 1973–74 का टोटल रैवेन्यू कितना था और फैसिलिटी में कितने परसैट दिया गया?

कर्नल महा सिंह: इस सवाल से प्रश्न पैदा नही होता इसलिये अलग से नोटिस दें तो बता देंगे।

चौ. पीर चन्द: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जो क्लास तीन और चार के मुलाजिम हैं क्या उनको रिटायर होने पर पैनशन देने का विचार है?

कर्नल महा सिंह: जिन मुलाजिमों को प्रोविडैंट फंड दिया जाता है उनको पैनशन नहीं दी जाती।

राव बंसी सिंह: जैसे मंत्री महोदय ने बताया कि 150 चेसिज खरीदी गई तो क्या वे बताने का कश्ट करेंगे कि वे कौन न महीने में खरीदी गई?

कर्नल महा सिंह: ये चेसिज अलग अलग बेचिज में आए हैं एक साथ नहीं आए। अभी बाडीज बनवाई जा रहीं हैं जोकि मार्च तक बन जाएंगी।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि वर्कर्ज ई.एस.आई. स्कीम से कवर्ड हैं?

कर्नल महा सिंह: जो वर्कशाप में काम करते हैं वे ई. एस.आई. स्कीम से कवर्ड हैं।

चौ. मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदय के नोटिस में यह चीज है कि झज्जर सब–डिवीजन की बसों की कंडीशन बहुत खराब है, उनके शीशे टूटे हुए हैं। क्या उनको रिप्लेस करने का प्रबन्ध करवाएंगे?

कर्नल महा सिंह: जहां–जहां बसे खराब हैं उनको आहिस्ता आहिस्सा तबदील किया जाएगा झज्जर का भी ख्याल रखा जाएगा।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि बसों की बाडीज ट्रांसपोर्ट विभाग खुद बनाता है या प्राइवेट कन्ट्रैक्टरों से बनवाता है? अगर प्राइवेट से बनवाता है तो फी बाडी कितना खर्च आता है?

कर्नल महा सिंह: बाडीज हरियाणा रोडवेज की तरफ से नहीं बनाई जा रही हैं। प्राईवेट तौर पर टैंडर इनवाइट करके बनवाई जाती हैं। हम चाहते हैं कि खुद भी बाडी बिल्डिंग का काम शुरू कर दें और जल्दी ही शुरू कर देंगे।

Sh. Gulab Singh Jain: Will the Hon. Transport Minister be pleased to state the total number of employees in the Haryana Roadways?

कर्नल महा सिंह: इस सवाल के इसका ताल्लुक नहीं है इसलिये मैं एग्जैक्ट फिग्गर नहीं बता सकता है। लेकिन फिर भी अन्दाजन साढ़े आठ हजार से 9 हजार तक इस वक्त रोडवेज में एम्पलाईज हैं।

चौ. शिव राम वर्मा: जैसे कि मंत्री महोदय ने यात्रियों को सुविधा देने की बात कही है तो जो यात्री रास्ते में सड़कों पर खड़े रहते हैं क्या उनको भी कोई सुविधा दी जाएगी?

कर्नल महा सिंह: हम जगह जगह छोटे छोटे शैड बना रहे हैं और कोशिश यह की जा रही है कि यात्री बसें खड़ी न होने के कारण रास्ते में न खड़े रहे और उनको हमारी बसें टाइम पर उठाएं।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि एक बस की बाडी बनाने पर कितना खर्च आता है?

कर्नल महा सिंह: पहले हम कम्पोजिट बाडी बनवाते थे उस पर कम खर्च आता था अब नई मैटल बाडी बनवा रहे हैं उसके ऊपर सीटों की कैपेसिटी के मुताबिक खर्च आता है। 52 सीटर पर और 62 सीटर पर 37 हजार से लेकर 46 हजार तक की लागत आती है।

चौ. अमीर चन्द कक्कड़: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जब नए इंजन या स्पेयर पार्टस वगैरह आते हैं तो क्या उन पर हरियाणा की मोहर लगाई जाती है ताकि वे बाजार में चोरी में न बिक सके?

कर्नल महा सिंह: अभी तक तो ऐसा नहीं था लेकिन अब हमने एस.टी.सी. से ऐसा कह दिया है, अब मोहरें लगानी शुरू कर दी हैं।

श्रीमती चन्द्रावती: क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि बाड़ी बनाते वक्त यह ध्यान रखा जाता है कि यात्रियों के लिये सीटें कमफरटेबल हों?

कर्नल महा सिंह: यह पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है।

मलिक सतराम दास बतरा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि आपके जो सिलसिला वार कई ग्रुपस में चैसीज खरीद की हैं तो ऐसा करने में चैसीज की जो कीमतें बढ़ती रही हैं उससे कितना ज्यादा खर्च आया है और चैसीज के ज्यादा देर बाडी न बनने की वजह से खड़ा रहने की वजह से कितना नुक्सान हुआ है?

कर्नल महा सिंह: चैसीज का रेट बढ़ रहा था तो पहले खरीद ली गई और अंदाजन एक–एक चैसी पर 10 हजार रूपये की बचत हुई है।

श्री अमर सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि क्या यह हकीकत है कि 1972–73 में बाडी बिल्डर्ज ने रिक्वायरमैंट के मुताबिक और जो स्टैंडर्ड अप्रूव किया गया था उसके मुताबिक बाडी नहीं बनाये, उसकी तहकीकात की गई और अगर की गई तो उसका क्या नतीजा निकला?

Mr. Speaker: It is not a supplementary question, it is an independent question.

चौ. दल सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि 1973–74 में कितने रूपये के स्पेयर पार्टस खरीदे गये?

कर्नल महा सिंह: अध्यक्ष महोदय, ये स्पेयर पार्टस की कीमत के बारे में सवाल नहीं है। इसके लिये सैप्रेट नोटिस दें।

Mr. Speaker: There have been sufficient number of supplementaries on this question. Next question.

Sahibi Nadi

***1115. Ch. Ram Parshad**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state whether there is any proposal under consideration of the Governmetn to control the havoc of Sahibi Nadi during the rainy season alongwith Pawti village in Bawal Block to save the adjoining villages like Jhabwa, Vidas, Khijuri, Jharkal from floods?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha): No, Sir.

Bribe Offered To Government Servants

***1117. Ch. Mehar Chand**: Will the Minister for Home be pleased to state the action taken during the period from 1.7.1968 to 30.6.1974, against private persons who offered bride directly or indirectly to Government servants and the steps proposed to be taken to curb corruption?

State Minister for Health and Home (Smt. Sharda Rani): During the period from 1.7.1968 to 30.6.1974, 15 cases were registered against private pesons, who offered bribe directly or indirectly to Government servants. Out of them, 7 cases ended in conviction, 2 ended in acquittal and the remaining 6 cases are pending trial in court. The State authorities are vigilant and whenever such instances of corruption come to notice, prompt action under the law is taken against the offenders, so that the evil of offering bribe is curbed effectively,. Besides departmental vigilance over

officials of doubtful integrity specific complaints are enquired into by the Special Inquiry Agency. The Government has also decided that employees of doubtful integrity would neither be considered for promotion nor kept in service beyond 50 years.

चौ. मेहर चन्द: क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि जो स्टैप्स उन्होंने बतलाये हैं उनके अलावा भी कोई और इफैक्टिव स्टैप्स लेने का विचार है जिससे कुरप्शन पूरी तरह ही खत्म हो या कम से कम हो और कम से कम जो प्राईवेट पर्सनज हैं उस बारे में कोई ऐसा कानून बनाने की तजवीज हे कि उनको रोका जाये कि वह रिश्वत न दे सकें?

श्रीमती शारदा रानी: अध्यक्ष महोदया, अगर चौ. मेहर चंद जी कोई इस प्रकार का कानून बनाने की सजैशन देंगे तो शायद सारा हाउस ही उसको कन्सिडर कर लेगा। (हंसी)

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदया बतायेंगे कि जो केसिज पकड़े हैं कुरप्शन के उनमें अमांउट कितना इनवाल्वड है और वे कौन कौन से अफसर थे?

श्रीमती शारदा रानी: यह केसिज प्राइवेट आदमियों द्वारा रिश्वत दिए जाने के बारे में हैं अफसरों के बारे में नहीं हैं। जहां तक यह बात है कि अमांउट कितना इनवाल्वड है तो वह हर एक केस का अलग अलग है लेकिन 10 रूपये से लेकर 8 हजार रूपये तक है। अगर अलेहिदा अलेहिदा केसिज के बारे में जानना चाहते हैं तो मैं बता सकती हूं वह फिगर्ज भी मेरे पास हैं।

चौ. दल सिंह: क्या वजीर साहिबा बतायेंगी कि कितने डाउटफुल अफसर ऐसे थे जिनके खिलाफ आपने 1973–74 में ऐक्शन लिया?

श्रीमती शारदा रानी: यह सवाल प्राईवेट पर्सनज के बारे में है अफसरों के बारे में नहीं है। इसके लिये सैप्रेट नोटिस दें।

Operation of Haryana Roadways Buses

***1120. Sh. Behari Lal Balmiki**: Will the Minister for Development be pleased to state –

*Reply to this question has been received and Printed as appendix to this debates

(a) the daily average total number of kilometres operated by the Hayrana Roadways during the years 1972-73 and 1973-74 separately;

(b) the said daily average number of passengers carried by the said Roadways during the years 1972-73 and 1973-74, separately;

(c) the total income accrued to the Haryana Roadways during the years 1972-73 and 1973-74, separately?

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of this question which has been granted. Communication received from the Minister concerned is as follows –

"Maha Singh

D.O. No. 86-3T-75/

Transport Minister,

Haryana

January 5, 1975.

Subject: Starred Assembly Question No. 1120 regarding daily average kilometers operated by Haryana Roadways.

My dear Chaudhry Sahib,

I write to inform you that Starred Assembly Question No. 1120 to be asked by Sh. Behari Lal Balmiki, M.L.A. was received in the Transport Department on 26-12-74. in understand that his question has been fixed for answer on the 6th January, 1975. As the information asked for by the member is of factual nature. I feel that it will not possible to answer it on the 6th January, 1975. I shall therefore, feel grateful if this Question is fixed for answer on any date after the 5th February, 1975.

Yours sincerely,

Sd/-

(Maha Singh)

Sh. Sarup Singh,

Speaker,

Haryana Vidhan Sabha,

Chandigarh.

Starred Question No. 1127

As the hon. member was not present, this question was not put.

Water Flown in Augmentation Canal

***1152. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state –

(a) the total cusecs of water flown in Augmentation Canal during the years 1973-74 and 1974-75, separately; and

(b) the district-wise details of distribution of water from this canal?

State Minister for Irrigation and Power (Sardar Harmohinder Singh Chatha):

(a)	(i)	1973-74 (1st April, 73 to 31st March, 74)	529374 Cusec. days (approximate)
	(ii)	1974-75	503241 Cusec.

		(1st April, 74 to 15 Dec. 74)	days (approximate)

(b) The Augmentation Canal is a feeder channel for augmenting supplies in the existing W.J.C. System. The supplies passing through this Canal are distributed over the entire W.J.C. tract. The question of district-wise distribution of these supplies does not, therefore, arise.

चौ. राम लाल वधवा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस पानी की डिवीजनवाइज और डिस्ट्रिक्टिवाइज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जो हमारे डिवीजन होते हैं वह डिस्ट्रिक्ट–वाइज नहीं होते हैं।

सिचाई तथा बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): अध्यक्ष महोदय, मैं इसे थोड़ा सा स्पश्ट कर दूं कि इसमें डिस्ट्रिक्ट–वाइज, डिवीजन–वाइज या सर्कल–वाइज, डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल नहीं है। बात यह है कि आगमैंटेशन कैनाल का सारा पानी जमना कैनाल सिस्टम में दिया जाता है और जहां–जहां वैस्टर्न जमना कैनाल सिस्टम का पानी जाता है वहां वहां उस अलाके को फायदा इससे होता है।

श्री गुलाब सिंह जैन: क्या वजीन साहब बतायेंगे कि आगमैंटेशन कैनाल से जो पानी बढ़ा है इससे कितने हैक्टेयर लैंड और इरीगेट हुई है?

स्रदार हरमोहिन्द्र सिंह: एडीशनल इरीगेशन जो हुई वह 558000 हैक्टेयर में बढ़ी है और 10 लाख 16 हजार हैक्टेयर में इरीगेशन में इम्प्रूवमैंट हुई हैं।

चौ. दल सिंह: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि 1973–74 की बजाये 1974–75 में आबपाशी कम क्यों हुई है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह: वह मार्च तक है ओर यह दिसम्बर तक है।

चौ. राम लाल वधवा: क्या वजीर साहब बातयेंगे कि वह नहर जिस–जिस जिला में गुजरती ळै क्या उस बारे में कोई क्राईटेरिया सरकार ने बनाया है कि हर जिला को अलग–अलग से कितना–कितना पानी मिले?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: पानी की डिस्ट्रीब्यूशन जिलावार नहीं होती है, लैंडवाइज होती है।

चौ. राम लाल वधवा: कया वजीर साहब बतायेंगे कि जितनी लैंउ जिस जिला में आती है उस लैंड के अनुसार पानी दिया जाता है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: स्पीकर साहब, इसमें कई चीजें देखने वाली हैं। कुछ एरिया ऐसा होता है जहां पानी लग सकता है और कुछ ऐसा होता है जहां पानी नहीं लग सकता है जैसे कि अम्बाला में से नहर जाती है लेकिन वहां पानी नही लग सकता।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस आगमैंटेशन कैनाल में टयूबवैल्ज लगा कर पानी डाला गया है? कया उस पानी से आगे उतना फायदा हुआ है जितना कि पीछे उससे नुकसान हुआ है और किसानों के निजी नल कूपों में पानी कम हो जान की शिकायतों का क्या बना है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: हमारे पास कोई शिकायत नही आई है।

चौ. दल सिंह: वजीर साहब ने फरमाया कि अम्बाला जिला में पानी नहीं लग सकता। इसका क्या कारण है, क्यों पानी नहीं लग सकता?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: इसका कारण यह था कि इसका लैवल ऊंचा था और पानी का लैवल नीचा था। दूसरे यहां बेइन्तहा नदियां चलती हैं। वहां के लिए एक स्कीम गवर्नमैंट कन्सिडर कर रही है।

चौ. अब्दुर्रजाक खां: क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस आगमैंटेशन सिस्टम पर सालाना लागत कितनी आती है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: इसके लिये सैप्रेट नोटिस दें।

चौ. फूल चन्द (मुलाना): क्या वजीर साहब बतायेंगे कि इस आगमैंटेशन कैनाल के लिये टयूबवैल्ज लगा देने से वाटर लोगिंग से कितना एरिया बचाया गया है?

सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जो एरिया नहर के नजदीक का है वहां से वाटर लागिंग खत्म हो गई है?

श्री गुलाब सिंह जैन: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि आगमैंटेशन कैनाल से जो फर्दर इरीगेशन हुई है उससे कितनी प्रोडक्शन बढ़ी है?

स्रदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा: जितना खच्र आगमैंटेशन नहर पर आया है उतनी प्रोडक्शन पिछले साल में हो गई है।

Sugar Mills

***1166. Sh. Om Parkash Garh**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state –

(a) the dates when all the three Sugar Mills located at Yamuna nagar, Rohtak and Panipat in the State, separately, started functioning during the year 1973-74;

(b) the rate at which the sugarcane was purchased from the cane growers by these mills during the period as referred to in part (a) above;

(c) the date by which the above said three mills had been functioning during the year 1973-74, separately;

(d) the rate at which they purchased the sugarcane from the growers at the time of closing the Mills; and

(e) whether any bonus in cash or kind was given to the cane growers?

कृशि मंत्री (चौ. भजन लाल):

(ए)	विवरण विधान सभा पटल पर रखा जाता है।
(बी)	
(सी)	
(डी)	
(ई)	

विवरणिका

	मिलों का नाम	(क) वर्श 1973–74 में कार्य आरम्भ करते की तिथि	(ख) गन्ने का भाव जो प्रतिदिन खरीदा गया (रूपयों में)	(ग) चीनी मिल की बन्द होने की तिथि	(घ) मिल के बन्द होने के समय गन्ना खरीदने का भाव प्रति क्विन्टल (रूपयों में)		(ड) बोनस जो नकद या जिनसे के रूप में गन्ना उत्पादकों को दिया गया
1	दी सरस्वती चीनी मिल, यमुनानगर	20.11.73	12.50	30.6.74	8.19		कोई बोनस गन्ना उत्पादकों को नहीं दिया जाता।
2	दी पानीपत सहकारी	20.11.73	12.50	10.5.74	13.00	1	अतिरिक्त भाव गन्ना 50 पैसे प्रति क्विन्टल सीजन शुरू होने से अन्त तक नकद दिया

	चीनी मिल, पानीपत						गया।
						2	चीनी के रूप में बोनस एक किलोग्राम प्रति टन गन्ना सप्लाई पर दिया गया। अधिकतम सीमा एक क्विंटल तक चीनी देने की थी। चीनी सबसिडी रेट 2.75 रूपये प्रति किलाग्राम की दर से दी गई।
3	दी हरियाणा सहकारी चीनी मिल, रोहतक	15.11.73	12ण्50	8.5.74	12ण्50		कोई बोनस गन्ना उत्पादकों को नकद रूप में नहीं दिया गया।
							चीनी के रूप में बोनस एक किलोग्राम प्रति एक टन गन्ना सप्लाई पर दिया गया। चीनी 2.85 रूपये प्रति किलोग्राम की दर से दी गई इस भाव में लेवी भाव चीनी तथा

							एक्साईज डियूटी फ्री चीनी पर सम्मिलित हैं ।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: हरियाणा में तीन मिलें हैं–एक रोहतक, एक पानीपत और यमुनानगर। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन तीनों में गन्ने के रेट के फर्क क्यों रहा हैं, अगर फर्क है तो क्यों है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, वैसे तो रेटस में कोई फर्क नहीं है। सारे प्रान्त में गन्ने का भाव 12 रूपये 50 पैसे प्रति क्विंटल दिया है। यमुनानगर शूगर मिल में और रोहतक शूगर मिल में पिछले साल पायरेला की वजह से रिकवरी कम हुई है। पानीपत की रिकवरी अच्छी रही और इसी वजह से 50 पैसे की क्विंटल ज्यादा कीमत किसानों को दी यानि 13 रूपये क्विंटल गन्ने का भाव कर दिया है, इसकी वजह यह है कि ज्यादा रिकवरी होने की वजह से दी है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरस्वती मिल यमुनानगर में किसानों को गन्ने का क्या रेट दिया है?

चौ. भजन लाल: 12 रूपये 50 पैसे से 8 रूपये 19 पैसे तक।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि इन तीन मिलों में किसानों का कितना रूपया बकाया है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, इन मिलों की तरफ कोई पैसा बकाया नहीं है, जो मिल वालों ने रोक रखा हो। अगर

किसान ने अपनी मर्जी से पैसा न लिया हो तो वह बात अलग है। वैसे थोड़ा–बहुत अमांउट बकाया हो सकता है, लेकिन हमें किसान की तरफ से कोई ऐसी शिकायत नहीं मिली कि मिल वाले पैसा देने में ज्यादती करते हों।

चौ. शिव राम वर्मा: जो चीनी कंट्रोल रेट पर मिलती है और जो खुले बाजार में मिलती है, इसका हिसाब लगाकर क्या मंत्री महोदय ने देखा है कि गन्ने की कीमत में और चीनी की कीमत में क्या तालमेल है?

चौ. भजन लाल: जब गन्ने का भाव तय करते हैं तो सारी बातें को ध्यान में रख कर करते हैं।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि सरस्वती मिल यमुनानगर में कौन कौन से महीने में कितना–कितना रेट किसान को दिया गया है?

चौ. भजन लाल: 16 मई, 1974 से पहले 12 रूपये 50 पैसे दिया, 16 मई, 1974 से 22 मई,1974 तक 11 रूपये 56 पैसे दिया, 22 मई, 1974 से 31 मई1974 तक 11 रूपये 50 पैसे दिया, 1 जून, 1974 से 7 जून, 1974 तक 10 रूपये 50 पैसे दिया, 8 जून, 1974 से 15 जून, 1974 तक 9 रूपये 28 पैसे, 16 जून, 1974 से 30 जून, 1974 तक 8 रूपये 19 पैसे दिया गया।

श्री अमर सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि 1972–73 में गन्ने का भाव 12 रूपये 50 पैसे क्विंटल था और लकड़ी का

भाव 18 रूपये 50 पैसे क्विंटल था, अगर ऐसा है तो यह डिस्पैरिटी क्यों है? (हंसी)

चौ. भजन लाल: मैं गन्ने का भाव बता सकता हूं, लकड़ी के भाव का सवाल नहीं हैं बल्कि सारे देश में सबसे अच्छा भाव हमारी मिलों ने दिया है।

चौ. दल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कि एक किलो चीनी की कौस्ट आफ प्रोडक्शन क्या है?

चौ. भजन लाल: यह हिसाब इनको लगाना चाहिए, हम तो हिसाब लगाकर ही गन्ने का भाव फिक्स करते हैं।

चौ. मेहर चन्द: क्या एग्रीकल्चर मिनिस्टर साहब बतायेंगे कि रोहतक शूगर मिल में जो बोनस तक्सीम किया है, क्या वे शेयर होल्डरों तक पहुंच गया है?

चौ. भजन लाल: इस सवाल से यह सप्लीमैंटरी उत्पन्न नहीं होता, इसके लिए अलग नोटिस चाहिए।

Mr. Speaker: It is a part of the question. Please see part "e" which read, "(e) whether any bonus in cash or kind was given to the cane growers".

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने बताया कि पानीपत शूगर मिलने 50 पैसे गन्ने का रट फालतू दिया है। इसी तरह से पानीपत शूगर मिल ने 1 टन गन्ना देने वाले किसान को 1 किलो चीनी 2.75 पैसे किलो के हिसाब से दी है। इसी तरह

रोहतक शूगर लि ने एक किलो चीनी एक टन गन्ना देने वाले किसान को 2 रूपये 85 पैसे किलो के रेट से दी है।

चौ. मनफूल सिंह: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि गन्ने की कीमत लेने के लिए किसानों को कई–कई चक्र लगाने पड़ते हैं यानी पैसे देर से मिलते हैं, क्या सरकार ऐसा इन्तजाम करेगी जिससे किसान को अरली पेमैंट की जाए?

चौ. भजन लाल: आनरेबल मैम्बर साहब ने बहुत अच्छी बात की है, हम इस बात को चैक करेंगे ताकि किसान को समय पर परपेमैंट हो। इस वक्त कोई ऐसी शिकायत सरकार सरकार के नोटिस में नहीं आई है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि पिछले साल चीनी का क्या रेट था और इन दिनों क्या है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यमुनानगर शूगर मल ने बोनस की शक्ल में किसानों को चीनी नहीं दी। जैसा मैंने बताया कि रेट जरूर कम दिया। शुरू में साढ़े बारह रूपये से शुरू किया और बाद में नहीं बढ़ाया।

चौ. मनफूल: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि मंहगाई ज्यादा होने की वजह से फर्टिलाईजर की कीमतों में बढौतरी और बिजली की कमी की वजह से गन्ने की लागत ज्यादा नहीं आती? क्या साढ़े बारह रूपये प्रति क्विंटल का भाव कम नहीं है, अगर कम है तो क्या सरकार भाव बढ़ाने की तजवीज कर रही है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, सरकार ने हाल ही में फैसला किया है कि भाव बढ़ने चाहिएं क्योंकि चीनी का भाव बढ़ा है। इस चीज को ध्यान में रख कर गन्ने का रेट 13 रूपये 75 पैसे किया है ओर यह रेट इस साल के शुरू से किया है, जो किसान शुरू में गन्ना देकर गया है उसको भी यही रेट मिलेगा।

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, रफी अहमद किदवई की रिपोर्ट के अनुसार जितेन रूपये क्विंटल चीनी बिके उतने आने क्विंटल गन्ना का भाव होना चाहिए। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो कीमत किसार को दी जाती है यह उस रिपोर्ट से तालमेल खाती है?

चौ. भजन लाल: यह बहुत पुरानी बात हो गई है, अब तो बड़ा फर्क हैं।

श्री गिरीश चन्द्र जोशी: स्पीकर साहब, यमुना नगर के साथ जो यू.पी. का इलाका सरसाब लगता है वहां पर पानीपत, रोहतक और यमुनानगर की निस्बत रिकवरी ज्यादा है। क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि यमुनानगर में रिकवरी क्यों कम है जबकि वे इलाके भी उसी बैल्ट पर आते हैं जिस पर सरसाब का इलाका आता है?

चौ. भजन लाल: रिकवरी तो सायल पर डिपैड करती है। पिछले साल रोहतक में कम रिकवरी रही है और इस साल ज्यादा है। पायरेला और किसी बीमारी की वजह से भी कम ज्यादा

रिकवरी होती रहती है। इस साल यमुनानगर की रिकवरी अच्छी चल रही है, यह सायल और बीमारी पर डिपैंड करता है।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि इन शूगर मिल्ज को सैन्ट्रल गवर्नमैंट की तरफ से कोई रिबेट मिलती है, अगर मिलती है तो पिछले दो सालों में कितनी–कितनी मिली है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब रिबेट मिलती है अरली चलाने पर भी बाद में चलाने पर भी। जहां तक इसके आंकड़ों का सवाल है वे इस समय मेरे पाास नहीं हैं। अगर ये इसके लिए सैपरेट नोटिस दे तो इसका जवाब भी दे देंगे।

चौ. पीर चन्द: क्या मिनिस्टर साहब बताने की कृपा करेंगे कि गनने की कीमत क्वालिटी के हिसाब स मुकर्रर होती है या सारे हरियाणा में अच्छे और खराब गन्ने की एक सी ही कीमत मुकर्रर होती है?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, भाव जो तुल कर गन्ना आता है उसके मुताबिक मिलता है यानि भाव तोल पर होता है और क्वालिटी का भी ध्यान रखा जाता है।

चौ. पीर चन्द: मैंने तोल की नहीं क्वालिटी की बात पूछी है।

(कोई जवाब नहीं दिया गया।)

लाला रूलिया राम: स्पीकर साहब, अभी बताया गया कि यमुनानगर मिल की रिकवरी कम आई है। क्या इस सम्बन्ध में इनके पास कुछ लोगों की तरफ से यह शिकायत आई है कि चूंकि वह एक प्राईवेट मिल है और कुछ गडबड़ी की वजह से उसकी रिकवरी कम होती है। इसके बरक्स पानीपत सरकारी मिल की रिकवरी ज्यादा है। इसी तरह की बात बाहर से जो टीम आई थी उसने भी कही है। क्या यह बात सच है?

चौ. भजन लाल: अध्यक्ष महोदय, यह मिल प्राईवेट है और इसका रिकार्ड हम देख नहीं सकते जबकि अपनी मिलों का रिकार्ड वक्तन फवक्तन देखते रहते हैं लेकिन जो कुछ आनरेबल मैम्बर साहब बता रहे है इस तरह की बात हमारे नोटिस में नहीं आई है और न ही इस किस्म की शिकायत कि वे किसी किस्म की गड़बड़ करते हों, हमारे पास नहीं आई है।

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अच्छी बात चाहे कितनी पुरानी क्यों न हो उसे पुरानी कह कर नहीं छोड़ना चाहिए क्योंकि वह देश के फायदे में नहीं होता। तो क्या मिनिस्टर साहब इस पुरानी बात पर विचार करेंगे?

Mr. Speaker: Order please. This is not a supplementary question.

श्री ओम प्रकाश गर्ग: स्पीकर साहब, अभी अभी मिनिस्टर साहब ने फरमाया कि सैन्ट्रल गवर्नमैंट मिल को जल्दी चलाने में भी और देर तक चलाने में भी रिबेट देती है। तो क्या

वे बताने की कृपा करेंगे कि जब मिल वालों का दोनों हालत में रिबेट मिलती है तो वे किसानो को एक सा पैसा क्यों नहीं देते?

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, सारी बातों का ध्यान रखकर ही भाव तक किए जाते हैं। ऐसी शिकायत हमारे प्रान्त में नहीं है कि कोई मिल कोई गलत काम करती है। ऐसी बात भी मेरे सामने नहीं आई है कि कोई मिल ज्यादा फायदा उठा कर किसानों को कम पैसा देती है।

चौ. शिव राम शर्मा: अध्यक्ष महोदय, क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि पुरानी बातों को छोडते हुए ही हम सरकार ने महात्मा गांधी की शिक्षा छोड़ी है और शराब को बढ़ावा दिया है? –(विघ्न)–

चौ. भजन लाल: स्पीकर साहब, हर पुरानी बात अच्छी नहीं हुआ करती। परन्तु उसकी तरफ देखने का हरेक का अपना अपना नजरिया होता है। पुराने जमाने में लोग मूंछे रखा करते थे परन्तु अब नहीं रखते। वर्मा जी ने अब भी रखी हुई हैं। क्या इसका मतलब यह है कि इनको अपनी मूंछे कटवा लेनी चाहिएं? –(हंसी)–

Fair Price Depost

***1175. Sh. Amar Singh**: Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state the number of Fair price depots in Urban and Rural areas district-wise in the State as on 1st May, 1968 and as on 1st December, 1974?

Social Welfare and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand): The requisite information is laid on the table of the house.

STATEMENT

Sr. No.	Name of Distt.	Total Number of Depots functioning as on 1-5-68			Sr. No.	Name of Distt.	Total Number of Depots functioning as on 1-12-74		
		Urban	Rural	Total			Urban	Rural	Total
1	Narnaul	25	370	395	1	Narnaul	62	330	392
2	Ambala	136	203	339	2	Ambala	174	311	485
3	Gurgaon	125	524	649	3	Gurgaon	153	377	530
4	Rohtak	115	456	571	4	Rohtak	115	363	478
5	Karnal	127	200	327	5	Sonepat	46	300	346
6	Hissar	132	273	405	6	Karnal	87	295	382
7	Jind	18	205	223	7	Kurukshetra	45	271	316
		678	2231	2909	8	Hissar	124	579	703
					9	Bhiwani	59	375	434

					10	Jind	28	156	184
						Total	893	3357	4250

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब मिनिस्टर साहब की तरफ से जो जवाब आया है उसके मुताबिक पोजीशन यह है कि 1 मई, 1968 को नारनौल में रूरल एरिया के अन्दर 370 डिपोज थे जबकि इनकी संख्या 1 दिसम्बर, 1974 को 330 बताई गई है। इसी तरह गुड़गावं की बात है। इसमें 1 मई, 1968 को रूरलल एरियाज में डिपोज की संख्या 524 थी परन्तु 1 दिसम्बर, 1974 को यह घटकर 377 रह गई। कुछेक दूसरे जिलों की भी यही पोजीशन है। तो मैं मिनिस्टर साहब से जब जानना चाहता हूं कि इसके कम होने का कारण क्या है? क्या यह कारण नहीं है कि क्योंकि रूरल एरियाज में आटा सही तरह से नहीं मिलता। इसीलिए लोग डिपो नहीं लेते?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, 1 मई, 1968 को सारे डिपोज 2909 थे जबकि 1 दिसम्बर,1974 की इनकी संख्या बढ़कर 4250 हो गई है। रीआर्गेनाइजेशन की वजह से कुछ एरिया इधर उधर हुआ है, अदरवाइज डिपोज हमारे इंक्रिज हुए हैं।

श्री अमर सिंह: स्पीकर साहब, 1 दिसम्बर, 1974 को भिवानी डिस्ट्रिक्टि में अर्बन एरिया मं 59 ओर रूरल एरिया में 375 डिपोज थे। मैं मिनिस्टर साहब से यह जानना चाहता हूं कि 375 जो रूरल एरिया में डिपोज हैं इनमें से कोई शिकायत उनके पास पहुंची है कि उन्हें आटा चार किलो प्रति युनिट के हिसार से नहीं मिलता?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, हरेक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और डी.एफ.एस.सी. को हिदायते दी गई हैं कि उनके जिले में जितनी डिमांड होगी उसे हम मीट करेंगे।

श्री जगजीत सिंह टिक्का: क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि डिपो से गन्दम और आटा तकसीम करने की शहर और गांव की पालिसी में जो फर्क है उसे मिटाने की कोशिश करेंगे?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, पर–हैड, पर–मन्थ एक सा ही मिलता है चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो।

श्री गौरी शंकर: स्पीकर साहब, मिनिस्टर साहब ने अभी फरमाया कि इंस्ट्रक्शंज जारी कर दी हैं। क्या उन्होंने कभी चैक भी किया कि डिपो पर आटा पहुंचता भी है या नहीं पहुंचता है?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, जहां आटा नहीं पहुंचता है वहां पर गेहूं भिजवा दिया जाता है।

चौ. फूल चन्द (मुलाना): क्या मंत्री महोदय के ज्ञान में यह है कि देहात में जो कपड़े के डिपोज इन्होंने खोले हैं वे बहुत कम है? अगर हैं, तो क्या उनकी संख्या बढ़ाने की तजवीज है ताकि लोगों को कपड़ा आसानी से मिल सकें?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, हर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को चिट्ठी भेज दी गई है कि पांच हजार की आबादी जहां पर हो वहां पर डिपो अलौट कर दें। क्लौथ का जहां तक

सम्बन्ध है जितना हमें कोटा मिलेगा उसके हिसारब से डिस्ट्रीब्यूशन होगी।

श्री ओम प्रकाश गर्ग: क्या मिनिस्टर साहब फरमायेंगे कि अगर उसके नोटिस में यह बात लाई जाए कि फलां जगह आटा ठीक तरह से नहीं पहुंचता या कम पहुंचता है तो वहां ठीक तरह से पहुंचाने की कोशिश की जाएगी?

श्री श्याम चन्द: जरूर जी।

चौ. फूल चन्द (मुलाना): मंत्री महोदय ने, स्पीकर साहब, अभी बताया कि पांच हजार आबादी वाले गांव के कपड़े का डिपो खोल दिया जाएगा। हमारे एरिया में तो पांच हजार आबादी वाले गांव बड़ी मुश्किल से दो या तीन होंगे। क्या वे बताने की कृपा करेंगे कि आस–पास के गांव को मिलाकर युनिट पूरा किया जाएगा?

श्री श्याम चन्द: जी हां।

चौ. मनफूल सिंह: स्पीकर साहब, आजकल ऐसा है कि हर गांव को चाहे उसकी आबादी बारह हजार की हो या तीन हजार की हो उसे केवल दस बोरी आटा दिया जाता है। हमारे यहां एक गांव बादली है उसकी आबादी बारह हजार की है लेकिन उसे भी दूसरे कम आबादी वाले गांव की तरह ही दस बोरी आटा मिलता है। क्या मिनिस्टर सहाब बताने की कृपा करेंगे कि डिस्ट्रिब्यूशन का प्रबन्ध आबादी के लिहाज से किया जाएगा?

श्री श्याम चन्द: यह बात, स्पीकर साहब, आनरेबल मैम्बर मेरे नोटिस में लाए थे। हमने अब इसका प्रबन्ध कर दिया है और हर डी.एफ.एस.सी. को इंस्ट्रक्शन इशू की हैं कि रिक्वायरमैंट के मुताबिक डिस्ट्रिब्यूशन किया जाए क्योंकि हमारे पास अनाज की शार्टेज बिल्कुल नहीं है।

चौ. पीर चन्द: क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस में यह बात है कि आटे के अन्दर क्योंकि मिलावट होती है इसलिये डिपो के आर्ट को लोग कम लेते है? क्या इस बात की कोई इक्वायरी की गई है?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, ऐसी कोई कम्पलेन्ट मेरे नोटिस में नहीं आई है। जहां तक अडलट्रेशन का सवाल हैं मैंने खुद हरेक मिल के सैम्पल चैक करवाए हैं। अगर आनरेबल मैम्बर किसी डिपो की या मिल की कंप्लेन्ट करेंगे तो उसकी हम जरूर इंक्वायरी करवायेंगे।

श्री गौरी शंकर: क्या मंत्री महोदय बताएंगे कि जिस डिपो पर न तो आटा पहुचता है और न कनक ही पहुंचती है वहां कोई सी चीज को भिजवाने की कृपा करेंगे? इसके साथ ही एक और बात का जवाब मैं जानना चाहता हूं। देहात में जो कपड़े के डिपो हैं वहां रद्दी कपड़ा जाता है क्योंकि अच्छा–अच्छा कपड़ा शहरों में रख लिया जाता है। क्या इस तरह भी मिनिस्टर साहब ध्यान देने की कृपा करेंगे?

श्री श्याम चन्द: स्पीकर साहब, कपड़ा तो एक ही किस्म का आता है लेकिन अगर कहीं आआ नहीं जाता है तो वहां उसे हम जरूर भिजवायेंगे।

लाला रूलिया राम: क्या मिनिस्टर साहब के नोटिस में कोई ऐसी शिकायत आई है कि करनाल का जो फलोर मिल है वह आटे में से मैदा निकाल लेता है? अगर आई है तो उस पर क्या ऐक्शन लिया गया है?

श्री श्याम चन्द: ऐसी कोई चीज मेरे नोटिस में नहीं आई है। हमने तो खुद सैम्पल लिए थे and there was no such thing.

Mr. Speaker: Question hour is over.

Harijan Welfare Advisory Boards

***1134. Ch. Dal Singh**: Will the Minister for Social Welfare and Taxation be pleased to state –

(a) whether District Harijan Welfare Advisory Boards have been formed in the State;

(b) if so, the dates of formation of such Boards as referred to in part (a) above; and

(c) the district-wise amount distributed among Harijans through the District Harijan Welfare Advisory Boards during the years 1972-73 and 1973-74 separately?

Social Welfare and Taxation Minister (Sh. Shyam Chand):

(a) At District level, District Harijan Welfare Advisory Committee and not Boards are constituted every year. These have not yet been set up fro the year 1974-75.

(b) Question does not arise.

(c) The amount distributed district-wise on the recommendations of teh Committees during the years 1972-73 and 1973-74 are given in the statement laid on the Table of the House.

Statement showing the District-wise amounts distributed during the years 1972-73 and 1973-74 on the recommendations of the District Harijan Welfare Advisory Committees.

Sr. No.	Year	Ambala	Bhiwani	Gurgaon	Hissar	Jind	Karnal	Kurukshetra	Mohindergarh	Rohtak	Sonepat
1	1972-73	170060	105040	158500	201000	76920	135210	111650	60714	122980	99600
2	1973-74	121000	71700	108000	196100	77500	92100	89900	67800	88600	56600

ANNEXURE 'A'

Statement showing the District-wise amounts sanctioned and distributed under the various Welfare schemes during the year 1972-73 on the recommendations of the District Harijan Welfare Advisory Committees.

Sr		Name of Scheme	Ambala		Bhiwani		Gurgaon		Hissar		Jind	
			Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted
1		Interest Free Loan to Scheduled Castes and Backward Classes	27000	27000	13500	13500	27000	26500	32000	32000	13300	12400
2	(i)	Houses for Sch. Castes (State Plan Scheme)	12600	12600	7200	7200	12600	12600	14400	14400	5400	5400

	(ii)	Houses for Sweepers, in Jayanti Villages. (Centrally sponsered)	7200	6300	5400	5400	12600	12600	12600	12600	6300	6300
	(iii)	Houses for Vimukt Jatis (Centrally sponsered)	4500	4500	2700	1800	3600	3600	4500	4500	2700	2700
3		House/Well Scheme	4500	4500	2500	2500	5000	3500	6000	6000	3000	2000
4		Piggery Scheme	5600	5600	2400	2400	6400	6400	6400	6400	2400	2400
5		3 per cent Loan for Land	48000	42000	26000	23800	44500	26500	58000	58000	24000	12000
6		Subsidy for Agricultural Implements/Inputs	2160	2160	14400	14400	2880	1800	3600	3600	1440	720
7		Dtrinking Water	65400	65400	47500	47500	65000	65000	63500	63500	33800	33000

		Wells										
		Total	176960	170060	108640	105040	179580	158500	201000	201000	92340	769020

ANNEXURE 'A' Contd.

Sr		Name of Scheme	Karnal		Kurukshetra		Mohindergarh		Rohtak		Sonepat	
			Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted
1		Interest Free Loan to Scheduled Castes and Backward Classes	18850	18850	18850	18850	8500	8000	23400	23400	11600	11600
2	(i)	Houses for Sch. Castes (State Plan Scheme)	9000	9000	9000	9000	3600	3600	9900	9900	6300	6300
	(ii)	Houses for Sweepers, in Jayanti Villages. (Centrally sponsered)	7200	7200	5400	5400	4500	4500	8100	8100	5400	5400

	(iii)	Houses for Vimukt Jatis (Centrally sponsered)	2700	2700	2700	2700	900	900	3600	1800	1800	1800
3		House/Well Scheme	3500	3500	3500	3000	2500	2500	2500	2000	1500	1500
4		Piggery Scheme	4000	4000	4000	4000	1600	1600	4000	4000	3200	3200
5		3 per cent Loan for Land	36000	36000	36000	30000	18000	18000	31200	26200	30000	30000
6		Subsidy for Agricultural Implements/Inputs	2160	2160	2160	1800	1080	1080	1800	1440	1440	1440
7		Dtrinking Water Wells	52300	51800	36900	36900	21000	20534	46140	46140	38860	38860
		Total	135710	135210	181510	111650	61680	60714	130640	122980	100100	99600

ANNEXURE 'B'

Statement showing the District-wise amounts sanctioned and distributed under various Welfare Schemes during the year 1973-74 on the recommendations of District Harijan Welfare Advisory Committees.

Sr		Name of Scheme	Ambala		Bhiwani		Gurgaon		Hissar		Jind	
			Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted
1		Interest Free Loan to Scheduled Castes and Backward Classes	25200	25200	13600	13600	21300	20800	38800	38800	15500	15500

2	(i)	Houses for Sch. Castes (State Plan Scheme)	74700	72900	39600	39600	63900	61200	114300	111600	45900	44100
	(ii)	Houses for Sweepers, in (Centrally sponsered)	8100	8100	5400	5400	7200	7200	13500	12600	4500	3600
	(iii)	Houses for Vimukt Jatis (Centrally sponsered)	2700	2700	1800	1800	2700	2700	5400	5400	2700	2700
3		House/Well Scheme	2500	2500	7000	6500	6500	6500	12500	12500	6000	6000
4		Piggery Scheme	9600	9600	4800	4800	9600	9600	15200	15200	5600	5600

		Total	122800	121000	72200	71700	111200	108000	199700	196100	80200	77500

ANNEXURE 'B' contd.

Statement showing the District-wise amounts sanctioned and distributed under various Welfare Schemes during the year 1973-74 on the recommendations of District Harijan Welfare Advisory Committees.

Sr		Name of Scheme	Karnal		Kurukshetra		Mohindergarh		Rohtak		Sonepat	
			Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted
1		Interest Free Loan to Scheduled	17500	16700	17500	17500	13600	13600	19400	18400	11600	11600

		Castes and Backward Classes										
2	(i)	Houses for Sch. Castes (State Plan Scheme)	52200	50400	52200	50400	39600	39600	57600	53100	34200	33300
	(ii)	Houses for Sweepers, in (Centrally sponsered)	5400	5400	5400	5400	4500	4500	4500	2700	4500	4500
	(iii)	Houses for Vimukt Jatis (Centrally sponsered)	2700	2700	2700	2700	1800	1800	2700	2700	1800	900
3		House/Well	11000	10500	8000	7500	3500	3500	4500	4500	1500	1500

		Scheme										
4		Piggery Scheme	6400	6400	6400	6400	4800	4800	7200	7200	4800	4800
		Total	95200	92100	92200	89900	67800	67800	95900	88600	58400	56600

ANNEXURE 'C'

Statement showing the District-wise amounts sanctioned and distributed under various Welfare schemes, during the year 1972-72 without inviting the recommendations of District Harijan Welfare Committees.

Sr	Name of Scheme	Ambala		Bhiwani		Gurgaon		Hissar		Jind	
		Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted
1	Chaupal Scheme	71000	71000	53000	53000	71000	71000	67000	67000	31000	31000
2	Legal Aid	1400	1400	30	30	660	660	30	30	600	600
3	Students Loan	24450	24450	16200	16200	24050	23450	15700	15100	14800	13300
4	Subsidy for										

	Girls Hostels										
	Total	96850	96850	69230	68830	95710	95110	82730	82130	46400	44900

Sr	Name of Scheme	Karnal		Kurukshetra		Mohindergarh		Rohtak		Sonepat	
		Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted
1	Chaupal Scheme	66000	66000	36000	36000	17000	17000	35000	35000	61000	61000
2	Legal Aid	780	780			250	250	120	120	60	60
3	Students Loan	21850	21250	15450	15450	17500	17100	29150	28250	14700	13700
4	Subsidy for Girls									30000	30000

	Hostels										
	Total	88630	88030	51450	51450	34750	34350	64270	63320	105760	104760

ANNEXURE 'D'

Statement showing the District-wise amounts sanctioned and distributed under various Welfare schemes, during the year 1973-74 without inviting the recommendations of District Harijan Welfare Committees.

Sr	Name of Scheme	Ambala		Bhiwani		Gurgaon		Hissar		Jind	
		Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted
1	Students Laon	28650	26250	11250	10850	15200	15200	17500	17700	10150	9150
2	Chaupal Scheme	121000	121000	101000	101000	102000	102000	150000	150000	57000	57000
3	Legal Aid	1200	1170								
	Total	150850	148420	112250	111850	117590	117500	167500	165700	67150	66150

Sr	Name of Scheme	Karnal		Kurukshetra		Mohindergarh		Rohtak		Sonepat	
		Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted	Amount sanc-tioned	Amount distri-buted
1	Students Laon	20050	19650	15600	15000	21500	20900	24600	22600	12950	11800
2	Chaupal Scheme	84000	84000	84000	84000	65000	65000	93000	93000	73000	55000
3	Legal Aid	330	330					920	650		
	Total	104380	102980	99600	99000	86500	85900	118520	116250	85950	66800

Procurement of Milk for the Jind Milk Plant

***1069. Sh. Dhaja Ram**: Will the Minister for Agriculture be pleased to state the names of districts in the State from where milk is being procured for the Jind Milk Plant together with the quantity thereof being procured, district-wise and the rate at which the same is being procured from each such District?

कृशि मंत्री (चौ. भजन लाल): मिल्क प्लांट जींद के लिए राज्य के लगभग सभी जिलों से दूध प्राप्त किया जा रहा है। 1.12. 74 से 10.12.74 तक की अवधि के दौरान इस मिल्क प्लांट ने औसतन 46840 किलोग्राम दूध प्रतिदिन हैण्डल किया और यह दूध निम्नलिखित जिलों से प्राप्त किया गया।

जिला	दूध की मात्रा
जीन्द	5550.4
करनाल	3668.1
रोहतक व सोनीपत	8920.9
गुड़गांव तथा महेन्द्रगढ़	12746.6
हिसार	881.8

अम्बाला	9706.7
भिवानी	5365.7
	46840.2

आजकल दूध खरीदने की दर 167.50 रूपए प्रति क्विटल, जिसमें 6.5 प्रतिशत चिकनाई हो, चल रही है।

Test Reports for Electricity Connection for Agriculture Purposes

***1088. Rao Dalip Singh**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

(a) the district-wise total number of test reports for electric connection for agriculture purpose pending in the State up-to-date; and

(b) whether it is proposed to give priority to the persons who have obtained loans from the banks for sinking wells?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):–

(क) जिलावार सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि बिजली बोर्ड के मंडल/परिमंडलों की सीमाएं जिला की राजस्व सीमाओं से विभिन्न हैं। तथापि कृशि के

लिए लंबित टैस्ट रिपोटो की परिमण्डलवार सूचना 30.11.74 को निम्नलिखित है:–

परिमण्डल का नाम	लंबित टैस्ट रिपोर्ट	जिले का लगभग क्षेत्र जो एक परिमण्डल में पड़ता है।
चंडीगढ	1322	अम्बाला और कुरूक्षेत्र का भाग।
करनाल	2227	करनाल और कुरूक्षेत्र का भाग और जींद जिले का भाग।
फरीदाबाद	465	गुड़गावं जिले का भाग।
देहली	2733	सोनीपत और गुड़गांव और रोहतक जिले का भाग।
हिसार	625	हिसार और भिवानी जिले का भाग।
रोहतक	1915	जीन्द, महेन्द्रगढ़ और रोहतक और भिवानी जिले का भाग।
कुल जोड	9287	

(ख) नहीं।

Over Bridge on Neelam crossing at N.I.T. Faridabad

***1093. Sh. K.N. Gulati**: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether there is any scheme under consideration of the Government to construct an over bridge on Neelam Railway Crossing at N.I.T. Faridabad.

(b) whether the Faridabad Complex has offered any amount as its share for the construction of the said bridge; and

(c) the time by which the said construction is likely to start?

Revenue Minister (Pandit Chiranji Lal Sharma):

(a) Yes, Sir.

(b) The Faridabad Complex has offered to share the cost of construction of the bridge in case the Railways refuse to share it.

(c) No target date can be given at this stage as the scheme is yet to be finalised with the Railways.

Self Sufficiency in Electricity

***1108. Sh. Girish Chander Joshi**: Will the Minister for Irrigation and power be pleased to state the steps, if any ,being taken to attain self sufficiency in the State in teh matter of electricity together with the period within which such self sufficiency is likely to be attained?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): राज्य द्वारा विद्युत क्षेत्र में आत्म निर्भरता प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए जा रहे है।

राज्य में निम्नलिखित तापीय बिजली घर बनाए जा रहे है:–

फरीदाबाद तापीय विद्युत परियोजना	2×60 मैगावाट
पानीपत तापीय विद्युत परियोजना	2×110 मैगावाट

व्यास कन्स्ट्रक्शन बोर्ड द्वारा बन रहे ब्यास परियोजना में राज्य, राजस्थान व पंजाब के साथ भी हिस्सेदार हैं। इस परियोजना के अन्तर्गत विभिन्न यूनिटों में हरियाणाा का हिस्सा निम्नलिखित है:–

व्यास यूनिट–1 चरण–1 (देहर परियोजना)	212 मैगावाट
व्यास यूनिट–2 चरण–2 (पोंग परियोजना)	40 मैगावाट

हरियाणा विभिन्न केन्द्रीय उत्पादन परियोजनाओं से विद्युत प्राप्त करने का भी प्रयत्न कर रहा है। केन्द्रीय परियोजनाए जिनमें हरियाणा का हिस्सा पहले से ही निर्धारित हो चुका है, निम्नलिखित है:–

हरियाणा का हिस्सा

बदरपुर तापीय बिजली घर	40 मैगावाट
सीबोल जल–विद्युत परियोजना (हिमाचल प्रदेश)	55 मैगावाट
सलाल जल–विद्युत परियोजना (जम्मू व कश्मीर)	50 मैगावाट

हरियाणा पहले से ही बदरपुर और राणाप्रताप अणा विद्युत प्लांट से बिजली प्राप्त कर रहा है। तथापि राणा प्रताप अणा विद्युत प्लांट से कोई पक्का हिस्सा निर्धारिता नहीं किया गया।

राज्य ने फरीदाबाद व पानीपत में कुछ और उत्पादक युनिट स्थापित करने का प्रस्ताव किया है। यह मामला भारत सरकार के विचाराधीन है।

Illegal Gratification

***1118. Ch. Mehar Chand**: Will the Chief Minister be pleased to state the number of Government Sevants who accepted illegal gratifications during the period from 1-7-1968 to 30-6-1974 and the disciplinary action taken against them?

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): वांछित सूचना एकत्रित करने में जितना समय और परिश्रम लगेगा, उसके मुकाबले में लाभ कम होगा।

Construction of Bus-Stands For Haryana Roadways

***1121. Sh. Behari Lal Balmiki**: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) the total number of bus-stands constructed for the Haryana Roadways during the year 1973-74 and 1974-75 to date; and

(b) the total number of Bus-Stands likely to be constructed for the said Roadways during the year 1975-76 together with their location?

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह): वाछित सूचना निम्न प्रकार से है:

(क) तथा (ख)

वर्श 1973–74 में निर्माण किए गए बस अड्डे	4

वर्श 1974–75 में निर्माण किए गए बस अड्डे	5
वर्श 1975–76 में जो बस अड्डे बनाए जायेंगे और उनकी लोकेशन।	
	बस अड्डों और कर्मशालाओं के चालू–निर्माण कार्य के अतिरिक्त 6 ओर स्थानों पर जहा पर भूमि अधिग्रहण की जा चुकी है, यदि धन राशि उपलब्ध हुई तेा अस्थाई बस अड्डे बनाने का विचार है।

Requirement of Electricity

***1153. Ch. Ram Lal Wadhwa**: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the total units of electricity required in the State during the year, 1973-74 and 1974-75 (to date) separately;

(b) the actual units of electricity received from different sources during the said period togetherwith the names of sources, separately; and

(c) the percentage of transmission line losses during the said period?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(क)	1973–74	24000 लाख इकाईयां
	1974–75	18961 लाख इकाईयां
	26.12.74 तक	

(ख) उपरोक्त समय में अलग–अलग स्त्रोंतो से मिलती हुई बिजली की इकाईयां इस प्रकार है:–

	स्त्रोत	1973–74 (लाख इकाईयां)	1974–75 (26.12.74 तक) (लाख इकाईयां)
1	भाखड़ा नंगल	13611.67	7044.70

	कम्पलैक्स		
2	इन्द्रप्रस्ाि	3313.94	2905.49
3	बदरपुर	277.15	1216.66
4	राणा प्रताप अणा बिजली घर	257.50	414.31
5	अपना उत्पादन	723.44	560.41
	कुल जोड़	18183.70	12141.57

(ग) 1973–74 में संचारिक नुकसान 9.3 प्रतिशत था और 1974–75 (आज तक) में 8.7 प्रतिशत है।

अतारांकित प्रश्न एवं उत्तर

Loan Borrowed from Different Sources

360. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Finance be pleased to state –

(a) the total amount of loan borrowed from different sources/agencies by the State Government during the period from April, 1968 to-dae together with the names of agencies and

amount of loan borrowed from them, separately;

(b) the balance repayable on 15th December, 1974 out of loans as referred to in part (a) above; and

(c) the amount of interest paid during the period as referred to in part (a) above on such loans together with the purpose of borrowing of loans?

(उत्तर)

अ.स. क्रमांक 10701—डब्ल्यू:एसः(3)—74

मंत्री,

वित्त विभाग, हरियाणा,

चण्डीगढ़

राम सरण चंद मित्तल

दिनांक, चण्डीगढ़ 3 जनवरी, 1975

विशयः अतारांकित विधानसभा प्रश्न क्रमांक 360 के उत्तर के सम्बन्ध में।

प्रिय चौ. सरूप सिंह जी,

कृपया विधान सभा के अतारांकित प्रश्न क्रमांक 360 जो दिनांक 6 जनवरी, 1975 की सूची में चौ. राम लाल के नाम है, कि ओर ध्यान देने का कश्ट करें।

2. इस प्रश्न से सम्बन्धित उत्तर तैयार नहीं है। इसका उत्तर सम्बन्धित सूचना के एकत्रित हो जने पर प्रस्तुत किया जायेगा।

आपका

हस्ता/–

(ग्राम सरण चन्द मित्तल)

श्री चौ. सरूप सिंह,

स्पीकर हरियाणा विधान सभा,

चण्डीगढ़।

Scheduled Castes and Backward Classes Employees

371. Sh. Amar Singh: Will the Chief Minister be pleased to state –

(a) the total number of Class I, II, III and IV Government employees in the State as on 31st May, 1968 and as on 31st December, 1974; and

(b) the total number of Class I, II, III and IV Government employees out of those referred to in part (a) above who belong to the Scheduled Castes and Backward Classes, separately?

समाज कल्याण मंत्री (चौ. भजन लाल):

31.5.1968 अनुसार

(क)	I	II	III	IV
	532	2173	71215	18362

(ख)	अनुसूचित जाति के कर्मचारी				पिछड़ी जाति के कर्मचारी			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	13	38	4482	4804		14	2697	1860

31.12.1974 अनुसार

(क)	I	II	III	IV

	949	3302	106355	26165

(ख)	अनुसूचित जाति के कर्मचारी				पिछड़ी जाति के कर्मचारी			
	I	II	III	IV	I	II	III	IV
	34	56	8726	7220	3	29	4701	3055

Grants by Khadi and Village Industries Board

358. Ch. Dal Singh: Will the Minister for Industries be pleased to state:-

(a) whether any grant has been given to industrial societies, firms and persons during the years 1973 and 1974 by the Khadi and Village Industries Board, Haryana; and

(b) if so, the number and names alongwith the addresses of the Industrial Societies, Firms, persons referred to in part (a) above together with the amount of grant given to each of these during the year 1973 and 1974 separately?

Industrial Minister (Sh. Harpal Singh):

(a) Yes.

(b) Two statements on in respect of 1973 and the other for 1974 are placed on the table of the House.

STATEMENT I

List of the Societies/Individulas/Institutions to whom grants disbursed during the year 1973

Sr. No.	Name and Addreess of unit	Grant
GURKHANDSARI INDUSTRY		
		Rs.
1	The Bega G.K.P. CIS Ltd. Bega (Sonepat)	200
2	The Kiwana Gramudyog Samiti, Kiwana (Karnal)	800
3	The Shiv Shakti Litani, G.K.P. CIS Ltd. Hissar	800
4	The Jai Kishan, G.K.P. CIS Ltd. Rajaund (Jind)	800
5	The Khedli Bhagmal, G.K.P. CIS Ltd. Khedli Bhagmal, (Gurgaon)	800

6	Ahrwam, G.K.P. CIS Ltd., Ahrwam (Hissar)	800
7	Yara, G.K.P. CIS Ltd., (Kurukshetra)	200
8	The Mochi, G.K.P. CIS Ltd., Mochi (Hissar)	200
9	The Barsola, G.K.P. CIS Ltd., Barsola (Hissar)	200
10	The Bari, G.K.P. CIS Ltd., Bari, (Rohtak)	200
11	The Ukhal Chana, G.K.P. CIS Ltd., Ukhal Chana, (Rohtak)	200
12	The Sadhnawas, G.K.P. CIS Ltd., Sadhnawas, (Hissar)	200
13	The Bali Qutabpur, G.K.P. CIS Ltd., District Sonepat	200
GOBAR GAS INDUSTRY		
1	Sh. Sultan Singh S/o Sh. Net Ram, Manasher	300
2	Sh. Ganpat Singh S/o Sh. Hari Singh, Manesher	300
3	Sh. Shiv Narain S/o Sh. Chander, Manesher	300
4	Sh. Gopi Ram S/o Sh. Jug Lal, Manesher	300

5	Sh. Surat Singh S/o Sh. Deegh Ram, Manesher	300
6	Sh. Sultan Singh S/o Sh. Murli Singh, Manesher	300
7	Sh. Shamsher Singh S/o Sh. Dalip Singh, Dharuhera	300
8	Sh. Raj Kumar S/o Sh. Ved Viyas, Babyal (Ambala)	300
9	Sh. Harcharan Singh S/o Sh. Gulab Singh, Ugla (Ambala)	300
10	Sh. Rajinder Singh S/o Sh. Pyara, Ugla (Ambala)	300
POTTERY INDUSTRY		
1	Sh. Om Parkash S/o Sh. Joo Ram, Ugla (Ambala)	200
2	Sh. Jiwan Ram S/o Sh. Moti Ram, Ugla (Ambala)	200
3	Sh. Narata Ram S/o Sh. Jee Ram, Ugla (Ambala)	200
4	Sh. Joti Ram S/o Sh. Kalu Ram, Shahbad, (Kurukshetra)	200
5	Sh. Madan Lal S/o Sh. Chet Ram, Shahbad, (Kurukshetra)	200

6	Sh. Sadhu Ram S/o Sh. Kalu Ram, Shahbad, (Kurukshetra)	200
7	Sh Jhandoo Ram S/o Sh. Mangal Sain, Shahbad (Kurukshetra)	200
8	Sh. Telu Ram S/o Sh. Ramji Lal, Rajpura (Jind)	200
9	Sh. Milla Ram S/o Sh. Gugan Ram, Khanpura (Jind)	200
10	Sh. Ratti Ram S/o Sh. Ami Lal, Jhajjar (Rohtak)	200
11	Sh. Mul Chand S/o Sh. Ami Lal, Jhajjar (Rohtak)	200
12	Sh. Amar Singh S/o Sh. Ami Lal, Jhajjar (Rohtak)	200
13	Sh. Manak Chand S/o Sh. Ami Lal, Jhajjar (Rohtak)	200
14	Sh. Kishori Lal S/o Sh. Ami Lal, Jhajjar (Rohtak)	200
15	Sh. Mangal Ram S/o Sh. Bihari Lal, Jhajjar (Rohtak)	200
16	Sh. Sheo Chand S/o Sh. Jaggan, Jhajjar (Rohtak)	200
17	Sh. Ude Singh S/o Sh. Kundal Lal,	200

	Jhajjar (Rohtak)	
18	Sh. Budh Ram S/o Sh. Mam Raj, Jhajjar (Rohtak)	200
19	Sh. Sohan lal S/o Sh. Mam Raj, Jhajjar (Rohtak)	200
20	Sh. Mohan Lal S/o Sh. Chuttan, Popara (Gurgaon)	200
21	Sh. sohan Lal S/o Sh. Chuttan, Popara (Gurgaon)	200
22	Sh. Dilsukn S/o Sh. Khushal, Popara (Gurgaon)	200
23	Sh. Dhandoo Ram S/o Sh. Chhote Lal, Popara (Gurgaon)	200
24	Sh. Sita Ram S/o Sh. Budh Ram, Maku (Gurgaon)	200
25	Sh. Phool Singh S/o Sh. Nandiya, Gurgaon	200
26	Sh. Kanhaiya S/o Sh. Tunda, Tain (Gurgaon)	200
27	Sh. Ramji Lal S/o Sh. Kishan Lal, Tain (Gurgaon)	200
28	Sh. Chandra S/o Sh. Ramla, Ferozepur Zhirka (Gurgaon)	200

29	Sh. Ramji Lal S/o Sh. Chhuttan, Gurgaon	200
30	Sh. Lakhi Ram S/o Sh. Nand Lal, Gurgaon	200
31	Sh.Subh Ram S/o Sh. Ganpat Ram, Malanwas (Mohindergarh)	200
32	Sh. Bhabha Ram S/o Sh. Durjan Ram, Sahbajpura, (Mohindergarh)	200
33	Sh. Ratti Ram S/o Sh. Lahri Ram, Pantawas, (Mohindergarh)	200
34	Sh. Bhura Ram S/o Sh. Mohan Ram, Sahbajpura, (Mohindergarh)	200
35	Sh. Bansi Dhar S/o Sh. Jhaber Ram, Kalbra (Mohindergarh)	200
36	Sh. Balu Ram S/o Sh. Ladu Ram, Kalba (Mohindergarh)	200
37	The Bhiwani Kiran B.K.P. CIS Ltd. Bhiwani	1500
38	The Bhiwani Saraswati B.K.P. CIS Ltd. Bhiwani	1500
39	The Bhiwani Friend B.K.P. CIS Ltd. Bhiwani	1500
40	The Hissar Khurma B.K.P. CIS Ltd.,	1500

	Hissar	
41	The Hansi B.K.P. CIS Ltd., Hansi (Hissar)	1500
42	The Uklana B.K.P. CIS Ltd., Uklana (Hissar)	1500
43	The Kheri Jalab B.K.P. CIS Ltd., Kheri Jalab (Hissar)	1500
44	The Mandi Adampur, B.K.P. CIS Ltd., Mandi Adampur, (Hissar)	1500
45	Teh Nimri-National B.K.P. CIS Ltd., Nimri (Hissar)	1500
46	The Kheri Sampla, B.K.P. CIS Ltd. (Rohtak)	1500
47	The Safidon, B.K.P. CIS Ltd., Safidon (Jind)	1500
48	The Jind Jai Bharat, B.K.P. CIS Ltd., Jind	1500
49	The Jind Haryana, B.K.P. CIS Ltd., Jind	1500
50	The Budha Khera Leather Pottery P. CIS Ltd., Jind	2000
51	The Azad, B.K.P. CIS Ltd., Narwana (Jind)	1500
52	Teh Narnaul Janta, B.K.P. CIS Ltd.,	1500

	Narnaul	
53	The Gram Udyog Kendra, Salwan (Karnal)	1500
54	The Singhra B.K.P. CIS Ltd., Singhra (Karnal)	1500

List of the Individulas to Whom the Grants Disbursed During the year, 1973

Sr. No.	Name and full Addreess	Grant
CARPENTRY AND BLACKSMITHY INDUSTRY		
1	Sh. Mukandi Ram S/o Sh. Santu Ram, VPO. Sankhera, (Ambala)	400
2	Sh. Parbhu Ram S/o Sh. Budhwa Ram, VPO. Sherpur (Ambala)	400
3	Sh. Umarao Singh S/o Sh. Ghumar Ram, VPO. Nangal (Mohindergarh)	330
4	Sh. Jai Narain S/o Sh. Hajari, VPO. Thanwas (Mohindergarh).	250
5	Sh. Barbhu S/o Sh. Pit Ram, VPO. Patharwa, (Mohindergarh).	250

6	Sh. Rameshwar S/o Sh. Dungar Ram, VPO. Shyampura (Mohindergarh).	250
7	Sh. Parbhu Lal S/o Sh. Budhwa Ram, VPO. Poginda (Mohindergarh).	250
8	Sh. Ram Pat S/o Sh. Har Dutt. VPO. Shyampura (Mohindergarh).	250
9	Sh. Ram Kumar S/o Sh. Har Dutt, VPO. Shyampura (Mohindergarh).	250
10	Sh. Nand Ram S/o sh. Laxmi Narain, VPO. Patharwa (Mohindergarh).	300
11	Sh. Guljari Lal S/o Sh. Sandu Ram, VPO. Palwal, (Hissar)	400
12	Sh. Ram Sarop S/o Sh. Topan Dass, VPO. Tohana (Hissar)	400
13	Sh. Sher Singh S/o Sh. Siv Karan, VPO. Dangra (Hissar).	250
14	Sh. Balbir Singh S/o Sh. Suraj Bhan, VPO. Madhuwala (Hissar)	250
15	Sh. Bhawar Singh S/o Sh. Gurunath Singh, VPO. Tohan, (Hissar)	250
16	Sh. Prem Singh S/o Sh. Gurmukh Singh, VPO. Tohana (Hissar)	397
17	Sh. Diwana S/o Sh. Ram Nath, VPO.	400

	Kharar, (Hissar)	
18	Sh. Nand Kishor S/o Sh. Khem Chand, VPO. Tohana, (Hissar)	250
19	Sh. Gurnam Singh S/o Sh. Sunder Singh, VPO. Rehanwali, (Hissar)	400
20	Sh. Bhajan Singh S.o Sh. Shyam Singh, VPO. Rehanwali, (Hissar)	400
21	Sh. Kartar Singh S/o Sh. Sant Ram, VPO. Tohana, (Hissar)	400
22	Sh. Gopal S/o Sh. Lekh Ram, VPO. Madhuwala, (Hissar)	400
23	Sh. Mani Ram S/o Sh. Mangla Ram, VPO. Motkharnial, (Hissar)	370
24	Sh. Manphool Singh S/o Sh. Suraj Ram, VPO. Madhuwala, (Hissar)	250
25	Sh. Khushi Mohmad S/o Sh. Anver, VPO. Sadulpur, (Hissar)	400
26	Sh. Shish Pal S/o Sh. Polu Ram, VPO. Juglan, (Hissar)	250
27	Sh. Umed Singh S/o Sh. Chandgi Ram, VPO. Sahwar, (Mohindergarh)	
28	Sh. Baru Ram S/o sh. Kunda, VPO. Mokhra, Distt, (Rohtak)	395

29	Sh. Hawa Singh S/o Sh. Lal Chand, VPO. Mokhra, (Rohtak)	250
30	Sh. Ram Kumar S/o Sh. Mansha Ram, VPO. Kandiala, (Jind)	250
31	Sh. Hom Singh S/o Sh. Joeta Ram, VPO. Kherijai Jawan, (Jind)	250
32	Sh. Ram Jani S/o Sh. Kharyati, VPO. Hirka, (Jind)	400
33	Sh. Baru Ram S/o Sh. Jiwan Ram, VPO. Kherijai Jawan, (Jind)	400
34	Sh. Kirpa Ram S/o Sh. Mai Ram, VPO. Kandiala, (Jind)	250
35	Sh. Kaur Singh S/o Sh. Nathu, VPO. Ramrai, (Jind)	400
36	Sh. Moti Ram S/o Sh. Barkat, VPO. Ikas, (Jind)	359
37	Sh. Sardara S/o Sh. Mithu Ram, VPO. Karsindhu, (Jind)	400
38	Sh. Gopi Ram S/o Sh. Jai Karan, VPO. Bhudhain, (Jind)	250
39	Sh. Maha Singh S/o Sh. Chhotu Ram, VPO. Jamni, (Jind)	
40	Sh. Sohan Lal S/o Sh. Mangria Ram,	250

	VPO. Gurgaon.	
41	Sh. Parmesh Chand S/o Sh. Bhagwan Dass, VPO. Hasangarh, (Gurgaon)	250
42	Sh. Hans Raj S/o Sh. Kesho Ram, VPO. Boharn Kalan, (Gurgaon)	250
43	Sh. Tej Ram S/o Sh. Indraj, VPO. Bahran Kalan, (Gurgaon)	400
44	Sh. Budh Ram S/o Sh. Kesho Ram, VPO. Bohran Kalan, (Gurgaon)	250
45	Sh. Om Parkash S/o Sh. Kesho Ram, VPO. Bahran Kalan, (Gurgaon)	400
46	Sh. Dev Dutt S/o Sh. Banwari Lal, VPO. Bohran Kalan, (Gurgaon)	250
47	Sh. Jai Karan S/o Sh. Sadhu Ram, VPO. Singoha (Karnal)	400
48	Sh. Aniat Ram S/o Sh. Bhana, VPO. Pogi Plot (Karnal)	400
49	Sh. Nhartiu Ram S/o Sh. Baktawar Lal, VPO. Singoha, (Karnal)	400
50	Sh. Ram Sarop S/o Sh. Ganga Ram, VPO. Bihi Pur Jatan, (Karnal)	400
51	Sh. Chapchal Singh S/o Sh. Dharsan Singh, VPO. Pakhi Mohal Singh,	400

	(Kurukshetra).	
52	Sh. Devi Dayal S/o Sh. Arujan Dass VPO. Kheroda, Teh. Kaithal (Karnal)	350
53	Sh. Faqor Chand S/o Sh. Daulat Ram, VPO. Bibi pur Jatan, (Karnal)	300
54	Sh. Imamudin S/o Sh. Finudin, Karnal	400
55	Sh. Hukam Chand S/o sh. Mam chand, VPO. Singoha (Karnal)	250
56	Sh. Devi Chand S/o Sh. Kundan Ram, VPO. Lopan Ledi (Ambala)	250
57	Sh. Rajan Lal S/o Sh. Mukandi Lal, VPO. Lopan Ledi (Ambala)	400
58	Sh. Ram Parshad S/o Sh. Chhjju Ram, VPO. Mahdhai (Ambala)	400
59	Sh. Balbir Chand S/o Sh. Puran Chand, VPO. Sadhupur, (Ambala)	400
60	Sh. Nandu Ram S/o Sh. Jiwan, VPO. Lopan Ledi (Ambala)	400
61	Sh. Parsh Ram S/o Sh. Biru Ram, VPO. Sherpur (Ambala)	400
62	Sh. Mam Chand S/o Sh. Kalu Ram, VPO. Lopan Ledi (Ambala)	250

63	Sh. Ratan Lal S/o Sh. Molu Ram, VPO. Nangli (Ambala)	400
64	Sh. Hot Ram S/o Sh. Sadhu Ram, VPO. Ambala.	400
65	Sh. Pannu Ram, S/o Sh. Parmanand, Chakhra (Ambala)	250
66	Sh. Faquir Chand Sh. Bhagwan Dass, Dadipur	400
67	sh. Mathura Ram S/o Sh. Chhjju Ram, VPO. Dariyapur.	400
68	Sh. Jai Ram S/o Sh. Bawadhana Ram, VPO. Sherpu (Ambala)	400
69	Sh. Parma Nand S/o Sh. Maghi Ram, VPO. Bhungherpur (Ambala)	400
70	Sh. Ram Lal S/o Sh. Bali Ram, VPO. Ganglu Chhachhroli (Ambala)	400
71	Sh. Chamala Ram S/o Sh. Kundan, VPO. Lopan Ledi (Ambala)	250

List of the Societies to whom the grants disbursed during the year 1973 in the Carpentry and Blacksmithy Industry

Sr.	Name of the Society	Grant

No.		
1	The Vikas Furniture and Sports P. CIS Ltd. Distt. Gurgaon.	5200
2	The Charkhi Dadri Upkar Wood and Furniture P. CIS Ltd. Charkhi Dadri (Gurgaon)	5200
3	The Krishna Gramudyog Mandal, Tohana.	5200
4	The Hissar Raj Furniture P. CIS Ltd. Hissar.	5200
5	The Charkhi Dadri Janta Engineer P. CIS Ltd.,	1600
6	The National Furniture P. CIS Ltd., Hansi.	5200
7	The Bejalpur Wood P. CIS Ltd., Bejalpur.	1500
8	The National C & B, P. CIS Ltd., Keorak	5200
9	The Hansi Swantantra Agro, Engg. P. CIS Ltd. Hansi	5200
10	The Dangra C. & B. Industry P. CIS Ltd., Tohana	1500
11	The Idel and Iron and Steel Impl. P. CIS Ltd., Sonepat	5200

12	The The Sonepat Iron Woods P. CIS Ltd., Sonepat	5200
13	The Badali Agri. Impl. P. CIS Ltd., Badli	5200
14	The Naveen Steel And Furniture P. CIS Ltd., Ambala Cantt.	4000
15	The pardeep Iron and Steel Goods P. CIS Ltd., Rohtak	5200
16	The Meham Wood Works P. CIS Ltd., Meham (Rohtak)	6700
17	The Vishkarma Furniture and Wood P. CIS Ltd., Fathehpur (Karnal)	5200
18	The Tarawari Agri. Impli. P. CIS Ltd, Tarawari (Karnal).	5200

List of the Societies to whom Grant was disbursed during the year 1973.

Sr. No.	Particulars	Grant
	LEATHER INDUSTRY	
1	The Janta Shoe Maker P. CIS Ltd, Faridabad, (Gurgaon).	4750

2	The Delight Footwear P. CIS Ltd, Sadar Bazar Karnla	4750
3	The Hissar Footwear P.CIS Ltd, Hissar	4750
4	The Gopal Footwear P. CIS Ltd, Sadar Bazar, Karnal	4750
5	Sh. Ravidass Footwear P. CIS Ltd, Sadar Bazar, Karnal	4750
6	The Modern Footwear P. CIS Ltd., Kandu (Gurgaon)	3900
7	The Ajanta Footwear P. CIS Ltd., Karnal.	4750
8	The Bright Udyog Sangh, Rohtak	4750
9	The Unique Footwear P. CIS Ltd., Rohtak	960
10	The Haryana Charamudyog Sangh, Ambala Cantt.	31000
11	Sh. Nathi S/o Sh. Faquira Kaoha, Talab Hodel, (Gurgaon)	420
12	Sh. Parbati S/o Sh. Chhaju Ram Kaohha, Talab Hodel, (Gurgaon)	420
13	The Bhartiya Gramudyog, Sadar Bazar, Karnal	1800
14	The Hansi Shoe marker P. CIS Ltd., Gohana (Hissar)	300

List of the Societies/Individuals/Institutions to whom Amount of Grant given during the year 1973.

Sr. No.	Particulars	Grant
	NEO SOAP INDUSTRY	
1	Kheri Jajwan Oil and Soap P. CIS Ltd., Patala Chowk, Jind.	1200
2	Kheri Jajwan Oil and Soap P. CIS Ltd, Patala Chowk, Jind	61739
3	Faridabad Prem Soap and Alied P. CIS Ltd., Faridabad	1500
4	Sirsa Shanker Soap P. CIS Ltd., Sirsa	1046
5	Narwana Oil and Soap P. CIS Ltd., Narwana (Jind)	1500
6	Ideal School for Childern (Hissar)	17178
7	New Light Neo Soap Tohana (Hissar)	1200
8	Arya Gramudyog Mandal, Ladwa (Kurukshetra)	1200
	LIME INDUSTRY	
1	Wazir Pur Lime Stone P. CIS Ltd.,	2400

	Wazirpue (Gurgaon)	
2	Kanhety Lime Stone P. CIS Ltd., Kanhety (Bhiwani)	2400
3	Palwal Lime Stone P. CIS Ltd., Palwal (Gurgaon)	3000
4	Hudina Lime Stone P. CIS Ltd., Hudina (Mohindergarh)	2400
5	Narinder Dev Narang S/o Sh. K. D. Narang, H. No. 119, Four Marla, Gurgaon.	2500
6	Hoshiarpur Singh S/o Sh. Duli Chand, V. and P.O. Nangal Sirohi (Mohindergarh).	2500
7	Mam Singh S/o Sh. Kisore Lal, V. Amirpur, P.O. Gamraj (Gurgaon).	3000
8	Narain Dass S/o Sh. Deg Ram, V. Lakhuwas Dhami, P.O. Sohna (Gurgaon)	3000
9	Radhey Shyam S/o Sh. Gauri Shanker, V and P.O. Lhaunhera (Mohindergarh).	3000
10	Omkar S/o Sh. Parbhati Lal, H.No. 391, Kath Mandi, Rewari (Mohindergarh).	2800
11	Shyam Sunder S/o Sh. Gaja Nand, Mohalla Frams-Khoma, Narnaul (Mohindergarh).	3000

List of the Societies/ Institutions /Individuals to whom Grant was disbursed During the year 1973.

Sr. No.	Name	Grant
PROCESSING OF CEREALS AND PULSES INDUSTRY		
1	The Safidon Handpounding of rice P. CIS Ltd., Safidon (Jind)	3000
2	The Jamal Oil Ghani and Pulses P. CIS Ltd., Jamal (Hissar)	3000
3	The Swatanter Cereals and Pulses P. CIS Ltd., Nilokheri (Karnal)	3000
4	Sh. Ram Kumar S/o Sh. Lachhaman Dass, Radhour (Kurukshetra).	500
5	Sh. Vijay Kumar S/o Sh. Sardari Lal., Patherwali Kothi, Kalka (Ambala)	500
COTTAGE MATCH INDUSTRY		
1	Brij Match P. CIS Ltd., Hodle (Gurgaon)	2350
VILLAGE OIL INDUSTRY		
1	Sultan S/o Sh. Nathi Teli, V. Karaka,	250

	P.O. Ujjana (Gurgaon)	
2	Alizam S/o Sh. Chand Ram, Teli, VPO. Meerpur (Mohindergarh).	250
3	Roshan Khan S/o Alibax, V. Karaka, (Gurgaon)	250
4	Ali Hasan S/o Bundi Teli, V. Muzafat Kala, P.O. Khijrabad (Ambala)	250
5	Banwari Lal S/o Allah Mehar, V. Niaya (Hissar)	250
6	Rustam Khan S/o Ibrahim Teli, VPO. Malai (Gurgaon).	250

STATEMENT II

List of Cooperative Societies/Institutions/Individuals to whom amout of Grant given during the year 1974.

	Name of the Society/Institution/Person	Amount of Grant
	1	2
FRUIT PRESERVATION INDUSTRY		
1	The Teja Khera Fruit Preservation P/CIS	3750

	Ltd., Teja Khera (Hissar)	
2	The Karnal Achar Murabba P/CIS Ltd., Karnal	2250
3	The Karnal Achar Murabba P/CIS Ltd., Karnal	1500
NEO SOAP INDUSTRY		
1	Roshan Lal S/o Sh. Sita Ram, H.No. 1577, Ram Bagth Road, Ambala Cantt.	750
2	Chittar Kumar S/o Johri Ram Aggarwal, H.No. 224, Civil Line, Gurgaon	750
3	Ved Parkash S/o Rakha Ram, 18, Kasturba Colony, Ambala Cantt.	750
4	Rattan Lal S/o Puran Chand, Kakar Majra (Ambala)	750
5	Ram Saroop S/o Bhiku Mal, H.No. 78, Ward No. 9, Gharounda (Karnal)	750
6	Arya Gramudyog Mandal, Ladwa (Kurukshetra)	554/14
LIME MANUFACTURING INDUSTRY		
1	Dongra Ahir Lime Stone, P/CIS Ltd., Dongra (Mohindergarh).	2400
2	Surajpur Gramudyog Samiti, Surajpur	3000

	(Ambala)	
3	Kanhety Lime Stone, P/CIS Ltd., Kanhety (Mohindergarh).	1800
4	Hidiana Lime Stone, P/CIS Ltd., Hudiana (Mohindergarh).	1800
5	Palwal Lime Stone, P/CIS Ltd., Palwal (Gurgaon).	1150
PROCESSING OF CENEAL & PULSES INDUSTRY		
1	Koer Hand Pounding of Rice P/CIS Ltd., Koer (Karnal)	1200
2	Haryana Gram Sewa Sadan, Dharuhera (Mohindergarh).	1200
3	Haryana Khadi Gramudyog Samiti, Narwana (Jind)	720
4	Fatehabad Cereals & Pulses P/CIS Ltd., Fatehabad (Hissar)	1200
COTTAGE MATCH INDUSTRY		
1	Haryana Khadi Gramudyog Samiti, Ambala City.	500
VILLAGE OIL INDUSTRY		
1	Navjeevan Singh, Kurukshetra	950
FIBRE INDUSTRY3650		

1	Ghuharpur Kalan Bag Making P/CIS Ltd., Ghuharpur Kalan, (Ambala).	3650
2	Triloki Nath S/o Basheshar Nath, Bandapur (Sonepat)	300
3	Ram Sarup S/o Mam Chand, Safidon (Jind)	300
4	Balbir Singh S/o Mehar Singh, Balu (Karnal)	300
5	Babu Ram S/o matu Ram, Pundrak (Karnal)	300
6	Lakshman Dass Kalra S/o R.C. Kalra, (Karnal)	300
7	Singha Ram S/o Daya Ram, Chibha (Kurukshetra)	300
8	Ajit Singh S/o Saudagar Singh, Chibha (Kurukshetra)	300
9	Khushwant Singh S/o Fateh Singh, Dera Fateh Singh (Kurukshetra)	300
10	Ranjit Singh S/o Phool Singh, Dialpur (Kurukshetra)	300
11	Charan Singh S/o Labh Singh, Dharaula (Kurukshetra)	300
12	Ram Singh S/o Bir Singh, Dharaula (Kurukshetra)	300
13	Tejpal Singh S/o Risal Singh, Chibha	300

	(Kurukshetra)	
14	The Gopalan Kendra (Navjeevan Sangh), (Kurukshetra)	1862
15	Umrao Singh S/o Khushi Ram, Manasher (Gurgaon)	300
16	Baldeva Teyal S/o Mahadeva, Hissar	300
VILLAGE POTTERY INDUSTRY		
1	Mangat Ram S/o Sh. Mani Ram, Thana Chhappar (Ambala)	650
2	Amar Nath S/o Hari Ram, Ambala	650
3	Gian Chand S/o Daulat Ram, Ambala	650
4	Man Chand S/o Paras Ram, Ambala	650
5	Paras Ram S/o Antu Ram, Malikpur (Ambala)	650
6	Banarsi Lal S/o Sarda Ram, Biruwala (Ambala)	650
7	Mansa Ram S/o Antu Ram, Ambala	650
8	Lal Chand S/o Mata Dari, Nai Sarai, Narnaul	650
9	Budh Mal S/o Mata Dari, Purani Sarai Narnaul	650

10	Giga Ram S/o Chottu Ram, Purani Sarei, Narnaul	650
11	Ratti Ram S/o Jai Ram, Nai Sarai, Narnaul	650
12	Malha Ram S/o Jutha Ram, Nai Sarai, Narnaul	650
13	Puran Mal S/o Nang Ram, Hazipur.	650
14	Rohtash Kumar S/o Murli Dhar, Hazipur.	650
15	Neki Ram S/o Asha Ram, Dingsarai (Hissar)	650
16	Banwari Lal S/o Mehar chand, Bhattan Kalan (Hissar)	650
17	Manglu Ram S/o Kalu Ram, Bhattan Kalan (Hissar)	650
18	Jagdish S/o Mani Ram, Bhattan Kalan (Hissar)	650
19	Om Parkash S/o Ravi Sukh Dass, Bhattan Kalan (Hissar)	650
20	Ladu Ram S/o Ramji Lal, Bhattan Kalan (Hissar)	650
21	Suraj Bhan S/o Sh. Kanha Ram, Bhattan Kalan (Hissar)	650
22	Ram Kishan S/o Daulat Ram, Mela Ground, Sirsa (Hissar)	650

23	Nathi S/o Kesariya, Kot Mohalla, Palwal (Gurgaon)	650
24	Mula S/o Budha, Raidaska Gurgaon	650
25	Suraj Bhan S/o Ramji Lal, Palwal (Gurgaon)	650
26	Bhandu S/o Baldeva, Nirwan (Gurgaon)	650
27	Khubi Ram S/o Maindhu, Rundhi (Gurgaon)	650
28	Bhagawana S/o Mangat Ram, Pataudi (Gurgaon)	650
29	Mangat S/o Tula Ram, Ralwal (Gurgaon)	650
30	Om Parkash S/o Hira Ram, Chibha (Kurukshetra).	650
31	Maya Rani W/o Prem Chand, Bera Khurd (Kurukshetra).	650
32	Sadhu Ram S/o Ganga Ram, Babain (Kurukshetra).	650
33	Ram Nath S/o Bhisha Ram, Chibha (Kurukshetra).	650
34	Parbhu Ram S/o Kashmiri Lal, Kaithal.	650
35	Sat Pal S/o Balak Ram, Umri (Kurukshetra).	650
36	Prem Chand S/o Raja Ram, Umri (Kurukshetra).	650

37	Jeet Ram S/o Faqir Chand, Yara (Kurukshetra).	650
38	Mam Chand S/o Mangal Sain, Ladwa (Kurukshetra).	650
39	Shiv Ram S/o Karta Ram, Yara (Kurukshetra).	650
40	Bhagat Ram S/o Mado Ram, Ladwa (Kurukshetra).	650
41	Lachmi Chand S/o Narata Ram, Ladwa (Kurukshetra).	650
42	Kura Ram S/o Assa Ram, Ladwa (Kurukshetra).	650
43	Santa Ram S/o Budh Ram, Thanehsar, (Kurukshetra).	650
44	Santa Ram S/o Surjeet Singh, Fatehpur, (Kurukshetra).	650
45	Rasala Ram S/o Dati Ram (Kurukshetra).	650
46	Sawan Ram S/o Budh Ram, Thanehsar, (Kurukshetra).	650
47	Sadhu Ram S/o Antu Ram, Ladwa (Kurukshetra).	650
48	Jagdish Kumar S/o Data Ram, Ladwa (Kurukshetra).	650

49	Mam Chand S/o ChhajuRam, Seedpur (Karnal)	650
50	Kishan Chand S/o Chheter, Seedpur (Karnal)	650
51	Krishan Lal S/o Jeti Ram, Seedpur (Karnal)	650
52	Phool Singh S/o Suraj Ram, Seedpur (Karnal)	650
53	Gram Seva Sadan, Muwana (Jind)	1500
DARPENTRY AND BLACKSMITHY INDUSTRY		
1	TheVishwakarma Agro, Gramudyog Samiti, Jalbera (Ambala)	1500
2	The Ellanabad Janta Agr. Impl. P/CIS Ltd., Ellanabad.	1500
3	The Bejalpur Wood P/CIS Ltd., Bejalpur.	1500
4	The Hissar Iron Works P/CIS Ltd., M/T, Hissar	1500
5	Krishna Gramudyog Mandal, Tohana	1500
6	The Friends Iron & Steel Agr. Impl. P/CIS Ltd., Panipat	1500
7	The Faridabad C. & B. Industry P/CIS Ltd., Faridabad	1500
8	The Vishwakarma Agro. Gramudyog Samiti,	1500

	Jalbera (Ambala)	
9	The Vishwakarma Iron & Wood P/CIS Ltd., Fatehpur (Karnal)	1500
10	The Hissar Himko Steel & Aluminium Goods P/CIS Ltd., Hissar	5200
LEATHER INDUSTRY		
1	Ambala Cantt. P/CIS Ltd., Ambala Cantt.	1440
2	Rewari Sangikabass P/CIS Ltd., Rewari, (Mohindergarh)	1200
3	Janhit Gramudyog Mandal, Ambala Cantt.	1920
4	Sirsa Janta Footwear P/CIS Ltd., Sirsa (Hissar)	960
5	Taru Modern Footwear P/CIS Ltd., Sadar Bazar, Karnal	4750
6	Taru Modern Footwear P/CIS Ltd., Gurgaon	4750
7	Bansa Ram S/o Chhitru, Bihta (Ambala)	750
8	Sawan Ram S/o Nanak Chand, Bodholi (Ambala)	450
9	Babu Singh S/o Jamal Singh, Sadhaura (Ambala)	500
10	Sadhu Singh S/o Attar Singh Sadhaura (Ambala)	500

11	Jabu Singh S/o Bucha Singh, Thember (Ambala)	500
12	Miluhi Singh S/o Ruldhu Ram, Sadhaura (Ambala)	500
13	Naurata Ram S/o Ranu Ram, Sadhaura (Ambala)	265
14	Nanak Chand S/o Indu Ram, Sadhaura (Ambala)	265
15	Jagir Chand S/o Babu Singh, Sadhaura (Ambala)	265
16	Mam Chand S/o Indrog, Ward No. 4, Gohana (Sonepat)	276
17	Parbhu S/o Mehar Chand, Ward No. 4, Gohana (Sonepat)	276
18	Dargoo Singh S/o Risala, Ward No. 4, Gohana (Sonepat)	276
19	Rati Ram S/o Baru Ram, Rami Rai (Jind)	500
20	Surjan S/o Bhuru, Barkhera (Jind)	500
21	Karatara S/o Mansa Ram, Kurar (Jind)	500
22	Faqir Chand S/o Juglal, Ram Rai (Jind)	500
23	Ronak Ram S/o Asa Ram, Kurar (Jind)	500
24	Sone Ram S/o Sohnu Ram, Tohana (Hissar)	500

25	Har Lal S/o Sh. Tulsi, Kheri Barli, P.O. Juglan (Hissar)	500
26	Surja Ram S/o Beg Raj, Tohana (Hissar)	500
27	Panna Lal S/o Gokul Ram, Mohalla Saraywala, Moli Nagar, Distt. Hissar	500
28	Jai Lal S/o Surja Ram, Mohalla Tekra Multani, Distt. Hissar	
29	Sulam S/o Harkesh, Ward No. 4, Gohana (Sonepat)	
30	Lakhi Ram S/o Pehlad, Anaj Mandi, Gohana (Sonepat)	
31	Phulu Ram S/o Pankira, Old Adda, Gohana (Sonepat)	
32	Daya Ram S/o Hoshiar, H.No. 420, Gohana (Sonepat)	
33	Rishal Singh S/o Ram Dass, Gurgaon	
34	Om Parkash S/o Lal Chand, Jhorasa (Gurgaon)	
35	Naval Singh S/o Bhole Ram, Jhorasa (Gurgaon)	
36	Bansi Lal S/o Reta Ram, Gurgaon	
37	Ram Parkash S/o Sh. Nathu Ram, Gurgaon	

38	Lala Ram S/o Nathr Ram, Moh.-8, Biswa, Gurgaon	
39	Phulu Ram S/o Jhandu Ram, Ladwa (Kurukshetra)	
40	Jyoti Ram S/o Jhandu Ram, Ladwa (Kurukshetra)	
41	Sher Singh S/o Rura Ram, Chanaura Jatan, P.O. Ladwa (Kurukshetra)	
42	Jeet Singh S/o Mukhia Ram, Ladwa (Kurukshetra)	

Domestic Connection

359. Ch. Ram Lal Wadhwa: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the number and names of villages in the State where no electricity domestic connection has been taken by the inhabitants so far; and

(b) the number of villages in the State where 10, 25 and 50 domestic connections of electricity have been taken by the inhabitants separately?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

इस सूचना को एकत्रित करने में लगने वाला समय तथा श्रम, इस प्रश्न से प्राप्त परिणाम के अनुरूप नहीं होगा।

Cinema Licences

361. Ch. Dal Singh: Will the Minister for Home be pleased to state –

(a) the number of cinema licences issued in the State during the year 1973-74; and

(b) the names together with the addresses of persons in whose favour licences as referred to in part (a) above were issued in 1973-74?

गृह मंत्री (श्री के. एल. पोसवाल):

(ए) 24

(बी) अपेक्षिता सूचना संलग्न सूची में दी गई है।

सूची

उन व्यक्तियों के नाम तथा पतों का विवरण जिनको 1973–74 में सिनेमा लाईसैंस जारी किये गये।

क्र. स.	सिनेमा का नाम		सिनेमा लाईसैन्सदारों के नाम तथा पते
			जिला हिसार

1	पुश्पा सिनेमा, हिसार		श्री सुभाश चन्द्र पुत्र श्री गुलाब सिंह जैन एडवोकेट, हिसार।
2	नीलम सिनेमा, हिसार	(1)	सर्वश्री महिन्द्र कुमार, जिनेन्द्र कुमार, राजेन्द्र कुमार, पुत्र गण श्री बनवारी लाल हिसार।
		(2)	श्रीमती किरनो देवी पत्नी श्री पदम कुमार, हिसार।
		(3)	श्री रामानन्द पुत्र तुला राम, हिसार।
		(4)	पूरन चन्द पुर रामेश्वरदास, हिसार।
		(5)	कृश्ण कुमार, सुभाश चन्द्र, सीता राम पुत्रगण प्रभुराम, हिसार।
3	सूरज सिनेमा, सिरसा	(1)	श्री इन्द्र कुमार पुत्र रूप चन्द, 20 ए, नई दिल्ली

			सिरसा।
		(2)	मोहिन्द्र कुमार पुत्र सोहन लाल, 23 ए, नई मण्डी, सिरसा।
		(3)	श्रीमती राम प्यारी देवी, पत्नी आई दान, 67 ए, नई मण्डी, सिरसा।
		(4)	श्रीमती जासमा देवी, पत्नी श्री भजन लाल, आदमपुर।
		(5)	श्रीमती चावली देवी पत्नी पोखरमल, आदमपुर हिसार।
4	सोहन सिनेमा, हिसार	(1)	श्री शिशपाल सिंह एडवोकेट, हिसार।
		(2)	श्री सुखबीर सिंह पुत्र चौ. दलीप सिंह, दौलतपुर, हिसार।
		(3)	श्री ललितपाल सिंह पुत्र

			श्री शिशपाल सिंह, हिसार।
		(4)	श्री विजयपाल सिंह पुत्र श्री शिशपाल सिंह, हिसार।
		(5)	श्रीमती पुश्पा रानी पुत्री श्री शिशपाल सिंह, हिसार।
		(6)	श्रीमती भगवानों देवी पत्नी श्री दलीप सिंह, दौलतपुर।
		(7)	श्रीमती शीला देवी पत्नी श्री बी.एस. लाम्बा, दौलतपुर।
		(8)	श्री अमरजीत पुत्र श्री पी. एस. लाम्बा, दौलतपुर।
		(9)	श्री जसबीर सिंह पुत्र श्री दलीप सिंह, दौलतपुर, हिसार।

		(10)	श्री हरद्वारी लाल पुत्र श्री मोहर सिंह, गांव न्याली।
		(11)	श्री परमजीत सिंह पुत्र श्री पी.एस. लाम्बा, दौलतपुर।
5	गनेरीवाला सिनेमा, एलनाबाद		श्री महावीर प्रसाद पुत्र श्री वैनी गोपाल गनेरीवाला तथा श्रीमती द्रोपदी देवी पत्नी श्री महावीर प्रसाद गनेरीवाला सूरतगढ़िया बाजार, सिरसा।
जिला नारनौल			
6	राजेन्द्र टूरिंग टाकीज, कनीना		श्री गोपी राम पुत्र श्री गुलजारी प्रसाद शर्मा, कनीना जिला महेन्द्रगढ़
7	राधिका थियेटर, रिवाड़ी		मैसर्ज प्रेम एन्टर प्राईजिज, पार्टनर सर्वश्री राजकुमार जैन, प्रेम कुमार जैन तथा संतोश

			कुमार जैन, पुत्र राजा रति राम, सिविल लाईन, गुडगांव।
जिला सोनीपत			
8	गन्नौर में चलता फिरता चल चित्र		श्री मांगे राम पुत्र श्री सरदार सिंह ग्राम ककरोई, तहसील व जिला सोनीपत।
जिला जीन्द			
9	गोल्डन टूरिंग टाकीज, सफीदों		श्री प्यारे लाल पुत्र श्री देश राज सकना सफीदों
जिला गुडगांव			
10	गगन सिनेमा फरीदाबाद		बाबा बलदेव सिंह सपुत्र बाबा ओतार सिंह, 35 राजपुरा रोड, दिल्ली।
11	उपकार थियेटर, होडल	(1)	श्रीमती सत्या चौ. धर्म पत्नी श्री ब्रहम प्रकाश।
		(2)	श्री सिधारथ चौधरी तथा

		(3)	श्री अजय चौधरी पुत्रान श्री ब्रहम प्रकाश 7 निजामुदीप वैस्ट, दिल्ली।
		(4)	श्री देव राम सिंह सपुत्र कप्तान छोटूराम।
		(5)	कप्तान छोटू राम सपुत्र गोधू राम ग्राम आया नगर, पोस्ट आफिस महरौली।
12	देव चित्रलोक सोहना	(1)	श्रीमती शान्ति देवी धर्मपत्नी श्री गंगा स्वरूप वशिश्ठ सदर बाजार, गुडगांवा
		(2)	श्रीमती वीना जैन धर्मपत्नी श्री सबोध जैन, दरिया गंज, दिल्ली।
13	प्रभात टूरिंग टाकीज, फरीदाबाद ओल्ड		श्री दौलत राम केकड़ सपुत्र श्री कुन्ज लाल केकड़, सी 124–ए ग्रेटर

			कैलास, नई दिल्ली।
14	कुसुम टूरिंग टाकीज, पटौदी		श्री डी.पी. कलानी सपुत्र श्री चन्दन मल निवासी पटौदी।
15	राज टूरिंग टाकीज, अडंगपुर		श्रीमती रत्न माला जैन, टी–6 ग्रीन पार्क एक्सटेन्शन नई दिल्ली।
जिला अम्बाला			
16	मधु पैलेस, यमुनानगर	(1)	श्री सहदेवा राधा
		(2)	श्री हरिदेव शर्मा (अवस्यक)
		(3)	श्री रणदेव त्यागी (अवस्यक) बेटे श्री मदन गोपाल भिवानी गोविन्दपुरी, यमुनानगर।
17	डिम्पल थियेटर, जगाधरी	(1)	श्री जय करण पुत्र श्री रण सिंह निवासी गांव नीमवाला, तहसील

			कैथल, जिला कुरूक्षेत्र।
		(2)	श्री खेम सिंह पुत्र श्री रणसिंह, निवासी गांव तारागढ़, तहसील कैथल, जिला कुरूक्षेत्र।
		(3)	श्री हरभजन सिंह पुत्र कैप्टल साधू सिंह, निवासी गांव तुम्बी, तहसील जगाधरी, जिला अम्बाला।
		(4)	श्रीमती बलबीर कौर, पत्नी राव नरसिंह दास, निवासी कैथल, जिला कुरूक्षेत्र।
18	पारस थियेटर, कुरूक्षेत्र		श्री कृश्ण चन्द सपुत्र श्री साधु राम, निवासी कुरूक्षेत्र।
19	नीलम थियेटर, कुरूक्षेत्र		श्री अनन्त राम सपुत्र श्री हरनाम सिंह, रणधीर सिंह सपुत्र श्री हुक्म

			सिंह, तुलसी दास सपुत्र श्री लोक राम अमीर चन्द सपुत्र श्री धन्ना मल, राम सिंह सपुत्र श्री मुगला राम, सभी निवासी कुरूक्षेत्र।
20	रंगशाला थियेटर, पुण्डरी	(1)	श्री निरंजल लाल सपुत्र श्री ठाकुर दास निवासी सीवन जिला कुरूक्षेत्र।
		(2)	अमर सिंह सपुत्र श्री राम विलास, निवासी फतेहपुर, जिला कुरूक्षेत्र।
		(3)	गौतम मनि सपुत्र श्री मातू राम, निवासी पुण्डरी।
जिला रोहतक			
21	लिबरटी थियेटर, रोहतक		मैसर्ज लिबरटी थियेटर, रोहतक।

22	बांगड थियेटर, रोहतक		मैसर्ज बांगड थियेटर, रोहतक।
23	कमला थियेटर, सांपला		मैसर्ज कमला थियेटर, सांपला।
24	मनोरंजन टूरिंग टाकीज, झज्जर		श्री हरि किशन शर्मा, झज्जर।

Employment of Graduates and Matriculates.

362. Ch. Dal Singh: Will the Minister for Development be pleased to state –

(a) the number of Graduates registered with the Employment Exchanges in the State as on 31-3-74;

(b) the number of Graduates as referred to in part (a) above registered in 1973-74;

(c) the number of graduates who got employment during the year 1973-74;

(d) the number of Matriculates registered with the various Employment Exchanges as on 31-3-74 in the State;

(e) the number of Matriculates registered in Employment Exchages in the State during the year 1973-74; and

(f) the number of Matriculates who got employment in the State out of those referred to in part (d) above in the year 1973-74?

श्रम मंत्री (कर्नल महा सिंह):

जैसा कि इस विभाग की नीति है, सूचना प्रति वर्श 30 जून तथा 31 दिसम्बर तक के समय की एकत्र की जाती है, इस आधार पर वांछित सूचना निम्नलिखित है?

(क)	16626	(as on 30.6.1974)
(ख)	19324	(1.7.1973 से 30.6. 1974)
(ग)	2473	(1.7.1973 से 30.6. 1974)
(घ)	53325	(as on 30.6.1974)
(ड़)	58797	(1.7.1973 से 30.6. 1974)
(च)	8008	(1.7.1973 से 30.6. 1974)

Import Licences for Stainless Steel.

363. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Industries be pleased to state –

(a) the district-wise names, addresses fo the persons and firms whoare holding imports licences to import stainless steel in the State;

(b) the district-wise quantity of stainless steel allowed on each licence to import steel in the State; and

(c) the date on which the licence to import stainless steel was given to the above mentioned persons and firms in the State?

उद्योग मंत्री (श्री हरपाल सिंह):

इसके संग्रहण/संकलन में लगने वाला समय तथा श्रम, दी जाने वाली सूचना की उगयोगिता के अनुरूप नहीं होगा।

Co-operative Societies under Liquidation

364. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the district-wise total number to Co-operative Societies under liquidation in the State;

(b) the district-wise total amount outstanding against the said Societies in the State; and

(c) the date, since when each of the Societies mentioned in part (a) above are under liquidation?

(Reply)

''तारांकित प्रश्नों की 6 जनवरी, 1975 की सूची में श्री दलीप सिंह राव, सदस्य विधान सभा के नाम दर्ज विधान सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 364 का उत्तर तैयार नहीं हुआ। ज्यों ही सम्बन्धित सूचना इकट्ठी हो जाएगी अपेक्षित उत्तर भेज दिया जाएगा।''

हस्ताक्षर

कार्यभारी मंत्री

सेवा में,

सचिव, विधान सभा,

हरियाणा, चण्डीगढ़।

अशाः क्रमांक 2एः क्यू:—सी (4)—75/78 चण्डीगढ़, दिनांक 3 जनवरी, 1975

Cause-way on Dohan River

365. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration fo the Government to construct a cause-way on Dohan river on Mohindergarh Bawania road, adn

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

राजस्व मंत्री (पण्डिल चिरंजी लाल शर्मा):

(ए) जी हां।

(बी) 1975–76 में, यदि धन उपलब्ध हुआ।

Loan or Grant to Municipal Committee Kanina

366. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state –

(a) the total amount of loan or grant advanced to the Municipal Committee Kanina for the construction of office of the Municipal Committee and construction of Market?

(b) the year in which the loan or grant was advanced to the Municipal Committee, Kanina;

(c) whether the said amount has been utilized;

(d) if not the reason therefore;

(e) the time by which the said office of the Municipal Committee and the Market is likely to be completed; and

(f) whether the instalments of the loan referred to in part (a) above are being regularly paid by the Municipal Committee?

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता):

(ए) 39000 रूपये का ऋण। अनुदान राशि प्रदान नहीं की गई।

(बी) 24000 रूपये का ऋण वर्श 1964–65 में तथा

15000 रूपये का ऋण वर्श 1966–67 में

कुल जोड़ 39000 रूपये

(सी) नहीं।

(डी) यह सूचना नहीं दी जा सकती है क्योंकि नगरपालिका का सम्बन्धित रिकार्ड इस समय अडीशनल सैशन्ज जज, नारनौल की अदालत में भूतपूर्व प्रधान नगरपालिका कनीना तथा सचिव, नगरपालिका, कनीना के विद्धध इण्डियन पीनल कोड की धारा 409 के तहत चलाए जा रहे है मुकदमें के सम्बन्ध में उक्त अदालत के कब्जे में है।

(ई) ज्यों ही इस एन.ए.सी. के पास धन राशि (ऋण राशि के अतिरिक्त) साधनों में से उक्त बिल्डिंगों के निर्माण हेतू उपलब्ध होगी।

(एफ) नहीं।

Construction of Kanina Gohra Road

367. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Kanina-Gohra road on which material is lying; and

(b) if so, the time by which the said road is likely to be constructed and completed?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरन्जी लाल शर्मा):

(ए) कनीना को गोहरा से सीधे मिलाने का कोई प्रस्ताव नहीं है, परन्तु कनीना नगर सड़क से गोहरा को सड़क द्वारा मिलाने का प्रस्ताव है जिसके कुछ भाग पर निर्माण सामग्री एकत्रित की जा चुकी है।

(बी) इस सड़क के मुकम्मल होने का समय धन की उपलब्धि पर निर्भर है।

Construction of Sehllong-Pota-Notana Road

368. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Revenue be pleased to state –

(a) whether there is any proposal under consideration of the Government to construct Sehllong-Pota-Notana road; and

(b) if so, the time by which it is likely to be constructed?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरन्जी लाल शर्मा):

(ए) सीहलोंग पोता सड़क पहले ही मुकम्मल है तो पोता से नोताना तक का भाग दोहरा सम्पर्क बनता है जिसका निर्माण नीति के अनुकूल नहीं है।

(बी) प्रश्न ही नहीं उठता।

Student in Government Higher Secondary School Kanina

369. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) the total number of students in Government Higher Secondary School Kanina, Tehsil Mohindergarh in the year 1974-75;

(b) the total number of students in Higher secondary Part I and Part II in the years 1972-73, 1973-74 and 1974-75 in the above said school;

(c) the total number of students passed in Higher Secondary Part I and Part II in the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74;

(d) the number of studnets passed in First Division and Second Division separately in

Higher Secondary Part I and Part II separately in the years 1971-72, 1972-73 and 1973-74;

(e) whether the number of staff at present posted in the said school is according to the sanctioned strength?

राजस्व मंत्री (पंडित चिरन्जी लाल शर्मा):

(ए) 1497

(बी)		1972-73	1973-74	1974-75
	भाग I	148	205	220 (मैट्रिक)
	भाग II	36	52	129

*वर्श 1974–75 में हायर सकैंडरी पार्ट–1 समाप्त होकर मैट्रिक हो गया है।

(सी)		1971-72	1972-73	1973-74
	भाग I	87	60	135
	भाग II	46	24	80

(डी)	1971-72		1972-73		1973-74	
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी
भाग I		3		20	1	11
भाग II		11	1	3		3

(ई) नहीं। अध्यापक वर्ग के 48 पदों में से निम्नलिखित 7 पद रिक्त पड़े हुये हैं:—

मास्टर	हिन्दी अध्यापक	ड्राईंग अध्यापक	एन.डी.एस. आई.
2	3	1	1

Government Higher Secondary School Mohindergarh

370. Rao Dalip Singh: Will the Minister for Education be pleased to state –

(a) the total number of students in Government Higher Secondary School, Mohindergarh;

(b) whether the staff at present posted in the said school is according to the sanctioned strength;

(c) the number of students in Higher Secondary Part I and Part II, separately in the years 1971-72, 1972-73, 1973-74, and 1974-75;

(d) the number of students passed in Higher Secondary Part I and Part II separately in the years 1971-72, 1972-73, and 1973-74;

(e) the number of students passed in the First Division and IInd Divisiion separately, in the years 1971-72, 1972-73, and 1973-74;

राजस्व मंत्री (पंडित चिरन्जी लाल शर्मा):

(ए) 1477

(बी) जी हां, सिवाये एक सोशल स्टडीज मास्टर तथा एक पंजाबी अध्यापक के पदों को जो कि रिक्त पड़ें हैं।

(सी)		1971-72	1972-73	1973-74	1974-75
	भाग I	233	253	425	*257 (मैट्रिक)
	भाग	108	142	96	154

	II				

*वर्श 1974–75 में हायर सकैंडरी भाग समाप्त होकर मैट्रिक हो गया है।

(डी)		1971-72	1972-73	1973-74
	भाग I	178	150	289
	भाग II	103	54	56

(ई)	1971-72		1972-73		1973-74	
	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी	प्रथम श्रेणी	द्वितीय श्रेणी
भाग I	3	26		18	1	29
भाग II		65		6	3	11

1969–70 के अनुदानों तथा विनियोजनौं से अधिक मांगों का पेश करना

15.00 बजे

Finance Minister (Sh. Ram Saran Chand Mital): Sir, I beg to present the Excess Demands over Grants and Appropriations of the Government of Haryana for the year 1969-70.

पटल पर रखे गए कागज पत्र

Home Minister (Sh. K.L. Poswal): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the notificaiton no. 282/HR/74, dated the 2nd December, 1974, containing the Delimitation Commission Order No. 28, regarding the Delimitation of Parliamentary and Assembly Constituencies in the State of Haryana.

Social Welfare Minister (Sh. Shyam Chand): Sir, I beg to lay on the Table a copy of the notificaiton No. G.S.R. 77/H.A./14/74 S 67/74, dated the 12th June, 1974, regarding the Haryana Children Rules, 1974, as required under section 67(3) of the Haryana Children Act, 1974.

राज्यपाल के अभिभाशण पर चर्चा

Sh. Gulab Singh Jain (Hissar): Sir, I beg to move that an Address be presented to the Governor in the following terms:-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the

Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 1st January, 1975."

Sh. Gulab Singh Jain (Hissar): Sir, the central theme of the Address of the learned Governor and the entire policy of the present Government, have been compressed in one sentence. The words -

> ".....the State Government has forged ahead in the pursuit of its primary objective of setting up of a Welfare State based on the concepts of economic justice and social equality."

This the policy, basic policy of the Congress party which runs the Government of Haryana today. The Members of the House know that in a democracy every political party has a programme, a policy and to achieve that programme and policy for the benefit of the people, every political party wants to form the Government. Now we have to see how far the present Government is carrying out the policy which the Party had put before it? In the election manifesto, the Party has placed a programme before the people and to execute and achieve that the present Government is functioning.

Sir, when Haryana came into being what was its condition? What was the economic condition? If I am not wrong even before 1947, before we attained freedom, this region was badly ignored for the reason that this part of the country, now known as Haryanal, was in the forefront of freedom struggle in 1857 and the Britishers had reason to ignore this region. Unfortunately, even after freedom this Region was being ignored and Haryana did not get the benefit

of first Three-Five Year Plans, which it should have. It was only of the 4th Five Year Plan that this regioin had the benefit of.

Sir, how far Haryana has developed during the last 6/7 years, since it came into being on 1st November, 1966 every member of this August House knows. One year of Haryana State was wasted, in what was called the dark period of the State. But after that the reigns of the Government came into the hands of the present Chief Minister and Haryana State has developed very fast. About what others think of Haryana, I may be permitted to quote from the 'Haryana Newsletter' published in a Paper not from Delhi, not from Haryana but from a far-flung State of West Bengal-Amrita Bazar Patrika, a well-known, well-established National Paper, which reads.

> "The Chief Minister has recounted his own efforts "to pull the State out of the morass of poverty and backwardness" and has paid tribute to the people for their wholehearted co-operation in taking the State forward. In his view the salvation of Haryana lay in increasing food production which could be stepped up only if there were more and more power and irrigation facilities. He claims that he has made 'concerted and systematic efforts" to extend these facilities and thus create the necessary infrastructure during the last six years. Because of those efforts, the State has made all round progress with the result that

Haryana, deficit State at the time of its formation in 1966, is now able not only to meet its own food requirements, but also contribute adequate quantities, of foodgrains to the Central pool. This is not a small achievement."

In the concluding paragraph, the Paper writes:-

"Even the critics of Mr. Bansi Lal agree that he has been making efforts to develop the State. The progress so far made is quite satisfactory. The face of rural Haryana has been completely transformed and today it is one of the most progressive States of India. According to the latest figures, the State's economy has recorded an annual average growth of 7.7 percent during the first four years of the Fourth Plan as against 2.97 percent of the country as a whole."

Mr. Speaker, Sir, such highly praise-worthy words have been said by a National Paper which are based on concrete facts. I may be permitted to narrate here another incident which took place recently. I had gone to Bombay and my host had hosted a party where all classes of people had gathered there. Since some of the people had occasion to visit this State and were very much impressed by the rapid progress which this State had made, they asked me as to what is the miracle in the hands of your Chief Minister by which, within a short span of six years, he has been able to build such a politically, economically and socially strong State

where all sorts of developments are there. I stated that this was because of eight factors. First was the able guidance of our worthy Governor to the Government. We are fortunate enough in having in the person of Mr. B.N. Chakravarty, such a learned, experienced and considerate Governor. Second was the stability of the Government. Stability of the Government is a great factor. Third was the hard work of our people. Our people are very much hard working. They questioned me, if it were so, why were they not progressing previously ? I replied ; the reason was that necessary infra-structure was not provided to the people of State. So previously the progress was very slow but now progress was speedy because of hard work of the people. The fourth factor was that our officers are dedicated to their jobs. No Government can progress unless the Officers of the State are dedicated to their mission and that mission should be to serve the people. Our officers are very much dedicated. Next reason was that there is absolutely team work in the Council of Ministers, solid backing of the Congress Party to the Government, absence of political interference in the day-to-day administration and last of all was-which was very surprising to them also-the impatience and asthama of our Chief Minister. Our Chief Minister suffers from Asthama. An asthama patient can not sleep. So when our Chief Minister suffers from asthama attack he cannot sleep but his brain only works. He then thinks about the problems of the State and how to develop the State. He being impatient, what he thinks in the night, gives effect to in the morning by giving directions to the officers accordingly. That is the basic root cause of the rapid progress of Haryana. So this is how our Haryana State has development. This is my submission.

Now, Sir, we have to seen whether the objective of having a welfare State based on the concept of economic justice, social welfare and equality has been achieved or not. Sir, as the hon. Members are aware Haryana is a State whose eighty per cent populattion is agriculture based. Eighty percent of our population live in the villages and they depend on agriculture for their economic uplift and then no State in the country can develop unless it develops its industry also. So to have faster development of any part or any region of the country i.e. any State, it is necessary that an infra-structure should be created or should be constructed for the agriculture development as well as for the infra-structure ? First of all, we must have more water for our fields; more power both for agriculture as well as for Industry. As you know, Sir, Haryana don't have much mineral wealth. We are deficient in it. So to attract entrepreneurs we must give them something which they don't get in other parts of the country. And I may quote an instance, Sir, Recently, Sir I had the occasion to discuss with certain industrialists of Calcutta as to why they prefer to come to Haryana. Sir, I was surprised when they told me "We know that there is power shortage; we know that Haryana is not a consuming market; but since there is stability in the Government there; there is no law and order problem there and the labour management relations are unique, so we want to come to Haryana, because the industry cannot flourish where there are occasional strikes." Where there are occasional strikes the industrialist cannot sleep with peace because of unrest in a particular part of the country and so is the industry concerned with the stability of the Government. They also told me that there is absence of red-tapism, which is a greatest thing. The industrialists want speed. They want

their work to be done speedily. All these factors go a long way for helping the industrial growth of the State. We have also to see whether the infra-structure has been created or not and for creating infra-structure, your honour, we must first give irrgation facilities. So we have to see what steps the Government have so far taken for providing more irrigation facilities. Mr. Speaker, Sir, we do not have any rivers in our State. We are very much unfortunate in this respect. But once we have stated that we have created water without any more water, the statement appears to be funny on the face of it. But it is a hard fact because with the same quantity of water, Mr. Speaker, Sir we have irrigated more area. How ? Our Government thought and they thought very quickly and deliverated as to how to increase the irrigation facilities there being no more water and came to the conclusion that they must stop seepage of water i.e. wastage of water by seepage. So for stopping seepage, the Government took up the alignment of our canals. They have started making the outlets pucca and thereby a lot of water is saved.

Again, Mr. Speaker, Sir, today during the question-hour, the State Minister stated as to how much more hectares of land is being irrigated by the augmentation canal. By creating infra-structure, by taking electricity to every village, more tubewells have come up. If we compare the figures as to what was there in the State when it came into being from 1947 when freedom came till 1966 when Haryana came into being-what was the number of tubewells, every Member of the House is well aware that is was less than forty thousand, which number today has gone to more than one lakh i.e. one lakh fifty thousand-we will find that within more then twenty years,

1947 to 1966, quite a long period, we will see that the progress was very slow. This region was being ignored. But today the progress is faster. Because of more tube-wells, Mr. Speaker, Sir as is known to everybody in the State as well as out of Haryana, the very State which was deficit in food production, which had to look to the Centre for the allotment of food-grains for its population, today is contributing to the Central pool. Last year even though there was drought, we contributed to the Central Pool. Last year I happened to go to Rajasthan and the Finance Minister of that State met me there. He asked me because there is a great scarcity in that State and they must depend at-least upon their bordering State of Haryana food-grains, of course a part of it goes to that State in an un-authorised manner i.e. it is smuggled out and this also affects after all the people of this country and they were keen to know as to whether Haryana will be able to fulfil its promise to contribute to Central pool. Now everybody know that Haryana is the second State in the country in contributing to the Central pool. After Punjab, Haryana comes next even though we are a very small State

Then, Mr. Speaker, Sir, for creating more irrigation facilitites we have taken up lift schemes. The area which could never dream in their life the people there could never dream of getting water for their fields, will get water. It is a miracle. Only we used to hear that Israel is a country where deserts have been irrigated. Today people from other States come to see that miracle being performed on the soil of Haryana. As every hon. Member of this House knows, after the completion of Jawahar Lal Nehru canal, after the completion of other lift projects which are in hand, there will not be any part of the

State which will not be fully irrigated and our Government is taking steps to go faster with these projects. If we look to the allocation made in the first year of the Fourth Five Year Plan, it would be clear, Sir, that the Government is keen to create an infra-structure and also to look to the necessities of those classes of the society which deserve the greatest attention, I mean, the agricultures' class. Even in the Fifth Five Year Plan, if I mistake not, sixty percent of the plan outlay is reserved for irrigation and electricity because today we have to depend more and more on tube-well irrigation in Haryana. We cannot get water from the rivers easily because for that we have to depend upon settlements with other States and unless they agree and unless the Centre intervenes we cannot get more water. So we have to make use of the sub-soil water which we have in Haryana. Recently, Sir, while answering a question in the House it was stated that the Government is making an experiment as to how to make use of the brackish water for cultivation purposes and the Government is an experiment and the Haryana Agriculture University has been directed to find out as to what quantity of brackish water can be mixed with canal water so that it may be useful for agriculture. If that experiment is successful, Sir, the day will come when the agriculture will not clamour, will not complain that he is not getting sufficient water.

Before coming to the subject of electricity, I may state a few figures about the increase in production on the agriculture side. When Haryana came into being, the production of foodgrain in 1966-67 was only 26 lakh tonnes while in 1972-73 it was more than 40 lakh tonnes. The production of sugar was 5 lakh tonnes while now it is more

than 6 lakh tonnes. As for cotton, the production then was 2.88 lakh bales and now we are producing more than four lakh bales and similarly we are producing much more oil seeds now than what we were producing at the time when Haryana came into being. The area under irrigation has also greatly increased. When Haryana came into being, the total irrigated area under principal crop was 1188000 hectares and now it is 1914000 hectares. How we have been able to achieve all that? It is because the Government is making all out efforts to increase the quantum of water by taking whatever steps they have to take and adopting various means of providing water for irrigation. Another factor for the increase of agricultural produce is the use of fertilisers. What was the quantity of fertilisers that we were utilising, which our farmers were using, when Haryana came into being? The use of urea was only 1731 tonnes in 1967-68 while in 1972-73 it went upto 115037 tonnes. It had no proportion. I cannot even count the percentage. It practically rose from nil to a lakh lonnes. Similarly, the use of calcium ammonium nitrate was 55618 tonnes in 1966-67 and it doubled in 1972-73. That shows that our farmers are using more and more of fertilisers. How? It is because our Government is providing facility to them, financial facility and know how. Our Haryana Agriculture University has an extension scheme. We are providing Inspectors in all blocks who go from village to village and from door to door explaining the use of the modern agricultural implements, modern means of agricultural production and the use of fertilisers and improved varities of seeds. All this has resulted n larger and greater production in the agriculture sector. There is much hue and cry, Sir, about the paucity of electricity. And, I agree that there is shortage of electricity.

But does it mean that we have started producing less of electricity ? Absolutely not. We are producing more than before but the consumption of electricity has increased and that is a sign of prosperity for the State. Which ever State uses more electricity is more prosperous and our Government is quite conscious of the fact that we have to produce more electricity. Sir, recently, it was stated before the House as to how many schemes we have in hand to increase electric production. Our one unit of 60 Mw capacity of Faridabad plant has already been commissioned and the second unit is likely to be commissioned very shortly. There is also a plan to have a third stand by unit because our Government knows that in thermal production of electricity unless there are three plants, two plants cannot work and there must be one stand by unit. The Government is conscious of it. Our Panipat Thermal Plan is also under construction. It will have two units of 110 MW capacity each and I am told that there is also a scheme to have a third unit as a stand-by ultimately. Then there are a number of other schemes by which the Government wants to increase the production of electricity and after we get electricity from Ravi Beas project, I think, the shortage of electricity will not be felt by the people of the State. Sir, I may, for the benefit of the members of this House, state some figures to show as to how much electricity is being used in the State. When Haryana came into being there were only 1312 villages which were electrified. Now there is 100% electrification and all the 6731 villages have been electrified. The consumption of electricity has increased tremendously. In 1968 the total number of connections for domestic purposes was 280376 while today it is 436276. On commercial side also the connections have increased from 67326 to 93177. On

agriculture side, these have increased from 45370 to 116882. The number of industrial connections has also increased from 12608 to 21931. This shows that Haryana is developing fast because the increase in the number of connections means that more and more people are being benefited by the use of electricity. Sir, in the address of the worthy Governor reference has been made to electrification, augmentation of irrigation facilities, provision of drinking water to rural areas. We have to see as to how far the State has progressed in this respect also? If we take the figures of villages that have been provided drinking water facilities, it is an eye opener. Before freedom Haryana languished for drinking water. There were areas where people had not seen pure drinking water what to say of using it. There was area where adulteration was made in the drinking water. It looks surprising but I know that in Kalawala Mandi the water carrier used to mix on bucket of well water with one bucket of canal water. But now we are supplying filtered drinking water to a large number of villages and a number of plans are in hand.

The number of villages covered by rural drinking water supply scheme from 1954 to 1st November, 1966 was 170 whereas the total number of villages covered in the State upto March, 1974 is 703. we have scheme for 22 village to be provided with this facility during this year. So we are much ahead in this respect also.

Next I come to communications. As I said at the outset, for development in any State, the communications have a great hand. Unless the entire State is connected by means of roads/communications, the economic development

cannot be so speedy. The farmers have to bring their produce in the markets. They must have roads to bring their produce to the area of sale. When Haryana came into being, hardly this facility was available to the villages. As every member of this Hon. House knows that we had planned to connect every village with pucca road and went ahead with this scheme but we had to slow down this work to give priority to irrigation and power. But inspite of that. Sir, our achievement on this side cannot be said to be mean. We are far ahead of other States in the respect. Our road mileage has greatly increased. When Haryana came into being the road length was about 5000 KM but now it is more than 12000 KM. This shows that in the matter of communications the State is quite alive to it and we are making all out efforts to increase our road mileage as much as possible. It is also clear that not only urban areas are being connected with roads but also the rural areas.

In the matter of education also the State has made tremendous progress. I would quote figures to show how many schools and colleges have been opened. Before freedom, I can say, it is a matter of great shame that during the British regime there was not a single degree college in whole of the area, which is today known as Haryana and even after the attainment of freedom the progress on educational side was slow. The number of Arts and Science Colleges in 1967-68 was 42 whereas it is 87 today. The number of students in schools and colleges has increased and the number of schools upgraded in the State during the last 6 years is an eye-opener to everybody. Not only in general education, but the number of students in technology, dairy sciences, Vety. Agriculture and engineering is increasing day by day.

The State is progressing economically. We are taking steps for the amelioration of the conditions of the weaker sections of the society also. We are looking to the social welfare side of the State activities.

In the matter of civil supplies, I submit, we have opened fair price shops practically in every village in order to give more facilities to our agriculturists. It will be seen that in the neighbouring State the procurement of rice is 86% whereas in our State it is 90% which has given increased impetus to production and financial benefit to our agriculturists. Last year we exported 33000 quintals of rice to foreign countries thereby we earned valuable foreign exchange to the tune of Rs. 10 crores. The State also made a profit of Rs. 4 crores. Again, out distribution system is said to be one of the best in the country. There are lesser complaints about the non-availability of essential goods at our fair price shops. That is why use of MISA in our State is missing. There is hardly any case of hoarding or black-marketing in our State. That speaks highly of our development in the State.

Another factor for the development of the State is labour relation. As I said at the very outset that people from other States are very keen to come to our State and start industries and for that I wish to give credit to the labour leaders of the State also. As a matter of fact I must give credit to my hon. friend, Mr. G.C. Joshi, who has been instrumental in keeping relations between the labour and management very cordial. He has been making all-out efforts towards that end. For that reason the number of lock-outs and strikes is the minimum.

Another point, Sir, is the welfare of the Scheduled Castes and Backward Classes. On this side, Sir, the Haryana State has taken special steps. To ameliorate the condition of this section of the society. Sir, the various steps which the Government has taken for the welfare of the Schedulesd Castes and Backward Classes, I may enumerate briefly that most of the surplus and the evacuee land is sold to the Harijans in restricted auctions; Children belonging to the Scheduled Castes and allowed free ship at all levels and they are allowed scholarships also. Special classes are being held for giving them training to compete in competitive examinations. There are centres at Ambala and recently two other Centres have been opened, one at Bhiwani and another place and more and more efforts are being made every day. Under Section 226 (b) (i) of the cooperative Societies Act, one seat is reserved for members of Scheduled Castes in the managing Committee of each cooperative society. This is a very noble thing, Sir, that Harijan members are nominated on cooperative societies on which otherwise they would not come by election. A State level cell was constituted in January, 1973, under Chairmanship of the Chief Minister to review the performance with regard to the welfare of Scheduled Castes and Backward Classes of the State. Sir, reservation in services is an important factor and Haryana has made a provision for reservation not only in Government services but in all the Corporations which are semi-government bodies. There is reservation in those Corporation also which is nowhere in other States, if I mistake not. Sir, you won't find this policy in other States, which is because of our energetic Social Welfare Minister, Ch. Shyam Chand, who always thinks for the Welfare of the Harijans and this thing is upper-most in his mind.

Because of him and because of the dynamic personality of the Chief Minister, the Harijan Welfare work is being speedily done and more and more care is being taken of this section of the society.

There is a new scheme for providing tailoring training to the Harijan widows and they are also given machines, Sir. Not only training is given but the tool to work with is also given. Atta depots are being opened in every mohalla where-ever there is a demand for it. Because it is a week section it is being seen that they get atta conveniently and freely.

There is another section of the society which is not being ignored and which is being looked after properly and that is the destitutes in the State. There are special institutions to look after their welfare and the Government is spending a lot of money for their welfare also. So there is all round progress in the State which was at one time being considered an ignored area, where Government servants would not like that they be posted before 1947 and even before Haryana came into being. Now every body wants to be in the State because there are all types of facilities here. The State is developing fast and the Address of the Governor clearly depicts all these things and has given clear indications of the achievements of the Government during the last six years, during the fourth five year plan and the steps which the Government proposes to take for the amelioration of he condition of the people and for achieving the noble object of having an economically strong welfare State.

Sir, the State, as I have submitted has developed and there is no doubt about it. But there are certain elements in the State which only criticise and they don't act for the benefit of the State. I am told that there is a clamour that there should be more and more employment. Who says, there should not be? But unless we change out outlook towards employment, it cannot be achieved. We have spread more and more education. But if we take the purpose of education as service only, then naturally the State cannot provide services to all matriculates even though they may be third class. Why should we produce third class matriculates? Our teachers don't work because some of our brothers in the State believe in agitations. They use the teachers for agitational purposes. They use the boys of schools and colleges for agitational purposes and they ignore their classes, and education. Since they ignore their education, they don't achieve higher numbers. They don't get higher divisions and naturally they cannot expect to have employment. They are not properly fitted for this purpose. If we look to the interests of the students more rather than taking them to agitation .....

चौ. दल सिंह: जैन साहब, ऐसा कब से है?

श्री गुलाब सिंह जैन: यह तो आप ही बतायेंगे। And again, Sir about employment I may state one thing more that so for as our engineers are concerned I think there is hardly any engineer who is unemployed. Even we are short of Overseers. Recently we wanted some Overseers and S.D.Os. (Civil) for our Improvement Trust, Hissar, when we advertised, we could not get enough. People from outside our State came. We do not have that slogan "Sons of the soil". We do not

believe in it because the entire country is one. We cannot go with that epithets. So, Sir here again if we take to the unskilled labour, as you know, Sir more and more people from outside come. We have abundance of Rajasthan labour. We do not get sufficient labour for work for out projects belonging to Haryana. We have taken industry to our villages. We have a project Officer to plan industry to be started near the villages and we give special facilities for them. This is why if we take the number of labour in our industrial concerns. I had the occasion to study this subject recently and I was surprised to find more than 60 per cent of the industrial labour of Haryana is from other States. The labour force does not belong to Haryana. I had discussion with the industrialists on this point and they told me that Haryana labour do not want to come to work in the factories. They want to work only in the villages. They do not want to leave their villages because they are unemployed seasonally. There are drought periods and there are periods when there are no agricultural activities. For that period they want employment otherwise they want to remain in their own villages and work in their own villages. It is why the State Government wants to provide them work in their villages also. The industries are, as I said being started nearer to villages so that the village people who are unemployed have not to move to far of places in search of employment.

So, Sir, looking from all angles of view, it would be seen that in this Address the worthy Governor has drawn the attention of this House to the all sided achievements which Haryana has made so far and the steps for further achievements which the State Government want to take for the amelioration of the condition of the people and the economical

development of the State. And so, Sir, I would urge that we send a motion of thanks to the Worthy Governor.

Thank you.

श्री गिरीश चन्द्र जोशी (यमुनानगर): अध्यक्ष महोदय, मेरे मौजिज दोस्त श्री गुलाब सिंह जैन ने आदरणीय राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर धन्यवाद का प्रस्ताव रखा, मैं उनका अनुमोदन करने के लिये खड़ा हुआ हूं। राज्यपाल महेादय का अभिभाशण स्पश्टता का अभिभाशण है। उन्होंने जो भी बातें कही हैं, वह सचाई की कही हैं। जहां उन्होंने, इस एक साल के दौरान जो विकास हुआ है, विकास के काम हुये हैं, उनके बारे में बताया है, वहां जो गतिरोध पैदा हुये, रूकावटे आई और कमियां हुई, उनका वर्णन भी किया है। उन्होंने सही नक्शा पेश किया है और जहां उन्होंने विकास के बारे बताया, वहां यह भी बताया, और यह बातें भी सामने रखीं कि क्या–क्या दिक्कतें पेश आई और क्या–क्या परेशानियां आई। इसके साथ–साथ उन्होंने एक टाई बाउंड प्रोग्राम भी दिया है कि हरियाणा कितने टाईम में किन किन मदों को पूरा कर पायेगा। तो यह सच्चाई की बातें हैं, असलीयतकी बातें है जो राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में बताई हैं। मैं इस पर कोई ज्यादा समय नहीं लूंगा और उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जिनका जिक्र मेरे दोस्त ने अभी बड़े विस्तारपूर्वक आंकड़े दे कर किया है। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपने देश के इतिहास के ऊपर कुछ बोलूं और कुछ बैकग्रांड पर रोशनी डालूं। हमारा देश 1947 में आजाद हुआ और किन

वजूहात से आजाद हुआ, यह बात किसी से छिपानी हुई नहीं है, सब जानते हैं। आजादी आने के बाद जो हमारा संविधान बना, उस में हर वयस्क को अडल्ट फ्रैंचायज के आधार पर जो भी 21 साल की आयु और इससे ज्यादा का था, चाहे मर्द था, चाहे औरत थी, जवान था या बूढ़ा था, गरीब था या अमीर था, छोटा ाि या बड़ा था सकको मताधिकार दिया गया। डायरेक्टिव प्रिंसीपल्ज के अनुसार हर एक को कर एक अधिकार दिया गया। स्पीकर साहब, एक बात मैं स्पश्ट तौर से आपके सामने रखना चाहता हूं कि अधिकार तो सबको सब मिल गये हैं। लेकिन हमारे देश में अभी तक नैशनलल डिसिपलन नाम की चीज नहीं आई है। एक मुहावरा कहा जाता हैः Discipline without freedom is slavery and freedom without discipline is chaos. और हमारा देश सदियों तक गुलाम रहा, चाहे वह मुगलों की गुलामी थी, चाहे ब्रिटिश राज की गुलामी थी। इस गुलामी से हमारा देश 1947 में मुक्त इहुआ और उसके बाद जो हमारा संविधान बना उसमें सबको सारे अधिकार दिये गये। मालिक को अपनी फैक्टरी बंद करने का अधिकार और मजदूर को हड़ताल करने का अधिकार मिल गया और वह अधिकार कलैश करते रहे आपस में लेकिन हमने डिस्पिलन को नहीं समझा, डयूटी को नहीं समझा और इस बात को नहीं समझा कि अधिकार के साथ–साथ हमारी डयूटीज भी हैं। पुलिटिकल फ्रीडम के लिहाज से तो हम आजाद हो गये, लेकिन इकनामिक फ्रीडम के लिहाज से जो हमें मेहनत करनी चाहियें थी, उसमें हमने पूरा योगदान नहीं दिया। इस बारे में मैं आपसे कुछ

ऐतिहासिक बात कहना चाहता हूं। जहां तक इस आर्थिक विकास में गतिरोध आने की बात है, इस सम्बन्ध में सबसे पहले सबसे ज्यादा संकट 1962 में शुरू हुआ जब चीन ने हमारे ऊपर एग्रैशान किया। हम उस वक्त तैयार नहीं थे ओर डिफैंस की तरफ ज्यादा पैसा न लगा कर विकास की तरफ लगाते थे। उसके बाद डिफैंस पर ज्यादा खर्च होना शुरू हुआ। इसके बाद पहले 1965 में और फिर दूसरी बोर 1971 में पाकिस्तान की तरफ से एग्रैशन हुआ। बंगलादेश के मामले के बारे में सब को पता है कि किस तरह से हमारा देश उसमें से गुजारा और क्या क्या हालात हुये। तो इन बातों से आर्थिक विकास में गतिरोध आया और संकट पैदा हुआ क्योंकि डिफैंस पर भारी मात्रा में रूपया खच्र होना शुरू हुआ और आर्थिक विकास के लिये संकट पैदा होना शुरू हुआ। इसके साथ–साथ कुदरत ने भी अपना पार्ट प्ले करना शुरू कर दिया है। देश में कहीं तो भारी बारिशें होती थीं और कहीं पर अकाल पड़ता था। तो इस तरह से हम कुदरत की मार से भी वंचित नहीं रहे। देश में जो यह हालात पैदा हुये उनका असर हरियाणा पर भारी पड़ा और यह पड़ना भी था क्योंकि हम भी तो इस देश का पार्ट हैं। लेकिन इन तमाम संकटों का मुकाबला करते हुये भी हरियाणा विकास के मार्ग पर अच्छी गति से चला। खासतौर पर जबसे यह मौजूदा सरकार आई और चौ. बंसी लाल जी ने इस हकूमत की बागडोर सम्भाली, विकास की गति में बहुत तेजी आई और एक बात को मैं अब दोहराना नहीं चाहता क्योंकि वह अब पुरानी हो चुकी है कि हरियाणा के हर गांव में पूरे तौर पर

बिजली पहुंचा दी गई। 70 प्रतिशत गांव को सड़कों के साथ मिला दिया गया बगैरा बगैरा। बाद में कुछ गतिरोध आया और यह क्यों हुआ? इसकी वजह यह है कि हरियाणा केन्द्र से पैसा लेता था क्योंकि हरियाणा के पास अपने जराये ऐसे नहीं थे जिनसे हम अपने पांव पर खड़ा हो सकते। हमरी बदकिस्मती की बात यह रही कि हमारे पास कोई नदी नहीं है। एक नदी है जमना हो हरियाणा और यू.पी. का विभाजन करते हुए चलती है। पहले यहां कोई नहर नहीं थी लेकिन अब कुछ बनी हैं। हरियाणा की अपनी कोई नदी न होने की वजह से हमारे पास पानी कम रहा और बिजली में भी हम आत्मनिर्भर नहीं हुये दूसरों के डिपैडेंट रहे और अब भी हैं चाहे भाखड़ा बोर्ड के हैं, डेसू के हैं और चाहे राणा प्रताप सागर के हैं, पहले भी हम उन पर डिपैंडैंट रहे और अब भी हैं। हरियाणा ने अपने बिजली के जराय बाद में धीरे धीरे पैदा करने शुरू किये और कर रहा है जैसा कि राज्यपाल महोदन ने भी अपने अभिभाशण में उल्लेख किया है कि फरीदाबाद का 60 मैगावाट का प्लांट तैयार हो गया है जो एक लाख 80 हजार यूनिटस बिजली तैयार करना शुरू करके 10 लाख यूनिटस तक पहुंचेगा। दूसरा प्लांट कुछ ही महीनों के बाद चालू हो जायेगा। इसके साथ ही साथ 110/110 मैगावाट के दो प्लांटस पानीपत में लगाने के लिये तेजी के साथ कदम उठाये जा रहे हैं और 1976 में जब हमें ब्यास प्रोजैक्ट से हमारा शेयर मिल जायेगा तो उससे मौजूदा संकट को दूर करने में काफी मदद मिलेगी। राज्यपाल महोदय ने यह आशा व्यक्त की है कि 1977–78 तक यह जो बिजली का संकट है काफी

हद तक दूर हो जायेगा और हम अपने पांव पर खड़ा होने के योग्य हो सकेंगे। यह चीज उन्होंने टाइम–बाउंड कर दी है और एक सही चीज हमारे सामने रखी है। अध्यक्ष महोदय, हमारा देश खेती प्रधान देश है और अपने इस खेती प्रधान देश के अन्दर हमारा यह हरियाणा खेती प्रधान प्रदेश है। तो हरियाणा में जहां बिजली की इन्डस्ट्री के लिये जरूरत है वहां खेती के लिये भी बिजली की सख्त जरूरत है क्योंकि हम बिजली के जरिये ही पानी का जरिया पैदा कर सकते हैं और इसकी वजह यह है जैसा मैंने पहले निवेदन किया कि हमारे पास हमारी अपनी नदी कोई नहीं है जिससे हम कैनाल निकाल सकें। एक ही नदी है जोकि हरियाणा और यू.पी. के बार्डर पर चलती है और इन दोनों प्रदेशों का विभाजन करती है। वहां उस पर अगर डैम बनाये तो यू.पी. अगर झगड़ा कर दे तो दो प्रदेशों में टकराव की बात सामने आती है। हमारे पास तो सिर्फ सब–सायल वाटर ही है जिसे इस्तेमाल कर सकते हैं ओर सब–सायल वाटर का हमारे पास बहुत खजाना है, बहुत रिजर्वायर हैं जिसे अगर एक्सपलायट किया जाये तो हमेशा के लिए हमारे पानी की कमी पूरी हो सकती है। यह पीन हम टयूबवैल्ज लगाकर ही निकाल सकते हैं जिसके लिये बिजली की जरूरत है। तो खेती को सहारा देने के लिये हमारे पास एक ही सहारा है वह है बिजली का। यह मानी हुई चीज है कि हरियाणा खेती प्रधान प्रदेश है और इसकी मेन आबादी खेती पर निर्भर करती है और ज्यादा लोग गांवों में देहात में बसते हैं। शहरों में जो लोग जाते हैं और रहते हैं वह देहात से ही रोजी के लिये

जाते हैं और वहां मजदूरी करते हैं। देहात के साथ उनका लगाव है और खेती के मौका पर देहात में जाकर काम करते हैं। हम देखते है कि हमारी फैक्टरीज से सोइंग सीजन के वक्त मजदूर लोगे चले जाते हैं और देहात में जाकर खेती का काम करते हैं। इसलिये इस बात को ध्यान में रखते हुये हम कह सकते हैं कि हरियाणा की तरक्की, हरियाणा का विकास और इसके लोगों का आर्थिक विकास तीन चीजों पर निर्भर करता है। प्राईमरी एग्रीकल्चर, सैकन्डरी इन्डस्ट्रीज और टरसरी सर्विसिज सैक्टर यानी कम्यूनिकेशन, बैंक्स वगैरा इसमें आते हैं। इन सैक्टर्ज का आपस में तालमेल हमारे आर्थिक विकास को आगे ले जा सकता है और विकास को ऊंचा ले जा सकता है। लेकिन

16.00 बजे

यह सब करने के लिये हमें हरियाणा में सैकंडरी टरसरी के बनिस्बत प्राईमरी सैक्टर को प्राथमिकता देनी चाहिये। इन तीनों में सबसे पहले प्राईमरी सैक्टर को प्राथमिकता दी जाए क्योंकि यह एग्रीकल्चर सैक्टर है और हरियाणा खेतीहर प्रदेश है। हमारे राज्यपाल महोदय ने अपने अभिभाशण में कहा कि सैकंडरी सैक्टर की कौस्ट पर, फैक्ट्रियों की बिजली पर कट लगाकर फैक्ट्रियों का हफ्ता–हफ्ता क्लोज करके बिजली बचाकर प्राईमरी सैक्टर को, एग्रीकल्चर सैक्टर को बिजली दी ताकि सोइंग सीजन में किसानों को एडीशनल पानी मिल सके। पूरी मिकदार में पानी मिलकर के खेती में काफी पैदावार हो, इस उदेश्य को पूरा करने के लिये

उद्योगों से बिजली काटकर खेती के लिए सरकार ने दी। आप देखें, हरियाणा जब वजूद में आया तो हरियाणा के पास क्या था? यह दोहराने वाली बात नहीं है, कई मरतबा सदन में कही जा चुकी है कि हरियाण के पास खाने के लिए अनाज नही था और सैन्टर से अनाज लेते थे। आज वही हरियाणा है जो अपनी जनता को अनाज देने के बाद सैन्ट्रल पूल में अनाज देकर इस देश की जनता को अनाज दे रहा है। यह तारीफ की बात नहीं तो और क्या है? यह हमने सोचना है और असलीयत को नजरअन्दाल नहीं करना चाहिए। लेकिन जो तरक्की हमने की है, हमें इससे सन्तोश नहीं है, हमने इससे आगे बढ़ना है, हरियाणा के पास काफी सरप्लस लैंड है जो कल्लर है। इस प्रकार की जमीन है जो कल्टीवेशन के काबिल नहीं हैं इस जमीन को एक्सप्लायट करने के लिए हमारी सरकार पूरी तरह जागरूक है, सवेग करवा रही है, कारपोरेशन बना रही है और भी कई किस्म के उपाय कर रही है। इस महत्वपूर्ण कार्य का करने के लिए पानी का दरकार है, बिजली की दरकार है। हरियाणा में बिजली की खपत 70–75 लाख यूनिट है और इसमें से 35 लाख यूनिट एग्रीकल्चर सैक्टर को जानी है और इतनी ही बिजली इंडस्ट्रियल सैक्टर को चाहिए। लेकिन आप देखें हमें मिलती कितनी है? देहली इलैस्ट्रिल सप्लाई अंडरटेकिंग, राणाप्रताप सागर, भाखड़ा मैनेजमैंट बोर्ड तथा बदरपुर थर्मल प्लांट से कुल मिलाकर 40 लाख यूनिट से भी कम बिजली मिलती हैं हरियाणा की आवश्यकता को पूरा करने के लिए 35 लाख यूनिट का शार्ट–फाल है। कैसे गुजारा हो सकता है? गुजारा करने के

लिए इंडस्ट्रीज पर कट लगानी पड़ती है और अगर इंडस्ट्रीज को रोक दिया जाए तो मजदूरों को फैक्टरी में आने से रोकना पड़ता है। किसी फैक्टरी में एक ि ाफ्ट लगानी पड़ती है, किसी में दो लगानी पड़ती हैं और इस तरह से लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ता है, लेकिन यह आवश्यक है क्योंकि अनाज पैदा करना है। अगर अनाज न पैदा हो तो मर्द भोजन कहां से करेगा? बिना भोजन तो भजन भी नहीं हो सकता। इसीलिए हम कहते है कि अनाज पैदा नहीं होगा तो मनुश्य खायेगा क्या? क्या लोहा, सीमेन्ट खायेगा? अनाज पहले मिले तब इन्सान काम करने के काबिल हो सकता है। हरियाणा में उद्योगों पर बिजली की कट होने के बावजूद भी वर्करों के अन्दर खलबली नहीं है क्योंकि हरियाणा का मजदूर समझदार है, वफादार है। वह समझता है कि उसका भला किस बात में है।

दूसरी बात राज्यपाल महोदय ने यह बताई कि सरकार की नीति क्या हैं उन्होंने बड़े दृढ़ शब्दों में कहा कि हरियाणा सरकार आर्थिक न्याय तथा सामाजिक समानता के सिद्धांतों पर आधारित लोक–कल्याणकारी राज्य की स्थापना हेतू अपने प्राथमिक उदेश्यों की पूर्ति की दिशा में आगे बढ़ी है। आर्थिक न्याय के क्या मायने है? आर्थिक न्याय के मायने हैं कि हमारे प्रदेश का आर्थिक ढ़ाचा इस तरीके का हो जिसमें आर्थिक विकास के रूप में हम हर एक वर्ग के साथ न्याय करते चलें, किसी वर्ग को पिछड़ा न छोड़ें। आप देखें हमारे यहां कई प्रकार के वर्ग हैं, जातियों के

वर्ग हैं, पिछड़े वर्ग हैं, पद–दलित वर्ग हैं, मजदूर वर्ग हैं, बलनरेबल सैक्शन आफ सोसायटी है जिनकी फिक्स–पे है, इनको सरकार की तरफ से प्रोटैक्शन मिलनी चाहिए। गवर्नमैंट सर्वैंटस हैं, फैक्ट्रीज मैं काम रने वाले लोग हैं, एग्रीकल्चर लेबरर्ज, लैंड–लैस लेबरर्ज हैं, इस प्रकार के और भी कई वर्ग हैं जिनको न्याय मिलना चाहिए जोकि आज मिल भी रहा है। सामाजिक समता का अर्थ यह है कि समाज के अन्दर एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं होना चाहिए, सबको एक समान समझना चाहिए। राज्यपाल महोदय ने सरकार का जो सिद्धांत अपने अभिभाशण में बताया है, सरकार इस पर पूरी तरह चल रही है। इसके आगे चलकर राज्यपाल महोदय ने नौ–सूत्री प्रोग्राम दिया है जिसको सरकार ने प्राथमिकता दी। नौ–सूत्री प्रोग्राम में राज्यपाल महोदय ने कहा कि सरकार ग्रामीण विद्युतीकरण, सिंचाई सुविधाओं के संवर्धन, देहाती इलाकों को पीने के पानी की व्यवस्था, संचार व्यवस्था, चिकित्सा उपचार, शिक्षा, गृह निर्माण तथा रोजगार और अनुसूचित जातियों तथा पिछड़ी श्रेणियों के कल्याण को प्राथमिकता दी गई है। अध्यक्ष महोदय, मैं इजराईल भी गया, इंग्लैड भी गया और जर्मनी भी गया। आप ताज्जुब करेंगे कि जब मैंने हरियाणा को देखा तो मुझे इजराईल की याद आ गई। एक तरफ इजराईल था और दूसरी तरफ हरियाणा का इलाका जो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं। एक तरफ खदर का इलाका, बागड़ का इलाका और पहाड़ी इलाका जिसमें कुछ भी नहीं होता। आप हरियाणा में हिसार वाली साईड पर चले जाएं, रेगिस्तान है और सब–सोयल–वाटर है

जिसको जानवर भी नहीं पी सकते। ऐसे इलाके में आज हरियाणा सरकार ने पीने का पानी उपलब्ध करा दिया है। हरियाणा में आगमैंटेशन कैनाल के जरिए से पानी पहुंचाया। इसके अतिरिक्त बीरेन्द्र नारायण चक्रवती कैनाल, इन्दिरा गांधी और जवाहरलाल नेहरू कैनाल तैयार होने वाली हैं। यह नहरें उन लोगों के लिए हैं जिन को पीने का पानी नहीं मिलता था, जिनकी औरतें सिर पर मिट्टी का घड़ा उठाकर कई–कई मील से पानी लाती थीं। कही पानी नहीं मिलता था। जो लोग यह सोचते हैं कि मेरे इलाके से मीठा पानी किसी दूसरे इलाके में नहीं जाना चाहिए, यह बुरी बात है। अगर मैं यह सोचू कि मेरे इलाके से पानी निकाल कर वहां क्यों फेंक दिया, मुझे मिलना चाहिए, यह बात गलत है। ऐसी स्वार्थ भावना नहीं होनी चाहिए। अगर मैं ऐसा करता हूं तो मैं खुदगर्ज इन्सान हू, मैं विशमता को लिए हुए हूं और समता को नहीं लेता। सम की भावना नहीं रखता जो कि इन्सान में बड़ी आवश्यक है। हरियाणा में इस तरह के लोग होने चाहिए जिनमें समता की भावना हो। लोग कहते हैं कि हमारे इलाके से पानी निकाल लिया इसलिए कम हो गया। मैं कहता हूं कि पानी कम नहीं हुआ। मेरे इलाके में वाटर लोगिंग खत्म हो गयी, जमीन कल्टीवेशन के लायक हो गई और वह पानी उस जगह मिला जहां पानी दरकार है। ऐसे कामों की तारीफ होनी चाहिए कि एक तरफ की दिक्कत को दूर करने के साथ–साथ किसी दूसरे इलाके की न्यूनता को भी पूर्ण कर दिया, विशमता को दूर कर दिया। यह है हरियाणा की मिसाल,ख जिसका वर्णन राज्यपाल महोदय ने अपने

अभिभाशण में किया है। इसी प्रकार संचार की व्यवस्था की गई है। 70 से 80 प्रतिशत सड़कें बन गई हैं। ग्रीन रैवोल्यूशन आपने देख लिया है। हाउसिंग बोर्ड ने मिडियम इन्कम ग्रुप और लो इन्कम ग्रुप के लिए अम्बाला, फरीदाबाद, हिसार, भिवानी आदि हरियाणा में सब जगह मकान बनाये हैं। ये वे लोग हैं जो किराये के मकानों में मुश्किल से गुजारा करते थे, लेकिन अब इन्स्टालैमैंट में पैसा देकर खुद मकान–मालिक बन गये हैं। वे कभी स्वप्न भी नहीं ले सकते थे कि उनका भी कभी मकान हो सकता है लेकिन आज वे मकान–मालिक हैं।

इसी तरह सरकार ने शिक्षा के लक्ष्य को पूरा किया। यह सरकार बनने से पहले हमारे इलाके में क्या हालत थी, यह आप सब जानते हैं। आज कितने ही हायर–सैकन्डरी स्कूल खुल गए हैं। शिक्षा–पद्धति में सुधार होना बाकी है और वह इस तरह होना चाहिए कि बच्चों की पढ़ाई के दौरान अपने पावों पर खड़े होने की शक्ति हो। वह शिक्षा की पद्धति हमारी रही नहीं। वह रहनी चाहिए। बेसिक ऐजुकेशन की पालिसी तो महात्मा गांधी जी ने भी हमारे सामने रखी थी। उस पालिसी के मुताबिक तो शिक्षा का मतलब एक ऐसी बुनियाद बनाने से था जिससे बच्चा आगे चलकर अपने पांव पर खड़ा होने की हिम्मत रख सके। उस पद्धति का मंशा यह था कि पढ़ाई के दौरान उसे ऐसा काम बताया जाए जिससे वह आगे चलकर, शिक्षा प्राप्त करने के बाद, किसी के ऊपर आश्रित न हो। वह चाहे अपना रोजगार खुद बना ले या

नौकरी कर ले। आर्थिक विकास का एक बहुत बड़ा अंग हमारी शिक्षा है। अगर किसी देश में शिक्षा का अंग पूरा न हो तो आर्थिक विकास हो नहीं सकता। हमें हरेक बच्चे को, चाहे वह लड़का है या लड़की है, शिक्षा देनी चाहिए। यह भी जरूरी है कि शिक्षा मुफ्त दी जाए लेकिन इसके लिए जराय चाहिएं हमारे यहां प्राईमरी तक मुफ्त शिक्षा दी जाती है क्योंकि हमारे जराय अभी यहीं तक अनुमति देते हैं। आज हमारे सामने एक बड़ा अहम सवाल है कि पैसा कहां से आए? इकनौमिक डिवैलपमैंट का एक फार्मूला मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। जो अर्थ–शास्त्र कार्ल माक्स ने बनाया था ''दास कैपिटल'' के नाम से, उसकी एकौनौमिक थयोरी में पापुलेशन का ध्यान नहीं रखा गया था क्योंकि उस वक्त पापुलेशन इतनी ज्यादा होती नहीं थी। इस बात को न तो पहले ही और न आज ही इस थयोरी में विश्वास रखने वाले समझ पाए हैं। बहरहाल आज की माडर्न इकौमनी ने उस थ्योरी को अलाहिदा कर दिया है। आज पापुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ती जा रही हैं आज साढ़े अठावन करोड़ की हमारी पापुलेशन है। अध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में एक अजीब सी बात में बताना चाहता हूं। आज हिन्दुस्तान की आबादी में जिस रेट से बढ़ौत्तरी हो रही है, उसके अनुसार एक साल में हम एक–एक न्यूजीलैंड और एक–एक आस्ट्रेलिया बना देते हैं। क्या हालत हमारी हो रही है, यह देखने की बात है? इस स्पीड से तो आने वाले 25 साल में हमारी आबादी एक सौ करोड़ हो जाएगी, अगर इस पर प्रतिबन्ध न लगाया गया। एक तरफ तो सवाल आता है रोटी का, कपड़े का,

शिक्षा का, निकित्सा का और रोजगार का, लेकिन दूसरी तरफ दशा यह है। ये पांच चीजें हमारी अर्थ व्यवस्था के अंग हैं जिनको मजबूत बनाना हमारा सर्वप्रथम कर्त्तव्य है। समाजवाद में विश्वास रखने और एक कल्याणकारी राज्य होने के नाते से तो हमारे यहां इस बात की ओर भी ज्यादा अहमियत है। लेकिन यह सब कुछ कैसे हो सकता है जबकि एक तरफ तो हमारी पापुलेशन बढ़ती जाए और दूसरी तरफ जराय पूरे न हों और जो थोड़े बहुत कदम सइ सिचुएशन को मीट करने के लिए उठाए जाएं उनको बढ़ती हुई पापुलेशन हड़प कर जाए। इन हालात में कितने तन–बदन को हम कपड़ा दे सकते हैं, कितने लोगों को मकान पूरे होंगे, कितनों को शिक्षा दे पाएंगे, कितनो को चिकित्सा की सुविधाएं मुहैया कर सकेंगे और कितनों को रोजगार दे पायेंगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने है। इस बात पर हम सबको सोचना है कि किस तरह से हमने इस सम्बन्ध में अपना योगदान देना है। अर्थशास्त्र के शब्दों में यह जो पापुलेशन ऐसप्लोजन हो रहा है इसको कैसे रोका जाए, किस तरह से अपनी अर्थ व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सुचारू रूप से आगे बढ़ाया जाए, इस बात पर सोचना हम सबका कर्त्तव्य है। राज्यपाल महोदय ने कहा तो है कि पिछले वर्श के अन्त में, जबकि वे इस वर्श की बात लेकर आए, हम टेक आफ की स्टेज में थे। लेकिन टेक आफ करने से क्या होता है जब तक कि पूरे बूम के साथ आसमान पर उड़ा न जाए। कहने का मतलब यह कि किसी राज्य की या सिकी कंटरी की इकौनोमिक डिवैल्पमैंट, डिवैल्पिंग से डिवैल्पड बनने के लिए जब

ऐसी टेक आफ की शक्त में हो तो उस वक्त पूरी ताकत, सामूहिक तौर पर हम आदमी में, प्रत्येक व्यक्ति में यदि पैदा हो जाए तो आर्थिक विकास में आगे उड़ा जा सकता है। तो इस तरफ हम सबको अपना–अपना योगदान देना है तथी हम आगे बढ़ सकते हैं।

स्पीकर साहब, आपको मालूम ही है कि सरकार तो अपनी ओर से भरसक प्रयत्न कर रही है लेकिन कुदरत के अपने कायदे कानून होते हैं। इस वर्श वर्शा बहुत कम हुई और इसलिए बिजली भी कम पैदा हुई। परिणाम यह हुआ कि हमारे उद्योगों की जो प्रोडक्शन बढ़ती चाहिए थी वह नहीं बढ़ पाई। गवर्नमैंट ने उद्योग इंस्टाल करने में और लोन आदि देने में लोगों की मदद काफी की है और इससे ज्यादा भी करने के लिए तैयार है और हमारे उद्योगों की कैपसिटी भी उत्पादन बढ़ाने की है बशर्ते कि उन्हें पूरी बिजली मिले तो इस ओर भी हमें ध्यान देना है। फिर स्पीकर साहब, इसमें एक बात और ध्यान देने योग्य है। अकेली प्रोडक्शन ही हमें जिन्दा नहीं रखती, जब तक कि इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन न हो। प्रोडकशन तो हमने बढ़ाई है, इसमें कोई शक नहीं की बात नहीं। जिस देश में सुर्द पैदा नहीं होती थी, वहां आज हवाई जहाज बनाए गए हैं, पानी के जहाज बनाए गए हैं, रेलें बनाई गई हैं, और यहां तक की ऐटम बम भी बन गया है। किस चीज की कमी रह गई है? लेकिन हमारी यह कमी है कि हम देश की महानता को नहीं समझ पाते, देश की दिक्कतों को, देश

की मुसीबतों को और देश की परेशानियों को नहीं समझते। इन सब बातों को समझे बिना अपने देश की एक बड़ी गलत तस्वीर विदेशों के सामने रखते हैं। इतनी प्रोग्रेस अगर किसी और देश में हुई होती तो वे अपनी सरकार को सर पर उठाकर चलते लेकिन हमार यहां असलियत को परे करके सियासत की बात पर चला जाता है हमारे यहां क्रिटिसिजम सियासत पर बनी है जबकि यह इकौनोमी पर बेस्ड होना चाहिए। फिर स्पीकर साहब, तेजी से जो काम करेगा उससे गलतियां हो होंगी ही, उसमें कमियां तो रहेगी ही, क्योंकि कहा जाता है किः—

गिरते हैं शाह सवाल मैदाने जंग में,

वे तिफल क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलें

जिन्होंने काम करना नहीं सीखा, बोलना सीखा है, नुक्ताचीनी करनी सीखी है उनको क्या पता कि काम में क्या तकलीफें आती है, काम में क्या दिक्कतें आती हैं और काम में क्या परेशानियां हो सकती हैं? (इस समय उपाध्यक्षा पदासीन हुई।)

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ भाईयों की तरफ से कहा हता है कि बिजली के क्रैश प्रोग्राम ने हरियाणा की तबाही कर दी। कितनी गलत बात है? मैं अभी आल इंडिया इन्टक कांफ्रैस में बम्बई गया था। वहां लोग हरियाणा की बड़ी तारीफ करते थे। वह कहते थे कि बिजली के बगैर उनके यहां बड़ी दिक्कत है। वे इस दिशा में कर भी कुछ नहीं पा रहे हैं क्योंकि बिजली का सामान

ही नहीं मिलता। उनकी हालत आज यह है कि जब पैसा है तो सामान नहीं और जब सामान है तो मंहगे भाव में है। इसके बगैर उनके यहां इतना काम पडा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अगर हमारे यहां भी वह क्रैश प्रोग्राम वाली हालत पैदा नहीं होती जिसके द्वारा सारे गांवों में बिजली पहुंचा दी गई, तो हमारी हालत भी दूसरी स्टेटस की तरह होती। क्या वह गलत बात थी? क्या वह क्रैश प्रोग्राम बुरा था? अगर हम भी दूसरी स्टेटस की तरह इस काम को स्टैप बाई स्टैप करते तो आज दूसरी स्टेटस हमारी तारीफ नहीं करती और हमारे सामने नहीं झुकतीं। हमारी स्टेट आज हिन्दुस्तान में सब स्टेटों से आगे है चाहे वह पर–कैपिटा इन्कम हो या रेट आफ ग्रोथ की हो, जो चाहे बिजली का मामला है चाहे सड़कों का मामला है। काम करने में गलतियां होती हैं, दिक्कतें आती है ओर हो सकता है बिजली के मामले में भी कुछ इररैगुलैरेटीज हो गई हों, जिनको नहीं देख पाए हों, क्योंकि कई बार ओवर साईट से भी कुछेक बातें हो जाया करती हैं लेकिन इसके मायने यह नहींकि सारे के सारे गन्दे हो गए। गन्दा तो, अगर सच पूछा जाए, आज हमारा सारा समाज है जिसमें हम सब शामिल हैं। आज हमारी नैतिकता, हमारे मौरल का कंसैप्ट जो है वह गंदा है। इसलिए गन्दा है कि हमारे समाज की ऐप्रोच सही नहीं है। हमारा समाज आज तक अपनी उच्चता को समझ नहीं सका है। एक वक्त था जब सारी दुनिया हमारे देश के सामने नत–मस्तक होती थी। महाराजा अशोक के टाईम में, महात्मा बुद्ध के टाईम में चीन और जापान तक हमारे बौद्ध भिक्षु अपनी शिक्षा

का प्रसार करने गए और उन सबने उसे अपनाया। कितना ऊंचा था हमारा आदर्श और चरित्र। उस वक्त इतनी तरक्की क्यों थी? इसलिए थी कि उस वक्त समाज में केवल उस व्यक्ति को ठेकेदारी मिलती थी जिसकी भावना और चरित्र ऊंचा होता था। आज पैसे वाला समाज का ठेकेदार बना बैठा है चाहे वह चरित्रहीन हो, स्मगलर हो या बेईमान हो। ऐसा क्यों है? यह इसलिए है क्योंकि पैसे का कंसैप्ट हमने विदेशों से लिया है। जिस वक्त हमारी कोहिशन विदेशों के साथ हुई उस वक्त पेसे का कंसैप्ट तो हमने ले लिया लेकिन उनका चरित्र नहीं लिया या यों कहें कि पैसे का कंसैप्ट लेकर के अपना चरित्र उनको दे दिया। आज हमें अपनी नैतिकता को ऊंचा उठाना पड़ेगा क्योंकि हमारा मौरल बिल्कुल गिरा हुआ है। आज हमें अपने समाज को ठीक करने के लिए अपनी ऐप्रोच को बदलना होगा ओर यह तय करना होगा कि हमारी ऐप्रोच में पैसे का नहीं बल्कि चरित्र का स्थान ऊंचा है। मैं मानता हूं कि पैसा इन्सान की जरूरतों को पूरा करने के लिए बहुत बड़ी चीज है लेकिन हमें यह भी तो समझना चाहिए कि क्या आदमी पैसा खाएगा? क्या वह पैसा लेकर आया था और पैसा लेकर ही जाएगा? कदाचित नहीं। साथ तो उसके अपने कारनामे जाएंगे। साथ जाएगी उसकी अच्छाई, बहादुरी और भलाई। पैसा इनके सामने कुछ नहीं है। इसलिए पैस की महानता को कम करना पड़ेगा, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है।

उपाध्यक्ष महोदया, इसके बाद हमारे राज्यपाल महोदय ने प्राथमिकता दी सिंचाई को। फिर उन्होंने कम्यूनिकेशन सिस्टम के बारे में भी काफी कुछ कहा। चिकित्सा का जहां तक सम्बन्ध है, इसके बारे में यदि पहले की फिगर्ज को अब की फिगर्ज से कम्पयेर किया जाए तो पता लगेगा कि पर पर्सन आज चिकित्सा के क्षेत्र में जितना कुछ हुआ है वह पहले से कहीं ज्यादा हुआ है। हास्पिटल्ज बन गये हैं, हैल्थ सैन्टर्ज भी बने हैं। अम्बाला जिले में नारायणगढ़ के एक गांव में इतना अच्छा बड़ा हास्पिटल बना है जोकि बिल्कुल पी.जी.आई. के अनुरूप है। आपको पता ही है कि रोहतक में भी कितना बड़ा हास्पिटल है, नार्दन इंडिया में उसके मुकाबले का कोई नहीं है, उसमें कितने ही हजारों बिस्तरों का प्रबन्ध किया गया है। अम्बाला में, यमुनानगर में आज कितने अच्छें अस्पताल बने हुए हैं।

शिक्षा के विशय में तो मैंने, डिप्टी स्पीकर साहिबा, पहले ही बता दिया है। अब मैं रोजगार के विशय में एक बात जरूर रखना चाहता हूं। हमारे यहां अन–एम्पलाएमैंट और अन्डर एम्पलाएमैंट है। कुछ लोग तो बड़े आराम से गुजारा कर रहे हैं और कुछ लोगों को रोजगार ही नहीं मिलता है। यह जो कड़ी है इसको हल करने का कोई बुनियादी तरीका हमें निकालना चाहिए। वह यही तरीका हो सकता है कि पापुलेशन पर कंट्रोल किया जाये। बेरोजगारी दूर करने के लिए लेबर इनटैंसिव स्कीम की ओर ज्यादा ध्यान दिया जाये। कैपिटल इनटैनसिव स्कीम की ओर इतना

ज्यादा ध्यान न दिया जाये। लेबर इनटैंसिव स्कीम के तहत हम ज्यादा लोगों को रोजगार दे सकते हैं। कैपिटल इनटैंसिव स्कीम में जो भी चीज निकले वह आम जनता के फायदा के लिए होनी चाहिए। ऐसी चीजें बनायी जायें ताकि बेरोजगारी दूर हो। दूसरा मेरा अपना सुझाव यह भी है कि बेरोजगारी को दूर करने के लिए यह तरीका भी अपनाना चाहिए कि किसी फैमिली में तो पांच–पांच आदमी रोजगार पर लगे हुए हैं और किसी फैमिली में एक आदमी भी काम पर नहीं लगा हुआ है। जिस फैमिली का एक आदमी भी रोजगार पर नहीं लगा हुआ है उसको पहले रोजगार मिलना चाहिए। जिस फैमिली के पांच आदमी काम करते हैं, उनके पास तो साधन होते हैं, उनकी अपनी पोजीशन होती है, वे अपने परिवार के लोगों को रोजगार दिलवा सकते हैं, परन्तु जिस फैमिली से कोई भी आदमी रोजगार पर नहीं है, वह कहां से साधन तलाश करेगा? मैं यह सुझाव दूंगा कि उस फैमिली के आदमी को तब तक रोजगार न दिया जाये जब तक कि ऐसी फैमिली को रोजगार न मिल जाये जिनका कोई भी आदमी रोजगार में नहीं है। पारिवारिक तौर पर जब तक हम रोजगार मुहैया नहीं करेंगे तब तक हमारा समाज उन्नति नहीं कर सकता। जिस प्रकार से वितरण के मामले में, प्रोडक्शन के साथ वितरण भी होता है, उसी प्रकार रोजगार के मामले में भी डिस्ट्रिब्यूशन होनी चाहिए। जब तक यह बात नहीं होगी तब तक समाज से विशमता दूर नहीं हो सकती। इसलिए इस चीज का लाना बहुत ही जरूरी है।

अनुसूचित जातियां और पिछड़ी हुई जन–जातियों के कल्याण के बारे में मेरे से पूर्व–वक्ता मेरे दोस्त श्री गुलाब सिंह जी जैन ने काफी विस्तार के साथ रखा है। हरियाणा स्टेट ही ऐसी स्टेट हे जिससे अनुसूचित जाति के लिए बहुत कुछ कार्य किया है चाहे वह हरिजन कल्याण निगम ने किया, चाहे शिक्षा में स्कोलरशिप देकर किया है चाहे और तरीके से किया है। हरियाणा प्रदेश सब प्रदेशों से हरिजनों औप पिछड़ी जातियों की भलाई में मामले में आगे है। अब हरियाणा ने लैन्डलैस को जमीन देने का प्रोग्राम बनाया है ताकि वे उस जमीन पर अपना मकान बना सकें। यह लक्ष्य हरियाणा ने रखा है। सारे देश में हरियाणा प्रदेश ऐसा है जो अपने प्रदेश के लोगों के लिए मकान की जमीन सबसे पहले देना चाहता है।

अब एक चीज जो हमें अखरती है वह देश के विकास के बारे में है। जून सन् 1962 में लड़ाई हुई, सन् 1965 में हुई, फिर सन् 1971 में हुई, जिसके कारण से विकास में रूकावट आयी। इन बातों को मैं दोहराना नहीं चाहता। डिप्टी स्पीकर साहिबा हरियाणा के अन्दर तीन–चार साल तक कहत पड़ा है। यह कुदरत की मार है। वर्शा का न होना और कहीं पर वर्शा का इस कदर होना जिसका कोई हिसाब नहीं। डिप्टी स्पीकर साहिबा जैसे टिक्का साहब के इलाके में बारिश न हो तो वहां कुद पैदा नहीं होता, अगर सरदार हरमोहिन्द्र सिंह चट्ठा के इलाके में बारिश ज्यादा हो जाये तो वहां की जमीन खराब हो जाती है। हरियाणा

की ऐसी शक्ल है कि यहां पर हमेशा कुदरत की मार रही है। हरियाणा सरकार की ओर से बाढ़ को रोकने के लिए प्रोग्राम बन रहे हैं। इस बाढ़ के पानी को रोक कर नहरों के जरिए सिंचाई करने का प्रोग्राम हमारी सरकार की ओर से बनाया जा रहा है।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यूरेस्लम एक शहर है जो कि इजराइल का कैपिटल है। उसे होली–सिटी कहा जाता है वहां पर मोहम्मद का जन्म हुआ, क्राइस्टि भी रहे, उन्होंने वहीं पर शरीर छोड़ा और तीसरे सन्त मूसा हुए। वहां तीनों धर्मो के अनुयायी रहते हैं। यूरेस्लम में बरसाल का पानी इक्ट्ठा करके साल भर तक पीते है। यह इन्तजाम वहां पर किया हुआ है बरसात के बाद जो लीन–डेज होते हैं, लीन मन्थ होते हैं, उनमें पानी साल भर के लिए इकट्ठा करते हैं। लेक आफ टाईबेरिया से जोर्डर रिवर निकलता है। जोर्डन रिवर को अब तो इजराइल वालों के काबू कर लिया है। अब जोर्डन रिवर से पानी उनको नहीं मिलता है। उन्होंने रेगिस्तान में पानी दिया। कितना बड़ा काम किया है? चारों तरफ समुन्द्र से घिरा हुआ है, कहीं मीठा पानी नहीं है। उनकी हिम्मत देखिए, उनके तरीके को देखिए।

मुझे पी.ए.सी. के मैम्बर की हैसियत से बिहार जाने का अवसर मिला है। वहां नार्दन बिहार में सिंचाई काफी है, नदियों का स्कोप काफी है लेकिन सदरन बिहार में पत्थर वर्गरह हैं, बरसात कम होती है। पानी की किल्लत है। वहां टयूबवैल्ज लगाना भी मुश्किल है। वहां पर बारिश का पानी रिजर्वायर में इकट्ठा

करके सदरन बिहार का कल्याण हो सकता है। यह चीजें सारी खोज पर डिपैन्ड करती हैं। खोज दी इजाद की मां होती है। सारी चीजें ही इसी बुनियाद पर आती हैं। इंसान को जब तकलीफ होगी तभी किसी चीज की इजाद करेगा। तकलीफ ही नहीं होगी तो फिर वह इजाद कैसे करेगा? बिजली के लिए गवर्नर महोदय ने अपने अभिभाशण में टाईम बाउन्ड प्रोग्राम रखा है, लक्ष्य रखा है। अगर यह इरादा करके हम चलेंगे तो इस पीरियड के अन्दर हम बिजली के मामले में खड़े हो जायेंगे, प्राइमरी सैक्टर में, एग्रीकल्चार के मामले में, कोआपरेटिव सैक्टर में, इन्डस्ट्री में, सर्विस में। सड़कों में आगे हम चल रहे हैं। ये सारी चीजें पूरी हो जाने पर यह आज का हरियाणा नहीं होगा, इसकी नयी शक्ल होगी। राज्यपाल महोदय ने अभिभाशण में असलियत बतायी है, सच्चाई बतायी है। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है।

हरियाणा में बारिश न होने के कारण से ड्राउट पीरियड आया। क्वैश्चन आवर में जिक्र आया था कि पांच करोड़ की स्कीम बनायी गई है। एक करोड़ रूपये की स्कीम चरी के लिए और तकावी के लिए बनायी गयी है। जवाहर लाल नेहरू कैनाल को बनाने के लिए 35 करोड़ रूपया लगेगा। इसमें से कुछ पोरशन बनाकर उन लोगों को रोजगार दे पायेंगे जो खाने के लिए मोहताज हैं। ये स्कीम इसलिए बनायी गई है।

एक बात उपाध्यक्ष महोदया मैं सदन में यह भी रखना चाहता हूं कि उद्योग के मामले में फरीदाबाद कम्लैक्स बहुत आगे

है। वहां का बहुत सामान एक्सपोर्ट होता है। फौरन एक्सचेंज पैदा करता है। आज हरियाणा इस देश मैं नई–नई चीजें इजाद कर रहा है। आज हरियाणा दावा कर सकता है कि जिस कदर एक्सपोर्ट प्रोमोशन करके फौरेन एक्सचेज ले सकता है तो उसी आधार पर हमें सैन्टर की ओर से सब सहूलियतें दी जाये तो और भी अधिक उन्नति कर सकता है।

हरियाणा के अन्दर तीन शूगर मिलें हैं। वहां पर वर्करज की तन्खाह बढ़ाई गई है। पहली जून से हर वर्कर को तीन सौ रूपया माहवार तन्खाह मिलेगी। पहले उनको छः सात दिन की दर से ग्रैच्यूटी मिलती थी अब 15 दिन की करवायी गयी। उनका डी.ए. बढ़ाया गया। हर वर्कर की तन्खाह में जून से 100 रूपये का इजाफा हुआ है। रोहकत, पानीपत और जमनानगर तीनों मिलों में ऐसा हुआ है एक यह भी फैसला करवाया गया कि चार साल तक हम लड़ाई नहीं करेंगे, हड़ताल नहीं करेंगे। हमें चीनी का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में करना। आज चीनी की दरकार ईरान को है, मलेशिया को है। वहां पर चीनी का भाव 31 रूपये किलो है।

बिट्रेन में भी चीनी की किल्लत है। वहां पर भी हम चीनी भेज कर फौरेन ऐक्सचेंज कमायेंगे। इसी तरह से सीमेंट है। फरीदाबाद में फ्रिज की फैक्टरी है। ट्रैक्टर्ज बनाने की फैक्टरी है। मेरा कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां एच.एम.टी. या जितने भी उद्योग के अदायरे हैं, इनसे फारेन–ऐक्सचेंज लाया जा सकता

है और हम ला रहे हैं। हमने हरियाणा में इंडस्ट्रियल पीस कायम रख कर और चीजें ग्रेटर इनक्वांटिटी पैदा करके, फारेन कन्ट्रीज में अपना माल भेज कर फारेन ऐक्सचेंज पैदा किया है, यह हमारे लिये एक शाबाशी की बात है। इससे हरियाणा के लोगों को भी फायदा हुआ है।

अब मैं कृशि के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। कृशि के बारे में आंकड़े तो मेरे साथी गुलाब सिंह जी ने बता दिये कि 1968–69 की बनिस्बत 1973–74 में हमारे उत्पादन में 71 परसैंट की वृद्धि हुई है। आप ही देखिये, काफी वृद्धि हुई है लेकिन यह वृद्धि और ज्यादा हो सकती थी। हम 150 परसैट तक वृद्धि रक सकते थे, लेकिन बिजली की कमी है जिस वजह से इतनी नहीं हुई। हमारे यहां का काश्तकार कमजोर नहीं है। वह बहुत बहादुर है। वह बहुत समझदार काश्तकार है। हमें उन काश्तकारों को सलाम करना चाहिए जिन्होंने बिजली की किल्लत होने के बावजूद भी हरियाणा की बहबूदी के लिये काम किया है। (व्यवधान) गन्ना, कपास और तिलहन हमारी नकद फसलें हैं, जिन्हें हम कैशक्रोप्स भी कहते हैं। हरियाणा में जो इस वक्त बारिशें हुई हैं, उससे फसल अच्छी हो सकेंगी। मुझे यह जानकर बहुत खुशी हुई है कि हमारा बजट भी ऐसे दौरान में आया है जिसमें हम दोनों बारिशों की बुनियाद पर यह महसूस कर सकते हैं कि हमारे फ्यूचर क्रौप्स प्रौसपैक्टस और आर्थिक व्यवस्था क्या होगी। बजट तो दरअसल फरवरी–मार्च में आता है। मैं कभी–कभी सोचता हूं कि बजट का

विन्टर रेन्ज के बाद भी आना जरूरी है और इसलिए जरूरी है कि हमारी क्रौप्स की प्रोडक्शन जिसकी बुनियाद पर हम अपनी पोजीशन आर्थिक तोर पर देख सकें, वह विन्टर रेन्ज पर ही मुबनी है। यह इसलिये भी जरूरी है कि हमारा कृशि प्रधान देश है और विन्टर रेन्ज के बेसिज पर ही हम अपने बजट को निर्धारित कर पाते हैं।

दूसरे मामलों में भी हरियाणा सरकार ने अच्छा काम किया है। हरियाणा कृशि विश्व–विद्यालय में कितना अच्छा काम हो रहा है, कृशि के मामले में, बीज के मामले में और दूसरी चीजों के मामले में, यह सराहनीय है। परिवार नियोजन की बात मैंने कही है। यह बहुत जरूरी चीज है। इस तरह से राज्यपाल महोदय के अभिभाशण में जो कहा गया है, इंडस्ट्रियल डिवैल्पमैंट, सोशल वैल्फेयर, टूरिज्म, रोडज ट्रांसपोर्ट, डेयरी ओर कोओप्रेशन जैसे सारे अदायरों में हरियाणा ने कही कुछ आगे, कहीं बराबर के तौर पर, जो अपने लक्ष्य निर्धारित किये हुये हैं, वे पूरे किये हैं। मैं मामनता हूं कि इनमें कहीं कुछ कमियां भी होंगी। यह ठीक है क्योंकि जो काम करता है, उसमें कमियां भी रह जाती हैं। अगर आज हम यह कहें कि हम दूध के धोये हैं तो यह बिल्कुल गलत बात होगी।

मैं आज यह भी दावे से कह सकता हूं कि हमारे यहां ला एंड आर्डर भी बहुत बढ़िया है। हमारे साथी गुलाटी साहब एस्टीमेट कमेटी के साथ जब मंसूरी के लिये गये तो हमारे यहां

यमुना नगर में आये थे। उनकी वहां पर 410 रूपये की जेब कट गयी। लौटकर इन्होंने मुझे बताया कि मेरी आपके यहां जेब कट गयी। मैंने जाते ही पुलिस इन्स्पैक्टर को बुलाया। हमारे यमुनानगर का बहुत समझदार इन्स्पैक्टर है। उसने 6 दिन के अन्दर ही पिक–पाकेट भी पकड़ लिया और गुलाटी साहब के पैसे भी वसूल कर लिये और वह इनको मल भी गये। गुलाटी साहब मेरे सामने बैठे हैं। वे खुद बेहतर बतायेंगे कि हमारे हरियाणा में ला–एण्ड आर्डर कैसा है? मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि वह इन्सपैक्अर हरिजन कौम से ताल्लुक रखता है। उसका नाम सरदार नसीब सिंह है। मैं उस हरिजन अफसर की तारीफ करूंगा। मेरे कहने का मतलब यह नहीं है कि सारे ही एम.एल.ए. मेरे यहां आकर जेबे कटवा बैठें। मैं तो आपको यह एक मिसाल दे रहा हूं। मेरे यहां पोकटमार कोई ज्यादा नहीं हैं। कोई एक–आध निकल आया। मैंने अपनी गवर्नमैंट के जरिये उसका रास्ता साफ कर दिया। मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे यहां ला एण्ड आर्डर सही है। आपके देखा होगा कि जब कुछ लोग बस को उड़ाकर ले गये थे तो किस तरह से पुलिस ने वायरलैस के तरीके से उनको पकड़ा और ठिकाने लगाया। मैं यह दावा नहीं करता कि हमारे यहां डाका नहीं पड़ता या चोरी नहीं होती। हमारा समाज ऐसा नहीं है इतना नैतिक उत्थान आ गया हो कि वहां ये सब समाप्त हो जायें। मेरे कहने का मतलब यह है कि हरियाणा में ये चीजें दूसरी स्टेटों के मुकाबले में कम हैं राज्यपाल महोदय के अभिभाशण की बुनियाद पर इतना कहने का मैं हकदार बन सकता हूं।

टूरिजम के बारे में कई बार कहा जाता है कि क्यों इस ओर ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है? उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक बात कहना चाहता हूं। मैं विदेश में गया हूं। फ्रांस की इकौनोमी को देखा जाये तो यह पता चलता है कि उसकी जो इकौनोमी बढ़ी है वह पेरिस के टूरिजम से बढ़ी है। अमरिका के डायरैक्ट पेरिस को रात को जहाज आता है। इस वजह से अमरिका का सारा पैसा फ्रांस में घूम रहा है। अगर बाहर से मनी आकर किसी देश में लगेगा तो वह देश फ्लोरिश करेगा, उस देश की अर्थ–व्यवस्था मजबूत होगी। इसी तरह से अगर टूरिजम की बदौलत हरयिाणा में भी बाहर से पैसा आता है तो उससे एक तो हरियाणा का इमेज बनता है और दूसरे आर्थिक तोर पर हमें फायदा होता है। इससे सब हरियाणा के निवासियों को भी फायदा होता है। आप सबको पता है कि चंडीगढ़ से हर इतवार को सैकड़ों फैमिलीज पिंजौर में पिकनिक मनाने जाती है और अपनी परेशानी कुछ समय के लिये भूल जाती हैं। इसी तरह से हमारे यहां बड़खल–लेक के नजदीक के बच्चे बड़खल लेक पर और चक्रवर्ती लेक के नजदीक वाले चक्रवर्ती लेक पर पिकनिक करने चले जायें तो क्या उनका नैतिक और मानसिक उत्थान नहीं होगा? हमने सिर्फ हरेक बात की अपोजीशन ही करनी है, इसलिये नुक्ताचीनी करें और दूसरी चीजों को नजरअन्दाज कर दें, अगर अपोजीशन ऐसी बात सोचे तो मुझे बड़ी शर्म आती है। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदया, मैं एक और चीज आपके सामने रखना चाहता हूं। मैंने कार्ल मार्क्स की बात मार्डन इकौनौमिक थ्योरी के सिलसिले में कही थी। मैं यह कहना चाहता

हूं कि अर्थ के विकास की रूप–रेखा तीन चीजों के बेसिज पर बतायी जाती है। उनमें से एक है: बचत। जितनी ज्यादा हमारे देश के अन्दर बचत की योजनायें होंगी, उतना ही ज्यादा हम देश के लिए इन्वैस्टमैंट का अधिकार पैदा करेंगे। इसलिए बचत बहुत जरूरी चीज है। इसके लिए हमारे यहां अल्प बचत योजना है, प्रोविडैन्ट फंड योजना है और भी दूसरी कई योजनायें हैं। अगर हम घर–घर में बचत का सिलसिला शुरू कर दें और उस बचत से जो पैसा इकट्ठा हो, वह सरकार के सामने रख दें और यह कहें कि इसे आप जनहित के लिए प्रयोग करो, तो हम अपने पांव पर खड़े हो सकते हैं।

दूसरी चीज है एम्पलायमैंट। रोजगार भी दो तरह के हैं: एक प्रोडक्टिव और दूसरे अन–प्रोडक्टिव। प्रोडक्टिव एम्पलायमैंट जितनी ज्यादा होती जायेगी, उतना ज्यादा सुधार हमारी अर्थ–व्यवस्था में होता जायेगा। अन–प्रोडक्टिव एम्पलायमैंट वह है जिससे कोई भी इकौनोमिक सुधार नहीं होता बल्कि परेशानी पैदा होती है। आज हमें यह देखकर हंसी आती है कि फैक्ट्रियों में काम करने वाले लोग, जो जराय पैदा करते है, इतनी आवाज नहीं उठाते जितनी आवाज बड़े–बड़े पैसे वाले लोग उठाते हैं। आज एयर–इंडिया के लोग कहेंगे कि स्ट्राईक कर दें, आज एल.आई.सी. के लोग कहेंगे कि स्ट्राईक कर लें लेकिन क्या कभी उन्होनें सोचा है कि आज हिन्दुस्तान के 40 प्रतिशत इन्सान जो स्टारवेशनलैवल पर हैं ओर जिन्हें पूरी चीजें भी नहीं मिलतीं,

उनको भी जरूरियातें जिन्दगी मिलनी चाहियें? उनको सोचने के बाद आप भी सोचिये। इसके साथ ही आप यह भी हिसाब लगायें कि अगर हमने कोई कारगुजारी ऐसी करनी है तो अपने हको–हकूक मांगने से पहले, समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी सोचनी पड़ेगी और निभानी पड़ेगी। हमें अपनी जिम्मेदरी समझकर, उनके लिए अपने हकों की कुर्बानी करनी होगी। जब तक हम ऐसा नहीं करेंगे, हम उन 40 प्रतिशन पद दलित लोगों को जो स्टारवेशन लैवल पर हैं, ऊपर नहीं उठा सकते। मैं एक किताब यहां पर रैफर करना चाहता हूं। गवर्नमैंट आफ इंडिया की तरफ से 1956–57 में जो एग्रीकल्चरल लेबरर की पोजीशन के बारे में इन्कवायरी हुई, उसमें उन्होंने सारी–स्टेट्स के एग्रीकल्चरल लेबरर के डेलीवेजिज बताये हैं। उस वक्त हरियाणा और पंजाब इकट्ठे ही थे। उस समय आन्ध्रे प्रदेश में आदमियों की 0.87 रूपये, औररतों की 0.55 रूपये और बच्चों की 0.48 रूपये वेजिज थी। आसाम में 1.54 रूपये आदमियों की, 1.15 रूपये औरतों की और 1 रूपये बच्चों की डेली वेजिज थी। बिहार में 0.91 रूपये आदमियों की, 0.74 रूपये औरतों की और 0.70 रूपये बच्चों की वेजिज थी। गुजरात में 0.87 रूपये आदमियों की, 0.55 रूपये औरतों की और 0.50 रूपये बच्चों की डेली–वेजिज थीं। हरियाणा–पंजाब हिमाचल प्रदेश में 1.73 से 2.47 रूपये आदमियों की, 1.40 से 1.94 रूपये औरतों की डेली वेजिज थीं। यहां बच्चों के डेली–वेजिज का कोई सवाल नहीं। केरल में 1.28 मर्द, 70 पैसे औरत, 63 पैसे बच्चा। मध्य प्रदेश में मर्द 76 पैसे, औरत 59 पैसे,

बच्चा 57 पैसे। महाराश्ट्र में मर्द 87 पैसे, औरत 55 पैसे, बच्चा 50 पैसे। मैसूर में मर्द 84 पैसे, औरत 55 पैसे, बच्चा 47 पैसे। उड़ीसा में मर्द 80 पैसे, औरत 55 पैसे, बच्चा 51 पैसे। तमिलनाडू में मर्द 84 पैसे, औरत 48 पैसे, बच्चा 39 पैसे। उत्तर प्रदेश में मर्द 92 पैसे, औरत 65 पैसे, बच्चा 55 पैसे। वैस्ट बंगाल में मर्द 1.43 पैसे, औरत 98 पैसे, बच्चा 89 पैसे। त्रिपुरा में मर्द 1.54 पैसे, औरत 1. 15 पैसे, बच्चा 1 रूपया। इस रिपोर्ट को देखा जाए तो जब यह रिपोर्ट 1956–57 में बनी उस वक्त भी यहां की एग्रीकल्चर लेबर सब स्टेटों से आगे थी यह क्यों थीं क्योंकि यहां के लोग मेहनती हैं और आज मैं समझता हूं कि यहां के एग्रीकल्चर के लेबर के वेजिज पांच–सात रूपये से कम नहीं होंगे। मैं एग्रीकल्चर लेबर की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारा देश कृशि प्रधान देश है और उसमें हमारा प्रदेश एक कृशि प्रधान प्रदेश है। जब तक एग्रीकल्चर लेबर की हालत को हम ठीक करने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक कोई बात बनने वाली नहीं है। आज हमारे राज्यपाल महोदय ने जो नौ सूत्री कार्यक्रम हमारे सामने रखा है, उसमें एग्रीकल्चर पर जयादा जोर दिया हैं उन्होंने हर सैक्टर का जो प्रोग्राम बनाया है, जो अपनी सरकार ने नीति निर्धारित की है हमें किस तरह से प्राथमिकता देकर आगे चलना होगा, बताया है। एक चीज और मैं अर्ज करना चाहता हूं। इंडियन कोंसिल आफ सोशल साईस रिसर्च जिसके डायरैक्टर प्रोफैसर जी.एस. भल्ला हैं, दो स्टेटों की स्टडी की गई। हरियाणा उसमें से एक है। उन्होंने हरियाणा के बारे में लिखा हैः–

"The State has not only high income but also high rate of capital formation ....." यह हरियाणा स्टेट की बात बता रहा हूं। "..... which constitutes 14% of its income as against the all India figure of 9.3%" इस प्रकार हरियाणा की कैपिटल फार्मेशन आफ दि इनकम 14 परसैन्ट है, जबकि सारे देश की 9.3 परसैन्ट है। उपाध्यक्ष महोदया, जब हमारी कैपिटल फार्मेशन बढ़ी है, तो हमारी पर–कैपिटा इनकम भी बढ़ी है, कैपिटल फार्मेशन का रेट बढ़ा है, तो आज उसके मुकाबले में परेशानियां भी हैं, जिसकी वजह से विकास में गतिरोध पैदा हो गया है और इसको हमें नजरअन्दाज नहीं करना चाहिए, बल्कि डटकर मुकाबला करना चाहिए हमारे साथियों को, बजाय नुक्ताचीनी के कोई कन्स्ट्रक्टिव सजैशन देनी चाहिए ताकि हरियाणा और आगे बढ़ सके। राज्यपाल महोदय ने हमारे सामने जो अभिभाशण रखा है, उसमें जो लक्ष्य रखा है, जो टाईम बाउन्ड प्रोग्राम रखा है, उसको समझकर और जानकर अगर हम मिल–जुलकर चलें, तो हमारा हरियाणा और भी आगे बढ़ सकता है और जो मुश्किलात हमारे सामने आई हैं, उनको आसानी से हल कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आर्थिक विकास के बारे में मैंने रखी थी बचत की और ऐम्प्लायमैंट की, उसके बारे में मेरा कहना यह है कि प्रोडक्टिव एम्पलायमैंट ज्यादा होनी चाहिए, लेबर इटैसिव इंडस्ट्री लगानी चाहिए। कैपिटल ऐसी चीजों के लिए लगानी चाहिए कि जो चीजें हमारी आम जरूरत की हैं, गांधी जी का भी यही स्वप्न था कि ऐसी इंडस्ट्री लगानी चाहिए जो आम लोगों की जरूरियात को पूरा करें। इसके बाद

दूसरी चीज आती है कैपिटल आउट–पुट रेशो। इंडस्ट्री में हम कैपिटल लगाते हैं, उसके बाद रिटर्न आएगी, जिस प्रकार कि हम बैंक में पैसा रखते हैं और उससे रिटर्न आती है अगर रिटर्न कम है तो वह इंडस्ट्री ठीक से चल नहीं सकेगी। प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए हमें हर प्रकार की सहूलियतें देनी पड़ेंगी, तब जाकर हम उनसे कहें कि अब आप प्रोडक्शन बढ़ाइए। प्रोडक्शन में अगर हम कम्प्यूटर्ज आदि लगाकर लेबर सेविंग स्कीम्ज को बढ़ावा देंगे, तो इससे अन–एम्पलायमैंट बढ़ेगी। हमें तो अनएम्प्लाइमैंट को दूर करना है। हमें तो ऐसी स्कीम्ज चलानी चाहिए, जो लेबर इंटेंसिव हों, जिससे अन–एम्पलायमैंट दूर हो सके और प्रोडक्शन अधिक से अधिक हो सके और आम जनता की तकलीफ दूर हो सके। प्रोडक्शन के साथ–साथ हमैं डिस्ट्रीब्यूशन पर नजर भी रखनी है। अगर डिस्ट्रिब्यूशन ठीक नहीं होगा, तो जनता के अन्दर यही भावना होगी, जैसे कहते हैं कि ''Rich has become richer and poor has become poorer" डिस्ट्रिब्यूशन बहुत जरूरी है। हम सारे देश में प्रोडक्शन से ज्यादा रूझान डिस्ट्रिब्यूशन की तरफ डालें। जब तक हर चीज का इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन नहीं होगा, तक तक हमारे जो फिक्सड इनकम ग्रुप के भाई हैं, जो मजदूर हैं, उनको पूरी प्रोटक्शन नहीं दे पाएंगे, चाहे कपड़े के लिए, चाहे खाने के लिए, हमें इक्विटेबल डिस्ट्रिब्यूशन को अपनाना पड़ेगा। इसलिए कैपिटल की आउट–पुर रेशो बहुत जरूरी है। पोलिटीकल आजादी हमें मिली है। अब इकौनोमिकल फ्रीडम और दिमागी फ्रीडम की आवश्यकता है। दिमाग में जब तक परेशानी रहेगी, रोटी की

चिन्ता, कपड़े की चिन्ता, मकान की चिन्ता, चिकित्सा की चिंता और रोजगार की चिंता से दिमाग परेशान रहेगा, यह परेशानी दूर नहीं होगी, तब तक सही मायनों में आजादी नहीं समझी जाएगी और इन सब चीजों को दूर करने के लिए आज तकलीफें होने के बावजूद भी आज हरियाणा ने जो कदम उठाए हैं, वे साबित करते हैं कि इन पर जरूर काबू पा लिया जाएगा। अगर आज हिन्दुस्तान की किसी स्टेट का मुकाबला किया जाए, इतने थोड़े अर्से के अन्दर हरियाणा जिस तरह से आगे बढ़ा है तकलीफों का सामाना करके, कमियों को दूर करके इसमें हमने मिलजुल कर काम किया है, हमारे गवर्नमैंट सर्वैंटस ने बड़ी हिम्मत से काम किया है, उनका योगदान काबिले तारीफ है, और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तकलीकों और मुसीबतों का सामना करना है। अगर हम यह सोचकर चलेंगे कि हमारी तकलीफों का कारण क्या है, मुसीबतों का कारण क्या है और इन कारणों को हम दूर करें, तो उसका रास्ता भी हमें मिल जाएगा और हमारी मुसीबत भी दूर हो जाएगी। इन शब्दौं के साथ उपाध्यक्ष महोदया, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे नोटिस दिया और मेरे भाई श्री गुलाब सिंह जैन ने राज्यपाल महोदय के धन्यवाद का जो प्रस्ताव रखा है, उसका मैं अनुमोदन करता हूं।

Deputy Speaker: Motion moved –

That an Address be presented to the Governor in the following terms:-

"That the Members of the Haryana Vidhan Sabha assembled in this Session are deeply grateful to the Governor for the Address which he has been pleased to deliver to the House on the 1st January, 1975."

Deputy Speaker: I have received notice of an amendment by Ch. Devi Singh, M.L.A. This will be deemed to have been read and moved. The hon. Member may take part in the debate.

I have also received notice of amendments from Ch. Ram Lal and Ch. Shiv Ram Verma. These will also be deemed to have been read and moved.

Ch. Dal Singh: That in the motion, the following be added at the end, namely:-

"but regret that no mention has been made regarding –

(1) irregular and in-sufficient supply of Electricity and Canal water to the farmers.

(2) repression and prosecution of teachers by police and non-acceptance of the demands of teachers and H.S.E.B. employees.

(3) solution in respect of rising prices.

(4) Solution to arrest unemployment and to provide renunerative prices to farmers.

Ch. Ram Lal Wadhwa, Ch. Shiv Ram Verma: That in the motion of thanks the following be added at the end, namtely:-

"but regret that no mention has been made regarding:-

(1) rural Industrialisation to provide more employment and work in Rural Areas.

(2) change in system of Education in such a way which could give more jobs to unemployed persons;

(3) providing efficient, adequate and economic Road transport to the public

(4) solution to provide Raw Material and electricity to Industrial units according to their needs;

(5) solution to provide electricity and fair price of production to the Farmers;

(6) solution to meet the scarcity fo essential commodities and their fair distribution to the people."

चौ. दल सिंह (जींद): डिप्टी स्पीकर महोदया, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाशण पहली जनवरी, 1975 को इस सदन के सामने पढ़ा और उसके ऊपर एक सम्मानीय सदस्य ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है और एक घंटे तक वह अपनी बात कहते रहे, और

सरकार की तारीफ करते रहे। उसी प्रस्ताव का अनुमोदन भी सरकारी पक्ष के एक एम.एल.ए. साहब ने किया और उन्होंने भी एक घंटे तक सरकार की तारीफ की। यह बात उचित प्रतीत नहीं होती कि सरकारी पक्ष के भाई अपनी ही तारीफ करें और सच्चाई को छिपाते रहें। मैं इससे पहले कि अपने विचार रखूं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर हम पिछले चार सालों के अभिभाशण देखें तो सभी मैं वही बात दिखाई देती है और दूसरी तरफ सरकार का भी जवाब अगर हम देखें, तो सरकार भी वही जवाब देती है। इस बात को जब मैं देखता हूं तो मुझे इंग्लैड के एक विद्यार्थी की बात सामने आती हैं कैम्ब्रेज यूनिवर्सिटी से पढ़ने के बाद जब वह अच्छी तरह से सैटल हो गया तो उसको ख्याल आया कि मैं अपने दोस्तों से जाकर मिलूं, अपने अध्यापकों से जाकर मिलू और देखू कि यूनिवर्सिटी में कोई तबदीली आई है and he went there. When he reached near the campus, he saw the trees and said 'the same old trees'. He went further and saw the building of the University and again remarked 'the same old building'. He went further and saw the hall and after seeing it he gain said 'the same old hall'. He entered the hall and saw a young boy and a gild sitting on a desk and said 'the same old game'. The boy felt astonished and said. No, no, Mr. she is my sister' and then he said 'the same old answer'.

तो यह सरकार का वही पुराना अभिभाशण है, वही सरकार का पुराना जवाब हैं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं केवल उनके अभिभाशण की ही बात कहूंगा, मेरी अपनी कोई बात नहीं

है। मैं जो कुछ कहूंगा सरकार की ही बात कहूंगा। अगर सरकार ठीक काम करती है तो हम अपोजीशन वाले उनकी मुखालफत नहीं करते। खासतौर से मैं सबसे पहले व्यक्ति हूंगा, जो सरकार की मुखालफत नहीं करूंगा बशर्ते कि सरकार कोई अच्छे ठोस काम करें। लेकिन अगर हरियाणा की सरकार कोई गलत काम करेगी और हम बड़ाई करवाना चाहेगी तो हम लाजमी तौर से यह कहेंगे कि आपकी बात गल्त है और उनको लाजमी तौर पर उनको मानना पड़ेगा।

डिप्टी स्पीकर महोदया, 10 जनवरी, 1972, 5 मार्च, 1973, 4 जनवरी, 1974 और 1 जनवरी, 1975 ये चार अभिभाशण हैं, जब हम इन्हें देखते हैं तो सभी में एक ही बात दिखाई देती है और एक काम नजर आता है। 10 जनवरी के अभिभाशण के सफा 9 पर और 5 मार्च, 1973 के अभिभाशण के सफा 11 पर 4 जनवरी के अभिभाशण के सफा 1 पर और अब 1 जनवरी 1975 के अभिभाशण के सफा 1 पर एक ही बात कही गई है। बार–बार सरकार यह कहती है कि हमने सारे हरियाणा प्रान्त में बिजली लगा दी है। मैंने पिछले साल भी बिजली के विस्तार के सिलसिले में अपनी बात कही थी। मैं समझता हूं कि इन्होंने 29 नवम्बर, 1970 को यह कह दिया कि हमने सारे हरियाणा प्रान्त में बिजली दे दी है लेकिन मैं यह नहीं समझता कि फिर बार–बार इस साल लगातार चार साल तक राज्यपाल के अभिभाशणों में एक ही बात को लिखने का क्या तात्पर्य है?

इसका साफा मतलब यह है कि हरियाणा सरकार को अभी यह यकीन नहीं कि सारे हरियाणा प्रान्त मैं बिजली पहुंच गई है, वरना भारत की प्रधानमंत्री आखिरी गांव उचानी में सविच आन करती है तो फिर कौन सी बात बाकी रहती है। यह गल्त बात को बार–बार कह कर यह चाहते हैं कि हम इनकी गलत बात को मान लें, यह कोई विश्वास कर सकता है कि सूरज ईस्ट की बजाय वैस्ट से निकल सकता है। जो गल्त बात है, वह गल्त ही है, उसको सही नहीं कहा जा सकता। डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं तो सरकार के दिए हुए आंकड़े पेश करना चाहता हूं। जो सरकार की छापी हुई Statistical Abstract 1973-74 की किताब है, उसके अनुसार सफा 135 पर लिखा है:–

> "Haryana is the first State in the country to achieve 100 per cent rural electrification. Uchani was the last of 6670 villages of Haryana electrified on 29th Novermber, 1970."

यह कहते हैं कि 29 नवम्बर, 1970 तक हरियाणा प्रान्त के हर गांव में बिजली पहुंची है और आखिरी गांव उचानी है, जहां पर भारत की प्रधानमंत्री ने सविच आन किया है और गावं की तादाद 6670 थी, यह उनकी किताब कहती है और आगे चलकर सफा 135 के ऊपर लिखा है:–

> "Number of towns and villages electrified in Haryana as on 31st March, 1973 was 6731."

तीन साल के बाद कहते हैं 6731। 1972–73 में एक किताब Haryana Review छपी है उसमें कहते हैं:–

> "Hundred per cent electrification was achieved in Haryana in 1970. Total number of villages in the State was 6669."

पहले कह दिया 6669, उसके बाद 6731, उसके बाद 6670 और फिर लास्ट में कहते हैं 6771, तो अब मैं इस सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि इन में से कौन सी बात ठीक है। यह उनकी अपनी ही बात है, वह यह खुद कहते वाले हैं, खुद करने वाले हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इस बारे में सरकार का दिमाग साफ नहीं है कि बिजली पहुंची है कि नहीं? डिप्टी स्पीकर महोदया, मैं एक मोटी बात करना चाहता हूं कि 22 नवम्बर, 1971 को एक प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि हरियाणा के 6609 गांवों को स्ट्रीट लाईट पहुंचा दी गई है, यह कब कहा, तकरीबन एक साल बाद। इसका मतलब यह हुआ कि फिर यह मान गए कि 6609 गांवों में बिजली है, फालतू में नहीं है। यह जो आंकड़े हैं, यह सरकार की किताबों में से लिए गए हैं। 10 जनवारी, 1974 के अभिभाशण के सफा 10 पर लिखा है:–

> "Besides the first 60 M.W. unit at Faridabad which is under construction, the Board proposes to instal there a second unit of 60 M.W. Two generating units of 110 M.W. each are proposed to be installed at Panipat."

5 मार्च, 1973 को जो अभिभाशण राज्यपाल महोदय ने पढ़ा उसके पेज 11 पर लिखा है कि फरीदाबाद में 60–60 मैगावाट क्षमता वाले दो यूनिट स्थापित किए जा रहे हैं। पानीपत थर्मल प्लांट स्थापित करने सम्बन्धी कार्य को प्रारम्भ कर दिया गया है। इसके आगे 4 जनवरी, 1974 के अभिभाशण के पेज 2 पर लिखा है कि 60–60 मैगावाट के दो थर्मल प्लांट फरीदाबाद में सैट–अप किए जा रहे हैं और 110–110 मैगावाट का एक–एक थर्मल प्लांट पानीपत में लगाया जा रहा है। वही पिछली बातें इसमें दोहरा दी गई हैं।

17.00 बजे

4, जनवरी, 1974 वाले में भी यही लिखा हैः–

> "Two thermal units of 60 M.W. each are being set up in Faridabad and two more of 110 M.W. each are being set up in Panipat."

फरीदाबाद और पानीपत के थर्मल प्लांटों का जिक्र चलता है, दोनों अभिभाशणों के अन्दर 1 जनवरी, 1975 को राज्यपाल ने जो अभिभाशण यहां पर पढ़ा है, उसके पेज एक पर लिखा हैः–

> "Efforts are being made to expedite the construction of two units of 110 M.W. capacity each at Panipat. One thermal unit of 60 M.W. has already been commissioned at Faridabad and another similar unit will be commissined a few months later."

तो मैं यह कहता हूं कि बार–बार एक बात को दोहरा कर सरकार खुद यह बात साबित करती है कि सरकार को खुद यकीन नहीं है कि हरियाणा के हर गांव में बिजली है। पानीपत के प्लांट का प्रचार सुनते हमें चार साल हो गए और अब भी कहते हैं कि एक्सपीडाइट करने की कोशिश कर रहे है। मैं यह चाहूंगा कि सरकार राज्यपाल महोदय को कम से कम वह बात लिखकर दे जिसमें कोई सच्चाई हो ताकि उसे हम भी मानें कि ठीक है। मैं पिछले हफ्ते फरीदाबाद गया था वहां मुझे पता लगा कि हमारे गुप्ता जी जो आई.पी.एस. हैं, इन्होंने वहां उदघाटन किया, हालांकि उस प्लांट की तैयारी नहीं थी, फिर भी इन्होंने उद्घाटन किया। ये नए–नए मिनिस्टर बने हैं, इसलिए इनको उद्घाटन करने का शौक है –(विघ्न)–

सिंचाई एवं बिजली मंत्री (श्री बनारसी दास गुप्ता): डिप्टी स्पीकर साहिबा, यह बिल्कुल गलत बात है। वहां कोई उद्घाटन नहीं हुआ। उन्होंने तो * * * * बोलने का ठेका ले रखा है। आप सारे साहिबान ध्यानपूर्वक सुन लो कि आज तक फरीदाबाद थर्मल प्लांट का औपचारिक उद्घाटन नहीं हुआ।

चौ. दल सिंह: आप मुझे बोलने दैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप उस वक्त कह लें, जब आप बोलेंगे।

श्री बनारसी दास गुप्ता: आपको गलत कहने का राईट नहीं है। यहां सामने इस हाउस में भी लिखा हुआ है कि झूठ बोलना पाप है।

चौ. दल सिंह: हमें भी बोलने दें ....(विघ्न)....आप कहते हैं कि बिहार में डैम बनाएंगे, कलकत्ता में बनाएंगे .....(शोर)..... आप हमारी बात शांति से सुने।

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैं आपकी सारी बात शांति से सुन रहा हूं लेकिन जब * * * * बोला जा रहा हो उसे कैसे सुना जाए?

उपाध्यक्षा: चौ. दल सिंह जी, आपको प्रापर–वे में बोलना चाहिए।

चौ. दल सिंह: मैं प्रापर–वे में ही बोल रहा हूं। जो मुझे वहां के लोगों ने बताया है, मैं यहां बता रहा हूं। मैं गुमराह नहीं कर रहा हूं।

श्री बनारसी दास गुप्ता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा प्वांयट आफ आर्डर है कि अगर यह बात सही हो, तो मैं अस्तीफा देने के लिए तैयार हूं, वर्ना चौ. दल सिंह अस्तीफा दे दें। इस हाउस में स्पश्ट लिखा हुआ है कि झूठ बोलना पाप है।

चौ. चांद राम: डिप्टी स्पीकर साहिबा, इन्होंने यह जो झूठ का लफ्ज कहा है, यह अन–पार्लियामैंट्री है।

उपाध्यक्षा: इन्होंने यह नहीं कहा कि झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने तो यह कहा है कि झूठ बोलना पाप है।

चौ. दल सिंह: मैं कोई इल्जाम थोड़े ही लगा रहा हूं। मैं तो अब भी इतनी बात कहता हूं कि आज भी उस यूनिट से कोई बिजली पैदा नहीं होती हैं। ....(विघ्न)....आप मेरी बात को सुन तो लें। मैं फरीदाबाद की बात कर रहा था। फिर यह अभिभाशण जो है, उसमें गवर्नर महोदय फरमाते हैं कि बिजली की कमी 1977–78 तक पूरी हो जाएगी। मेरे कहने का मतलब यह है कि पिछले 4–5 सालों से राज्यपाल के अभिभाशण में तोड़–मरोड़ कर वही बात लिखी जा रही है–यह क्या तमाशा है? हमें यह बात कहते का

*अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

हक है कि यह बात सही है और यह गलत है (विघ्न) अब एक और अजीब बात देखिए कि 4 जनवरी, 1074 के अभिभाशण के पेज 5 पर ये फरमाते हैं कि हरियाणा प्रान्त में 149160 टयूबवैल्ज है और अब फरमाते हैं कि 133000 टयूबवैल्ज हैं यानी एक साल में 16160 टयूबवैल्ज घट गए। यह चीज मैं नहीं कहता यह इन्होंने खुद लिखा है। सबझ में नहीं आती यह क्या तमाशा बना रखा है? फिर कोई बोलना चाहे तो बोलने नहीं देते।

जहां तक बिजली के उत्पादन की बात है वह भी मैं आपकी मार्फ सदन के सामने रखना चाहता हूं। हरियाणा प्रान्त में और बाकी सारे मुल्क के अन्दर कितनी–कितनी बिजली पैदा हुई और कितनी क्षमता के प्लांट लगे यह भी देखने योग्य बात है। 'स्टैटिस्टीकल एब्स्ट्रैक्ट आफ हरियाणा 1973–74' में यह दर्ज है कि हरियाणा के अन्दर 504 मैगावाट की क्षमता के प्लांट हैं और उपभोक्तओं की तादाद 616193 है, आंध्र प्रदेश के अन्दर 608 मैगावाट की क्षमता के प्लांट हैं और उपभोक्ता 1249234 हैं, गुजरात के अन्दर 904 मैगावाट की क्षमता के प्लांट हैं और उपभोक्ता 1437275 हैं, इसी प्रकार महाराश्ट्र के अन्दर 2109 मैगावाट यानी हरियाणा से चार–गुणा ज्यादा क्षमता के प्लांट हैं यह कहते हैं कि देश भर में हमारे बराबर कोई नहीं है–तो वहां उपभोक्ता 2295794 इससे आगे मैसूर में 960 मैगावाट की क्षमता के प्लांट हैं और उपभोक्ता हैं 1200761 उसके बाद पंजाब जो हमारा पड़ौसी प्रदेश है वहां 750 मैगावाट क्षमता के प्लांट हैं और उपभोक्त 1156240 है, तमिलनाडू में 2186 मैगावाट क्षमता के प्लांट हैं और उपभोक्त 2426424 हैं, हरियाणा से चार गुणा ज्यादा। पश्चिम बंगाल, जिसे हम बड़े फख्र से कहते हैं कि बड़ा गरीब सूबा है उस प्रान्त के अन्दर 1215 मैगावाट की क्षमता के प्लांट हैं और उपभोक्ता हैं 938125। तो जहां तक प्लांटों की क्षमता का ताल्लुक है, हरियाणा का नम्बर हिन्दुस्तान में बारहवां हैं। यह तो थी क्षमता की बात, इससे आगे आप चलें, पर–कैपिटा बिजली कंजम्पशन में, मेरे साथी श्री गुलाब सिंह जी बड़े जारे से कह गए

और जोशी जी ने भी बड़े जोर से कहा कि हमारी जो पर–कैपिटा कन्जम्पशन है वह बड़ी भारी है। लेकिन हरियाणा के अन्दर पर–कैपिटा कन्जम्पशन जो है बिजली की वह 104.82 यूनिट है, पंजाब के अन्दर 168.63 यूनिट है, तमिलनाडू के अन्दर 131.99 यूनिट हैं, पश्चिमी बंगाल में पर–कैपिटा कन्जम्पशन 106.55 यूनिट, गुजरात में 129.19 यूनिट, मैसूर में 113.60 यूनिट पर–कैपिटा कन्जम्पशन बिजली की है। इस हिसाब से अगर हरियाणा को देखा जाए, तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, हरियाणा का सातवां नम्बर पर–कैपिटा कन्जम्पशन में आता है। लेकिन यह भाई डींगे मारते नहीं थकते कि साहब हम तो सारी दुनिया में आगे हैं और हमने तो बिजली के मामलों में सारे प्रदेशों को मात कर दिया लेकिन जो असलियत है वह आप ही देख लें कि इसमें कितनी सच्चाई है। यह अजीब तमाशा इन्होंने बना रखा है, कम से कम सच्चाई की बात तो करो। आज हम अगर ठीक बात करें तो हमारी बात को सुनते ही नहीं। यह जो फिगर्ज मैंने दी हैं यह मेरी नहीं है, सरकार की अपनी किताब से पढ़कर मैंने कोट की हैं। अगर गलती होगी तो इनकी किताब की होगी लेकिन जो बात सही है वह मैंने अर्ज कर दी हैं यह कहते फिरते हैं कि सारे हरियाणा में इन्होंने बिजली पहुंचा दी हर गांव में दे दी। इसका नमूना मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि दूसरी स्टेट्स में कितने गांवों को बिजली उन्होंने दी, पहले साल में कितने गांवों में दी और उसके अगले साल में कितने गांवों में दी। हरियाणा में 1970–71 में कहते हैं कि 6770 गांवों में बिजली

पहुंचा दी। अब दूसरों की बात देख लो। आंध्र प्रदेश मैं 1970–71 में 8878 गांवों में बिजली थी और अगले साल 1971–72 में 9252 गांवों में पहुंचाी यानी एक साल में 1174 गांवों में उन्होंने बिजली दी। हरियाणा में कहते हैं कि और कोई गांव हीं नहीं थे कि जिनको बिजली दी जाती। लेकिन अगर आप दूसरों के साथ मुकाबला करते हैं ओर अपने आपको सबसे आगे कहते हैं, तो सच्चाई की तरफ भी देखना चाहिए कि हमने किया क्या है? तो मैं अर्ज करता हूं कि बिहार के अन्दर जो गरीब प्रान्त कहा जाता है 1970–71 में 7741 गांवों में बिजल थी और अगले साल 1971–72 में 8313 गांवों में उन्होंने बिजली दी। फिर मध्य–प्रदेश को लें वहां 1970–71 में 6609 गांवों में बिजली थी और 1971–72 में उन्होंने 8787 गांवों में बिजली पहुंचा दी, यानी एक साल में अढ़ाई हजार से ज्यादा गांवों को बिजली दी .....।

उपाध्यक्षा: इसके साथ यह भी तो मैंशन करें कि वहां कुल गांवा कितने थे –(हंसी)–

चौ. दल सिंह: मैं कम्पैरेटिव फिग्र्ज दे रहा हूं इससे आप अन्दाजा लगा लें कि असलियत क्या है? मैं अर्ज कर रहा था कि महाराश्ट्र में 1970–71 में 12151 गांवों में बिजली थी और 1971–72 में उन्होंने 13160 गांवों में बिजली पहुंचा दी। मैसूर में 1970–71 में 8328 गांवों में बिजली थी और 1971–72 में 10075 गांव में पहुंच गई इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में 1970–71 में 20714 गांवों में बिजली थी और 1971–72 में 23795 गांवों में पहुंच गई।

तो आप अन्दाजा लगाएं कि एक साल में उन्होंने हरियाणा के कुल गांवों के आधे गांवों बिजली दे दी सिर्फ एक साल में। फिर हमारे यहां बिजली की क्या हालत है यह भी एक अजीब तमाशा है और बिजली बोर्ड कैसा काम करता है वह एक अजीब कहानी है। मैं फिर सरकार के अपने आंकड़ों की तरफ आता हूं। यह मेरे पास हमारे सदन की पब्लिक अकाउंटस कमेटी की 1972–73 की रिपोर्ट है। आप जानते है कि इस सरकार का बहुमत है और इस कमेटी में भी सरकारी पक्ष के ज्यादा मैंबर हैं ओर इसका चेयरमैन भी सरकारी पार्टी का है और उस कमेटी की रिपोर्ट है जिस कमेटी में सरकारी मैम्बरों का बहुमत है, मैजोरिटी है। यह कमेटी हाउस की सबसे अहम कमेटी होती है और बड़ी जिम्मेदार कमेटी है। उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है:–

"The Committee note with concern that line losses are on the increase from 1967-68 onwards."

1967–68 से लगातार लाइन लौसिज ऊपर ही ऊपर जा रहे हैं। 1967–68 में तो दूसरी सरकार थी लेकिन उसके बाद इनकी यह सरकार आई है और उसक बाद से यह लौसिज बढ़ते ही चले गए लगातार "As against 16.6% in 1966-67, the loss had almost doubled by 1971-72". यह कहते हैं कि 1966–67 में लाइन लौसिज 16.6 थे फिर 1968 से यह बढ़ते लगे और बढ़ते–बढ़ते आज तकरीबन दुगने हो गए हैं। यह मैं नहीं कहता इनकी कमेटी की रिपोर्ट कहती है। फिर इसके बावजूद यह कहते हैं कि बहुत

बढ़िया चेयरमैन है, लेकिन मैं कहता हूं कि अगर हिन्दुस्तान में ऐसे दो–चार चेयरमैन और हो गए, तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। आगे चलकर इसी रिपोर्ट में लिखा है:–

"The Committee strongly feel that it is due to improper planning, non-strenthening of transformers and other equipment."

अब यह कहते हैं कि, क्योंकि हरियाणा बिजली बोर्ड की प्लानिंग ठीक नहीं थी डिफैक्टिव थी, नुक्सादार थी, अच्छी नहीं थी, ट्रासफार्मज जो लगाए गए वह ठीक तरह से नहीं लगाए गए इसलिए लौसिज बढ़े। अगर हम यह बात कहते हैं तो यह कहते हैं कि हमारे अफसर बहुत बढ़िया हैं। हमें पता है कि किस तरह के बढ़िया हैं। अब मैं इस सदन का ध्यान इस बोर्ड की माली हालत की तरफ दिलाना चाहता हूं। इस बोर्ड पर इस वक्त कोई दो सौ करोड़ का कर्जा है, लेकिन आप देखें कि इस कर्ज से इस बोर्ड ने क्या फायदा उठाया है। इस बोर्ड को 1970–71 में 126 लाख 29 हजार रूपए का घाआ रहा एक साल में। फिर आप इससे आगे चलें। 1971–72 में 429 लाख का नुक्सान रहा और 1972–73 में 364 लाख का घाटा रहा। मैं पूछना चाहता हूं कि यह कैसी प्लानिंग है और क्या यह बोर्ड की कार्यवाही है कि दो सौ करोड़ रूपये का कर्ज इसके सिर पर हो, जिस पर हर साल आठ–नौ करोड़ रूपया सूद दिया जाता है और फिर हर साल ही घाटा होता चला जाए। इन हालात में कौन मानेगा कि बोर्ड की कारगुजारी ठीक है। एक गुजारिश मैं और करना चाहता हूं और

यह कोई नाराजगी की बात नहीं होनी चाहिए। मैं आपका ध्यान कम्प्ट्रोलर ऐंड आडिटर जनरल आफ इंडिया की रिपोर्ट की तरफ दिलाना चाहता हूं। पिछली दफा चीफ मिनिस्टर ने बड़े फख्र के साथ कहा था कि ज्यों ही हमारे पास वह रिपोर्ट आएगी, हम फौरन सदन की मेज पर रखेंगे। लेकिन मैं अर्ज करता हूं कि वह रिपोर्ट भारत सरकार को मिल चुकी है और हरियाणा सरकार को मिल चुकी है, मगर आजतक सदन की मेज पर वह नहीं रखी गई। अगर सरकार का दामन साफ है और ये समझते हैं कि कोई गलत बात इनकी नहीं है तो फिर क्यों वह सदन की मेज पर नहीं रखी जाती और वह क्यों नहीं पब्लिश की जाती? मैं यह कह सकता हूं कि अगर हरियाणा सरकार इसे मेज पर रखेगी तो इस बोर्ड के चेयरमैन और दूसरे कार्य–कर्ताओं की कारगुजारियों का पता लग जाएगा कि करोड़ों रूपए का गबन किया गया है और करोड़ों रूपए के ब्लैक में बिजली के खम्बे खरीदे गए, जो रिजैक्टिड खम्बे थे उनके ऊंचे भाव पर टैंडर मन्जूर किए गए। अगर मिनिस्टर साहब इस बात से इनकार करते हैं तो उस रिपोर्ट को सदन की मेज पर रखें, यह रिपोर्ट मेरे पास है अगर डिप्टी स्पीकर साहिबा आप इजाजत दें तो मैं इसे हाउस की मेज पर रखता हूं। If you allow me, I am prepared to place it on the table of the House. आप देखिए इसके अन्दर क्या तमाशा हैं इस्लामाबाद गांव से 33 के.बी. लाइन की एक्सटैंशन के लिए, 11 के.बी. लाईन को दोबारा एक्सटैंशन करने के लिए 60 किलोमीटर लाईन को गिराना पड़ा, डिसमैंटल करना पडऋाख जिससे आठ लाख रूपए का घाटा पड़ा।

इनको कया हक है कि गरीबों से टैक्सों के जरिए रूपए लेकर इस तरह से वेस्ट किया जाए। फिर ये कहते हैं कि इतनी बिजली लगा दी और इतनी तरक्की कर दी। इसके लिए तो बेहर था कि चुप रहते और चुप रहें मैजोरिटी इनके पास है, जो चाहें पास करवाते चले जाएं लेकिन यह जो इस तरह चैलेंज करके कहते हैं कि यह कर दिया वह कर दिया यह ठीक नहीं है। आप इस रिपोर्ट से देख सकते हैं कि कितनी गड़बड़ है और हेरा–फेरी है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, अगर आप इजाजत दें तो मैं यह रिपोर्ट सदन की मेज पर रखता हूं। यह गवर्नमैंट आफ इंडिया की रिपोर्ट है आपकी बड़ी मेहरबानी होगी अगर आप इसे मेज पर रखने की इजाजत दें।

टैंडर रिजैक्ट किए हुए परचेज किए और खम्भे जो डिफैक्टिव थे, वे परचेज किए, ट्रासफार्मरज रिजैक्टिड खरीदे गए। मेरे कहने का मतलब यह है कि घटिया सामान लिया गया। जो घटिया ट्रांसफार्मर्ज जल गए, उसकी मुरम्मत के लिए 11488952 रूपए इस बोर्ड ने खच्र किए। इतनी भारी रकम कहां से ली गई। मैं यह बता देता हूं कि एक क्वैश्चन नं. 1201 दिनांक 23.8.71 के जवाब में गवर्नमैंट ने कहा कि 11488952 रूपए मुरम्मत पर खर्च हुए। आप देखें कि कितनी भारी रकम है और फिर हम उस चेयरमैन की तारीफ करते हैं जो हरियाणा का दीवाला निकालता हुआ चला जाए और दूसरी तरफ हम उसकी तारीफ के पुल बांधते रहें। 1970–71 में जो घटिया ट्रांसफारमर्ज खरीदे गए उससे

किसानों को बड़ा भारी नुक्सान हुआ, क्योंकि दो–दो महीने तक सरकार उनकी रिप्लेसमैंट नहीं कर सकी और आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि बिजली और पानी के बगैर किसान की कितनी बरबादी हुई। इसके इलावा किसान ने एम.सी.जी. के तहत रूपया वसूल किया गया। मैंने मुख्यमंत्री महोदय से कहा था कि जिस अर्से में सरकार बिजली की कटौती करती है, जिस अर्से में किसान को बिजली नहीं दे सकते, मेहरबानी करके उससे उसका खर्चा न लें। इस पर मुख्यमंत्री आश्वासन दिया था कि बिजली पर कट जहां हुई है, उस दौरान का बिजली का कोई बिल नहीं बनेगा। लेकिन आप देखें कितनी हैरानी की बात है कि उस दफ्तर से बिजली का बिल बनकर जा रहा है, हजारों रूपया किसानों से वसूल यिका जा रहा है। चीफ इंजीनियर इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के दफ्तरों से एक चिट्ठी निकलनी है कि 25 परसैन्ट रिबेट दे दिया जाए, लेकिन कोई रिबेट नहीं दिया जाता, क्योंकि हमारे रूल्ज ऐसे हैं कि पहले पेमैंट करा, बाद में देखा जायेगा तब जाकर बाद में रिबेट का फैसला होता है। पहले पेमैंट करके कौन झगड़ता रहे? झूठे बिल बनाकर किसानों से पैसा वसूल किया और इस तरह से हरियाणा बिजली बोर्ड हरियाणा की तबाही करने के लिए बना हुआ है, यह एक सीधी सी बात है।

सरकार खेती की तारीफ के पुल बांध रही है। एक तरफ खेती को बिजली देते हैं और दूसरी तरु एक लाख मजदूर हरियाणा प्रान्त में बेरोगजगार हैं। किस लिए, क्योंकि बिजली की

कटौती उद्योग–धन्धों पर है। फिर ये बड़ी डिंग मारते हैं कि हम बेरोजगारी को खत्म करेंगे। एक तरफ कहते हैं कि हरयिाणा का वर्कर समझदार है और दूसरी तरफ आप देखें मजदूर के तन पर कपड़ा नहीं है, जूती नहीं है, बच्चों के लिए रोटी नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, एक तरफ मजदूरों को सरकार की तरफ से धोखा मिलता है और दूसरी तरफ कहती है कि हम तरक्की पसन्द हैं, कितनी कमाल की बात है। उद्योगों पर बिजली की कटौती से उद्योंगों में 7 अरब रूपए के उत्पादन का घाटा रहा है। अगर 7 अरब रूपए का उत्पादन होता तो इसमें सरकार को भी फायदा रहता लेकिन इन्होंने सारे उद्योग–धन्धे चौपट कर दिए, हरियाणा की तबाही हो गई। मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि वह इस बात पर सीरियसली गौर करें और इस बात को देखें कि जो कुछ हम कहते हैं वाकई ही उसमें कोई सच्चाई है? हम सरकार के साथ चलने के लिए तैयार हैं। * * * * आफिसर अगर कोई है, तो उसकी क्यों मदद की जाएद्य अच्छी बात है फिर तो तारीफ करो, उसको इंसैटिव दो। अगर चेयरमैन * * * * आफिसर बना दिया है जो हरियाणा को तबाह करने पर तुला हुआ है, अगर सरकार उसकी तारीफ करें तो बड़े अफसोस की बात है। .....

श्री बनारसी दास गुप्ता: आन ए प्वांयट आफ आर्डर, मैडम। क्या कोई अधिकारी जो इस सदन में आकर जवाब न दे सकता हो, उसके ऊपर कोई इल्जाम लगाया जा सकता है? –(व्यवधान)–

चौ. दल सिंह: बाई नेम मैं नहीं लगा सकता ..... आप बता दें मैंने क्या कहा? –(व्यवधान)–

श्री बनारसी दास गुप्ता: मैं रूलिंग चाहता हूं .....

चौ. दल सिंह: पिछली दफा इस पर रूलिंग जा चुकी है .....

उपाध्यक्षा: कोई मैम्बर क्या कहता है, इस पर रूलिंग देना बड़ा मुश्किल है। अगर कोई ऐसे आब्लैक्शनेबल शब्द हैं तो उसको एक्सपंज किया जा सकता है .....

चौ. प्रताप सिंह दौलता: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरी एक सबमिशन है। एक बार पहले भी यह सवाल पूछा गया था और उसका जवाब सुनकर मैं खामोश रहा। चेयर इस क्वैश्यन को अच्छी तरह एग्जामिन करवा ले कि एक आफिसर, चाहे उसका नाम लिया जाए, चाहे डी.सी. जींद कहा जाए, चाहे राम नारायण कहा जाए, कुछ भी कहें, जो चीज

*उपाध्यक्ष महोदया के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उसको आईडैटिफाई करती है और वह यहां पर आकर जवाब नहीं दे सकता, क्या उसकी बड़ाई की जा सकती है, जैसे हरद्वारी लाल ने बड़ाई की थी? जो चीज उस आफिसर को आईडैंटीफाई करती

है उसकी न कोई बड़ाई की जा सकती है और न बुराई की जा सकती है। आप इसको इग्जामिन करवा लें।

चौ. चांद राम: अगर बड़ाई न करें, तो डिस्कशन किस तरह होगी? –(व्यवधान)–

उपाध्यक्षा: एक चीज गुप्ता साहब की तरफ से आई है ओर एक दौलता साहब ने कही है। जहां तक मैं समझती हूं कि यदि किसी की तारीफ की जाए उसको हम नहीं रोक सकते मगर मैं इतना कह सकती हूं कि जो मैम्बर डैफामेटरी शब्द कहता है I will request the hon. Member, Ch. Dal Singh that he should not speak defamatory.

चौ. दल सिंह: यह तो आपने तजवीज कर दी है, जैसा आप कहेंगे मैं वह कह देता हूं, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर नहीं चाहते तो मैं 'चेयरमैन' क्यों कहूं, लेकिन 'चेयरमैन' तो एक बहुत बड़ा औहदा है। दूसरी बात यह है कि मैंने डी.सी. जीन्द, रामनारायण की बाबत कोई बात नहीं कही .....
.

उपाध्यक्षा: पर्सनल किसी अफसर का नाम लेकर या उसके पद को लेकर न कहें। हम यह कह सकते हैं कि फलां चीज में कमी रही, बोर्ड को कह सकते हैं, किसी भी संस्था को कह सकते हैं कि यह–यह कमी रही, मगर किसी अफसर को बाई–नेम या उसके पद के बाई–नेम कही जाए, तो उसको बाई–नेम समझा जाएगा। अगर आप उनका नाम ले लें, चाहे आप डिप्टी कमिश्नर

अम्बाला कहें, चाहे के.के.शर्मा कहें दें it is the same thing. So please avoid mentioning the name in any form.

श्री बनारसी दास गुप्ता: उपाध्यक्ष महोदया मेरा प्वांयट आफ आर्डर यह है कि आपने जो अभी आदेश दिया है, रूलिंग दी है, उसकी रौशनी में वे शब्द एकसपंज कर दिए जाएं जो इन्होंने कहा है कि चेयरमैन कुरप्ट है।

Deputy Speaker: If there is any word "corrupt" used, I will say that this word should be expunged.

Ch. Partap Singh Daulta: I want to bring to your notice that you cannot revise ro review a ruling given by the Chair. When Mr. Banarsi Dass Gupta was the Speaker, a ruling from the Chair, an observation in the form of ruling fell from his lips. That was to this effect that no officer by name or by offce can be praised or criticised when he is not in a position to answer it. This Ruling had been given in the very first session when Ch. Hardwari lal began to praise this very Chairman and I objected to it. The ruling is on record. You can examine your record.

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं आपका ध्यान नवम्बर के सैशन की तरफ दिलाना चाहता हूं।

उपाध्यक्षा: आप एक मिनट बैठें। दौलता साहब की तरफ से एक चीज आई है मुझे उसका जवाब देने दें। बात यह है कि वक्तन फवक्तन जब कोई चीज होती है, तो चेयर की अपनी–अपनी रूलिंग होती है। गुप्ता साहब की आपनी रूलिंग थी और मेरी

अपनी रूलिंग है। दूसरी बात यह है कि प्रेज का यहां कोई खास सवाल नहीं था। अगर गवर्नमैंट अच्छी है, तो किस तरह से यह कहा जा सकता है कि यह गवर्नमैंट अच्छी नहीं है। हां, डैफेमेटरी बात कोई भी किसी ऑफिसर के खिलाफ यहां नहीं कर सकता। अगर कोई कहेगा तो उसे मैं एक्सपंज कराऊंगी।

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो इसमें प्रेज (तारीफ) या क्रिटिसिज्म की कोई बात नहीं थी। अगर कोई ईमानदार है, उसे ईमानदार कहा जाए और अगर कोई बेईमान है, उसे बेईमान कहा जाए, तो इसमें कौन–सी गलत बात है? अगर कोई सेहतमन्द है, तो उसे मैं बीमार कैसे कहूं? खैर, मैं गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा अगर कोई गलत बात मैंने कह दी है। लेकिन एक बात डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं जरूर कहूंगा कि हमें बड़ा दु:ख होता है, जब करोड़ों रूपया हमारा इस तरह से जाया जाता है। अगर यह बात भी हम यहां न कर सकें, तो आप ही बताएं कि फिर लोग हमें यहां किस लिए भेजते हैं? हमें तो लोग चुनकर यहां इसीलिए भेजते हैं कि सही मायनों में हम उनकी नुमायंदगी करें, जो चीज जैसी हो, वैसा ही उसे कहा जाए। मैं तो डिप्टी स्पीकर साहिबा, फिर यह अर्ज करूंगा कि बिजली के महकमें ने जितनी जयादती की है, उसको ब्यान नहीं किया जा सकता।

आज, डिप्टी स्पीकर साहिबा, वैसे तो किसानों के गुणगान चारों तरफ हैं, लेकन वास्तव में उनकी हालत बहुत बुरी है। पानी ऊपर से बरसा नहीं, इन्होंने दिया नहीं और फसल का

सत्यानाश हो गया है। मैं तो अपनी जीन्द की ही बात आपको बताता हूं। पिछले काफी दिनों से जीन्द के अन्दर बिजली नहीं है। आई.पी.एम. साहब को अगर मेरी बात पर विश्वास न आता हो, तो वे बेशक इस बात का पता करा लें। बिना पते के यह बात कहना कि हम छः घंटे बिजली देते हैं, ठीक बात नहीं है। डिप्टी स्पीकर साहिबा बिजली और पानी उत्पादन बढ़ाने के लिए सबसे जरूरी हैं। इनका ठीक ढंग से प्रबन्ध होना चाहिए, तभी अनाज के मामले में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। आज हमारे प्रदेश और देश का अनाज की बहुत ज्यादा जरूरत है। फिर, डिप्टी स्पीकर साहिबा, ये रात को बिजली देते हैं। यह बात भी ठीक नहीं, क्योंकि इससे किसान को बड़ी भारी परेशानी होती है, लेकिन फिर भी चाहे कितनी सर्दी हो, किसान फसल को पानी तो देता ही है। कारखाने के अन्दर तो राम को काम हो सकता है, लेकिन खेत के अन्दर का काम करना बड़ा मुश्किल है। वहां तो 20 गज तक, 100 गज तक, 200 गज तक और हजार–हजार गज तक का पानी जाता है, और अगर थोड़ा–सा भी पानी खराब हो जाए, तो न सिर्फ जमींदार को नुक्सान होता है, सरकार को नुक्सान होता है, बल्कि सारे नेशन को नुक्सान होता है। तो मैं गुजारिश करूंगा कि यदि हो सके, तो दिन में किसान को पानी देने का इन्तजाम कीजिए। मैं इस सम्बन्ध में, डिप्टी स्पीकर साहिबा, कुछ सुझाव भी देना चाहता हूं। यह बात सर्वविदित है कि बिजली के महकमें के अन्दर रिश्सत का बाजार गर्म हैं इसका चैक किया जाना चाहिए। मैं इसके लिए सुझाव देना चाहता हूं। सरकार को यह पता है कि

हरयिाणा प्रान्त में इतने बिजली के टयूबवैल्ज हैं, इनको यह भी पता है कि इतनी हौर्स पावर के मीटर्ज हमारे यहां लगे हुए हैं, सरकार को यह भी पता है कि कितने बिल्ज बनते हैं, सरकार को यह भी पता है कि कितनी आमदनी माहवार होती है और सरकार को दूसरी सारी बातों का भी पता है। मान लीजिए कि किसी के मीटर का एक रूपया रैंट हे और पांच रूपया उसका खर्चा आता है, तो आप किसान से पर–हौर्स पावर 6 रूपए ले लें। इसमें हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि डायरैक्ट कुनैक्शन कर दिया जाए, जिस तरह कि पंजाब में है। इससे फायदा क्या होगा? लाखों मीटर बचेंगे। इस वक्त 149160 मीटर्ज हैं। तो आप देखें की कितने मीटर बचे और करोड़ो की तादाद में जो रूपया इनको खरीदने में खर्च होता है, वह बचेगा, फिर इनकी रिपेयर में जो पैसा खच्र आता है, वह बचेगा, मीटर रीडर्ज पर जो लाखों रूपया खर्च होता है, वह बचेगा, बिल बुक्स जो छपती हैं, उनका खर्चा बचेगा और सबसे ज्यादा किसान को जो डिफिकल्टी होती है वह नहीं हो पाएगी। आप इस बात पर कृपया जरा सोचे लें। एक हौर्स पावर पर आप चाहे कितना खर्च रख लें, लेकिन डायरैक्ट कुनैक्शन कर दीजिए। इससे न एम.सी.जी. का चक्र रहेगा, न क्लर्क का चक्र रहेगा और न ही रिश्वत की बात रहेगी। सारी बीमारी ही मिट जाती है। मैं उम्मीद रखता हूं कि आई.पी.एम. साहब इस तरफ ध्यान देंगे। डिप्टी स्पीकर साहिबा, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे पड़ौस वाले प्रांत पंजाब में यह बात की गई हैं उनके तजुर्बे से हमें फायदा उठाना चाहिए।

श्री बनारसी दास गुप्त: डिप्टी स्पीकर साहिबा, सदन की सूचना के लिए मैं बता दूं कि वे भी अब फ्लैट रेट वाली बात का बदल रहे हैं। अभी एक महीने के अन्दर अन्दर ये इस बात को देख लेंगे।

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मेरा यह सुझाव है। ये मानें या न मानें इनकी मर्जी है। मैंने तो एक बात कह दी है कि यह किसान के हित में है। अगर इन्हें उससे हमदर्दी है, तो माल लें और उसे अगर इन्होंने बर्बाद ही करना है, तो न मानें।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, गवर्नर साहब ने जो अभिभाशण यहां पढ़ा है, उसके सफा 4 पर लिखा है:–

> ''समय की मांग है कि कृशि उत्पादन को अधिक से अधिक बढ़ाया जाए। यह अत्यन्त सन्तोशजनक बात है कि राज्य सरकार ने अपनी स्कीमों में कृशि–उत्पादन को सबसे अधिक प्राथमिकता दी है।''

इसके बाद उन्होंने सिंचाई स्कीमों का जिक्र किया है। डिप्टी स्पीकर साहिबा, इस सम्बन्ध में भी मैं फिर उसी किताब से आंकड़े देना चाहता हूं और यह बताना चाहता हूं कि इसके अन्दर सच्चाई कहां तक है। यह 1973–74 का स्टैटिस्टिकल ऐब्स्ट्रैक्ट है। इसके अनुसार सन् 1966–67 के अन्दर, जब हरियाणा प्रान्त बना था, अनाज की पैदावार 2592000 टन थी। इसके बाद यहां

1967–68 में विरोधी दल की सरकार बनी और उस वक्त अनाज की पैदावार 3970000 टन हुई। तो आप देखें कि एक साल के अन्दर कितनी बढ़ौत्तरी हुई थी? यह हुई थी 1378000 टन। उसके बाद यह सरकार लगातार चलती आई है। 1968–69 में पैदावार हुई 2754000 टन। अब आप देखें कि एक साल में पैदावार 3970000 टन से घटकर 2754000 टन पर आ गई। इस मौजूदा सरकार के रिजीम में कितनी कमी हुई एक साल के अन्दर 1216000 टन जबकि विरोधी दल की सरकार के वक्त में एक साल में 1378000 टन की बढ़ौत्तरी हुई थी। 1969–70 में पैदावार कुछ बढ़ी और यह हुई 4626000 टन। 1970–71 में 4771000 टन पैदावार हुई, 1971–72 में फिर यह घटकर 4543000 टन रह गई और 1972–73 में केवल 4007209 टन रह गई। इसका दूसरा पहलू, डिप्टी स्पीकर साहिबा और भी मजेदार है। ये कहते हैं कि सन् 1968–69 में हरियाणा प्रान्त में 29000 टयूबवैल्ज थे लेकिन अब कितने हैं, यह देखने की बात है। इसके बारे में एक जगह तो ये कहते हैं कि 149160 हैं और दूसरी जगह कहते हैं कि 133000 हैं। कोई सी भी बात मान लो, यह बात तो ठीक है कि टयूबवैल्ज बढ़े हैं। अगर इस फिगर को 133000 ही मान लिया जाए, तो भी 104000 टयूबवैल्ज इनके बढ़े हैं। अनाज तो, डिप्टी स्पीकर साहिबा, 1972–73 में इनका बढ़ा है 27209 टन, परन्तु टयूबवैल्ज बढ़े हैं 104000। तो यह हे इनकी सही पोजीशन।

डिप्टी स्पीकर साहिबा, यहीं बस नहीं। आगे भी गवर्नर महोदय ने बहुत कुछ फरमाया है। ये भी बहुत कुछ कहते रहते हैं। एक सवाल के जवाब में यहां कहा गया कि इन्होंने टयूबवैल्ज ही नहीं लगाए, बल्कि हरियाणा को खुशहाल कर दिया। बड़ा भारी पानी पहुंचा दिया, बड़ी भारी इसके अन्दर नहरें निकाल दीं। नहरें कहां निकाली हैं, लोग जानते हैं। क्या हमारे साथ सलूक हुआहै इसको भी लोग जानते हैं। खैर, इस तरफ मैं ज्यादा न जाते हुए एक बात और अर्ज करना चाहता हूं। डिप्टी स्पीकर साहिबा, सन् 1968 में हरियाणा के अन्दर 4399000 एकड़ रकबा नहरी था।

उपाध्यक्षा: चौधरी साहब, आप कितना टाईम और लेंगे?

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, बड़ी कमाल की बात हैं अभी तो मुझे बोलते हुए बहुत थोड़ा टाईम हुआ हैं। मैं कोई गलत बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए फ्री टाईम मिलना चाहिए।

Deputy Speaker: I have only asked the hon. Member as to how much more time he will take?

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं एक लफ्ज भी गलत कहने के लिए तैयार नहीं हूं। जो कुछ सरकार की तरफ से कहा गया है, उन्हीं के बारे में मैं अपने विचार प्रकट कर रहा हूं।

उपाध्यक्षा: मैंने तो सिर्फ इतना पूदा था कि कितना टाईम आप और लेंगे?

चौ. दल सिंह: मुझे बोलते हुए केवल पन्द्रह मिनट हुए हैं और कोई बोलने वाला नहीं है। इसलिए मुझे खुला टाईम मिलना चाहिए।

श्री बनारसी दास गुप्त: क्या कोई और नहीं बोलगा?

चौ. दल सिंह: बिल्कुल नहीं बोलेगा।

श्री बनारसी दास गुप्त: चौ. राम लाल जी क्या यह बात ठीक है? –(शोर)–

चौ. राम लाल वधवा: इसका मतलब यह है कि इनकी पार्टी की तरफ से कोई नहीं बोलेगा ....(विघ्न).....

चौ. दल सिंह: डिप्टी स्पीकर साहिबा, मैं कहना चाहता हूं कि सन् 1968 में हरियाणा प्रान्त में 43 लाख 99 हजार एकड़ जमीन को पानी मिलता था। 1973 के अन्दर नहरों की सिंचाई का रकबा जो इन्होंने बताया, वह 61 लाख 21 हजार एकड़ था। इस तरह से 1968 से लेकर 1973 तक 17 लाख 22 हजार एकड़ रकबा को अधिक पानी दिया है। टयूबवैल्ज की तादाद बढ़ी है एक लाख चार हजार और नहरी रकबा बढ़ा है 17 लाख 22 हजार एकड़ और पैदावार बढ़ी है 37 हजार 209 टन। आप एस्टीमेट लगा लीजिए और इसको तक्सीम कर लीजिए, तो स्पीकर साहब आप यह बात सुनकर हैरान होंगे कि हरियाणा प्रान्त की सरकार एक टयूबवैल्ज के ऊपर दो क्विंटल 60 किलो अनाज पैदा कर सकी

है। आई.पी.एम. साहब तो हिसाब के मामले में ज्यादा होशियार हैं, वही अन्दाजा लगा लें।

मुख्यमंत्री (चौ. बंसी लाल): हकीकत यह है कि इनकी तो दुकान है, इसलिए हिसाब तो ज्यादा इनको आना चाहिए।

(इस समय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

चौ. दल सिंह: मैं कहना चाहता हूं कि एक टयूबवैल पर दो क्विंटल 60 किलो अनाज पैदा हुआ है। हरियाणा सारे देश के अन्दर .....

श्री अध्यक्ष: चौ. दल सिंह जी आपने खासा टाईम ले लिया है, इसलिए आप वाईड–अप करें।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, मैं कोई बात गलत तो नहीं कह रहा हूं। अब तो चीफ मिनिस्टर साहब भी तशरीफ ले आए हैं। अब तो मुझे बोलने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: आपने सब से ज्यादा टाईम लिया है।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, ज्यादा टाईम तो नहीं हुआ है। स्पीकर साहब, मेरे को एक देहाती मिसाल याद आ गई। वह मैं कहना चाहता हूं। हामरे यहां देहात में कहते हैं कि अगर कोई साधू हो, तो अपनी उम्र बढ़ाकर बताता है ओर कोई वैश्या हो, तो वह अपनी उम्र घटाकर बताती है। सिकी ने साधू से पूछा, कयों बाबा आपकी उम्र कितनी है? तो साधू ने जवाब दिया कि 80

साल, लेकिन उसकी उम्र थी तीस साल। फिर वैश्या से पूछा कि तुम्हारी उम्र कितनी है तो उसने जवाब दिया कि मेरी उम्र तीस साल है, लेकिन उसकी उम्र 80 साल की थी। तो फिर एक थर्ड पर्सन ने पूछा कि आपकी उम्र कितनी है, उसने जवाब दिया कि मेरी उतनी ही है कि जितनी बाबा जी ने बढ़ाई और वैश्या ने घटाई। मेरी उम्र 50 साल है। यही हालत हरियाणा सरकार की है। आंकड़े देती रहेगी। तारीफ करती रहेगी। पैदावार में बढ़ोत्तरी कोई नहीं, वहीं की वहीं है।

श्री अध्यक्ष: टाईम का पता लगाया है। आपने सबसे ज्यादा टाईम लिया है। इसलिए टाईम लिमिट लगानी पड़ेगी।

चौ. दल सिंह: टाईम लिमिट न लगाएं तो ठीक रहेगा। मैं अर्ज कर रहा था कि जहां तक किसानों के साथ .....

श्री अध्यक्ष: आपको बोलते हुए पचास मिनट से ज्यादा हो गए हैं।

चौ. दल सिंह: आप जवाब मना करेंगे, तो मैं जबरदस्ती तो क्या कर सकता हूं, लेकिन दो भाई पहले जो बोले हैं, उनका किसी ने मना नहीं किया।

श्री अध्यक्ष: आपको बोलते हुए उनसे ज्यादा टाईम हो गया।

चौ. दल सिंह: टाईम होने के लिए है। टाईम तो जाएगा ही। तो मैं अर्ज करूंगा कि एक तरफ तो सरकार किसानों की हमदर्द बनती है, दूसरी तरफ सरकार का यह नमूना है। जो खाद का कट्टा आज से छः साल पहले 20 रूपए का आता था, आज वह 100 रूपए का आता है। पांच सौ गुणा खाद की कीमत बढ़ी हैं कनक की कीमत सन् 1968 में 76 रूपए थी और आज सन् 1975 में 105 रूपए क्विंटल है। छः साल के बाद तीस परसैन्ट है। एक साल में पांच परसैन्ट बढ़ी है। लोहे और डीजल की कीमतें भी बहुत ज्यादा बढ़ी हैं।

चौ. बंसी लाल: 1969 में, चौ. दल सिंह जी भी उन दुकानदारों में से है, जिन्होंने 60 के भाव भी गेहूं नहीं लिया।

चौ. दल सिंह: इतनी ज्यादती किसानों के साथ हुई है। ट्रैक्टरों की कीमत, बिजली के रेट तो किसानों के तपड़ ही उल्टा दिए हैं। यही नहीं, हरियाणा सरकार ने लैण्ड टैक्स लगाया और चीफ मिनिस्टर साहिब यहां पर हाजिर हैं, उन्होंने फरमाया था कि हम तीन करोड़ रूपए का रैवेन्यू वसूल करेंगे। इस ऐक्ट के तहत जमीन की भिन्न–भिन्न किस्में बनाई गई हैं और उसी के अनुसार टैक्स की दरें बनाई गई हैं, परन्तु जिन गांवों के अन्दर बूंद भी पानी नहीं जाता है, वहां बरानी जमीन को भी नहरी करार दिया गया। मेरी अपीन कांस्टीच्युएंसी में दोनों झांज, जाजवान, बड़ौदी, जाजवान खेड़ी, दरियावाला और कितने गांव हैं जिनमें पानी नहीं के बराबर है, परन्तु नहरी जमीन करार दी गई। हरियाणा की

सरकार टैक्स वसूल करने जा रही है और वह तीन गुणा टैक्स होगा। तो मैं लीडर आफ दी हाउस से दरख्वास्त करूंगा कि वे तहकीकात कराएं अगर वाकई ही मेरी बात सच हो, तो उनकी जमीन को नहरी जमीन करार नहीं दिया जाना चाहिए। आपने ऐक्ट बनाया है, उस ऐक्ट की पूरी पालना होनी चाहिए। अगर कोई उसकी अवहेलना करता है, तो वह कसूरवाल है, हम सब हैं। लैण्ड सीलिंग ऐक्ट यहां हाउस में दो बार लाया गया, लेकिन आज हरियाणा प्रान्त के अन्दर इस किस्म के साहूकार मौजूद हैं, जिनके कारखानों की आमदनी दस हजार रूपए रोजाना है, हजार रूपए रोज है, और पांच सौ रूपए रोज तो बहुत कमाते हैं, परन्तु उन पर कोई सीलिंग नहीं लगाई गई, मैं यह कह सकता हूं ईमानदारी के साथ कि हरियाणा प्रान्त के अन्दर किसी भी किसान की आमदनी पांच सौ रूपए रोजाना नहीं है और यह सरकार उसी पर टैक्स लगाती है। जुलाई के महीने में 1.5 करोड़ रूपए की डयूटी बढ़ाई गई है। टैक्स लगाया, यह कितनी ज्यादती है और यह डर दिखा कर कि तुम्हारी जमीन छिन जाएगी। हरियाणा में जमीन है कहां पर? 85 परसैन्ट के पास पांच एकड़ है। नौ करोड़ रूपए के एस्टाम हरियाणा के किसानों ने खरीदे। इस तरह से सरकार ने उन्हें लूटा। हरिजनों को बहकाया गया कि तुम्हें जमीन देंगे। हरिजनों को बहका का बेचारों को हजारों को खस्सी करा दिया, लेकिन एक खूड भी जमीन नहीं दी। सरकार किसान से 105 रूपए प्रति क्विंटल के भाव पर गेहूं खरीदती है और उसी कनक को दस गज के फासले पर दूसरी दुकानों में रखकर हरिजनों को 152

रूपए प्रति क्विंटल के भाव पर बेचती है, जोकि बड़ा भारी अन्याय है।

चौ. बंसी लाल: एक तरफ तो चौ. दल सिंह जी कहते हैं कि हरिजनों को जमीन नहीं दी। दूसरी तरफ कहते हैं कि हरियाणा में जमीन है कहां। यह सैल्फ कन्ट्राडिक्ट्री स्टेटमैंट है।

चौ. दल सिंह: मैं अर्ज कर रहा था कि यह गलत कहते हैं। यह हरिजन को कहां से जमीन देंगे। फैमिली प्लानिंग के बारे में आपको सुनकर हैरानगी होगी कि खरखौदा के अन्दर सितम्बर महीने में 80 लड़कों का आप्रेशन कर दिया, जो 16 ओर 20 साल के थे। स्पीकर साहब मैं चैलेन्ज करना चाहता हूं डाक्टर की बात को, और आप चाहे बेशक इन्क्वायरी करवा लें, उनमे ंऐ एक भी खरखौदा गांवों का या देहात का नहीं है। अगर मैं गलत हूं तो चाहे जो सजा आप मुझे देना। आप यह जुल्म है। आज मूरथल के अन्दर 173 की नसबन्दी हुई। 17 आदमी मूरथल के हैं, बाकी सारे बाहर के हैं, दिल्ली से दल्ले आते हैं, हरियाणा का नाम बदनाम करते हैं। इसके बाद दोबारा फिर खरखौदा में चन्द विद्यार्थियों की नसबन्दी नौकरी देने का बहाना बनाकर की गई। लोगों ने वहां पर डिमानस्ट्रेशन किया, जिस पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया। यह सारी नसबन्दी बी.डी.ओ. की मार्फत कराई गई। हर केस पर 120 रूपए लिए गए, जिसमें से केवल 20 रूपए उन गरीब बच्चों को देकर बाहर कर दिया और बाकी सीमेन्ट के कट्टे बी.डी.ओं. साहिबा हजम कर गए। आज हरियाणा प्रान्त में सीमेंट उसको

मिलता है, जो नसबन्दी कराता है। इन्तकाल उसका तसदीक होता है, जो नसबन्दी कराए। तमाम नगरपालिकाओं के कर्मचारियों को और पटवारियों को हुक्म दिया हुआ है कि वह नसबन्दी कराएं, अन्यथा उनकी इन्क्रीमैंट बन्द हो जाएगी। आज तमाम इडमिनिस्ट्रेशन ठप्प होकर रह गया है और एक ही बात के पीछे है कि ठीक लोग गलत ढंग से दबाव से नसबन्दी कराई जाए। पुलिस में कोई रिपोर्ट दर्ज कराने जाए तो कहते हैं कि नसबन्दी कराओ। तमाशा बनाया हुआ है। जिसका नतीजा यह है कि किसान टयूबवैल्ज नहीं लगा सकता। कोई मकान की मरम्मत नहीं कर सकता, कोई इंडस्ट्री नहीं लगा सकता और न ही मकान बना सकता है। सारा कारोबार ठप्प हो गया है।

अध्यक्षः आपका टाईम हो गया।

चौ. दल सिंहः बात तो स्पीकर साहब सारी ही रह गई। मैंने तो कुछ भी नहीं कहा।

श्री अध्यक्षः काफी टाईम हो गया। बहुत से आनरेबल मैम्बर गवर्नर एड्रैस पर भी बोलना चाहते हैं। इस ढंग से तो अब तक तीन ही मैम्बर बोले हैं, फिर पांच–दस मिनटर ही एक मैम्बर को देने पड़ेंगे। अगर हाउस की मर्जी है, तो फिर टाईम लिमिट फिक्स कर देते हैं।

चौ. चांद राम: स्पीकर साहब चौ. दल सिंह तो हम चारों की तरफ से बोल रहे हैं। मूवर के बाद तो मेन स्पीच है। इनपर तो टाईम लिमिट नहीं लगनी चाहिए।

चौ. दल सिंह: स्पीकर साहब, हरियाणा की माली हालत क्या है? ये कहते हैं कि हमने डैम बना दिए। स्पीकर साहब तमाम की तमाम चीजें अन–प्रोडक्टिव, अन–प्लान्ड स्कीमों पर पैसा खर्च किया गया है। कोई भी प्रजातन्त्र की सरकार हो, उसका यह फर्ज है कि उस स्कीम पर रूपया खर्च करें, जिससे आम जनता की भलाई हो, लेकिन यहां पर क्या कार्य किया गया? लेक बनवाई, झील बनाई। मेरे दोस्त डूबता चाहते हैं, हम डूबोना नहीं चाहते। हम सही सलामत चाहते हैं। यहां पर रैस्ट हाउसिज बनाए जा रहे हैं। रैस्ट हाउसिज भी ऐसे, जिसमें गर्मी न लगे और सर्दी भी न लगे। मोटल और होटल और हवाई जहाज खरीदे जा रहे हैं। 5 लाख का हवाई जहाज खरीद रहे हैं। सात जिलों से 10 जिलें बना दिए। तीन डिप्टी कमिश्नर बढ़ दिए। अब एक मोटर बनारहे हैं, जींद के अन्दर, हमारे मुख्यमंत्री जी ने फरमाया कि दो लाख में यह मोटर बन रही है। किस लिए बन रही है, इसलिए ए बन रही है कि जीन्द से अफसर चण्डीगढ़ बैठ कर जाया करेंगे।

आज हरियाणा प्रान्त की माली हालत क्या है? तीन सौ करोड़ का कर्जा हरियाणा प्रानत पर है और दो सौ करोड़ रूपए का कर्जा बिजली बोर्ड पर है और रोज हरियाणा सरकार कर्जा मांगती है। आपने किया क्या है, यह भी जरूर सुन लो। स्पीकर

साहब, सन् 1970–71 में सरकार ने 8 करोड़ 80 लाख रूपऐ सूद दिया। 1971–72 में कर्जे का 9 करोड़ 74 लाख रूपए दिया। 1972–73 में कर्जे का 11 करोड़ 41 लाख रूपए सूद दिया। 1973–74 में कर्जे का सवा तेरह करोड़ रूपए दिया सूद दिया। तो मैं बताना चाहता हूं कि 8 करोड़ से शुरू होकर 13 करोड़ तक चार साल में इस सरकार ने सूद दिया है। इस तरह से हरियाणा प्रान्त का कैसे भला हो सकता है? क्या कोई इस बात को मानेगा? हरियाणा में जब हम पूछते हैं– स्कूल होंगे, नहीं, कोई डिस्पैंसरी होगी – नहीं, टूटी हुई सड़कें हैं, इनको ठीक बनवाएंगे – नहीं। क्यों नहीं बनवाते? कहते हैं पैसा नहीं है। हमेशा यही कहते हैं नान अवेलेबिलिटी आफ फण्डज। एक अंग्रेजी का लफ्ज आ गया 'अवेलेबल'। कब फण्डज अवेलेबल होंगें? मैं यह कहता हूं कि अगर यही सरकार रही तो फंडज अवेलेबल होने का सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारे ये दोस्त तो दिवाला निकाले बैठे हैं। फण्डज तब अवेलेबल हो सकते हैं, जबकि आपके दिल के अन्दर हरियाणा प्रान्त की भलाई का कोई जजबा हो। फण्डज की बात करना चाहता हूं कि नान–अवेलेबिलिटी आफ फण्डज का खत्म हो सकती है? क्या जरूरत थी 10 जिलों की? क्या जरूरत थी दो कमिश्नरों की? क्या जरूरत थी 5 डी.आई.जी. बनाने की? फोर्स की फोर्स सारी पुलिस के अन्दर धकेल दी, क्या बात है, यही हालत प्रान्त के अन्दर सर्विस की है। हरियाणा प्रान्त की माली हालत जब तक ठीक नहीं होगी, तब तक कोई काम बनने वाला नहीं है। नान–प्लान और अन–प्रोडक्टिव स्कीमों पर खर्च होने की

बदौलत इतना खर्चा है और इसी वजह से इतना सूद देना पड़ा है।

स्पीकर साहब, कानून की व्यवसाि बहुत ही जरूरी है। अगर स्टेअ में कानून नहीं है, तो कोई बात नहीं है। हमने पिछली बार भी कहा। यहां पर बड़े–बड़े कांड होते हैं, चोरियां होती हैं ओर डकैतियां होती हैं। मैंने पिछले सैशन के अन्दर स्पैसिफिक केस व नाम दिया था। मैं आज भी वह बात कहना चाहता हूं। मैं होम मिनिस्टर से और मुख्यमंत्री साहब से कहता हूं कि दम है तो मेरै साथ चलो, मैं बताता हूं कि चोरी का सामान कहां है? मैं वह बरामद कराता हूं कि यह रहा, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मैजिस्ट्रेट के घर में चारी, एस.डी.एम. के घर में चोरी होती है, लेकिन कोई नहीं पूछता। मेरे साथी जोशी साहब कह रहे थे कि गुलाटी साहब के पैसे निकाल लिए। कहां गए थे? कहीं यू.पी. एकान्त भवन में। हरियाणा में नहीं, यू.पी. के एकान्त भवन में मीटिंग होती है, यू.पी. के भवन में। हरयिाणा में नहीं, यू.पी. के एकान्त भवन में मीटिंग होती है, यू.पी. के भवन में जाकर मीटिंग होती है। हरियाणा प्रान्त का दिवला निकालने के बाद, हरियाणा प्रान्त को तबाह करने के बाद आप बिहार में और यू.पी. में मीटिंग करते हैं। आज हरियाणा प्रान्त के हरिजनों की हालत क्या है? आज हरियाणा प्रान्त के बैकवर्ड क्लासिज की हालत क्या है? कोई भी देखकर बर्दाश्त नहीं कर सकता। आज हरियाणा के किसान की क्या हालत है? किसान को तबाह करने पर तुले हुए हैं। गुलाटी

साहब के पैसे काढ़ लिए और पुलिस इतनी बढ़िया कि रूपए वसूल कर लिए। मैं कहता हूं कि जींद जिले के एक मोहलखेड़ा में जो चोरी हुई थी, उस चोरी का सामान मैं कल ही पकड़वाता हूं। सरकार में दल है तो मेरे साथ चलो। अगर मैं न बरामद करवाऊं, तो मुझे लानत कहना। आज हरियाणा प्रान्त की यह हालत हे कि साजिश से कत्ल होते हैं, साजिश से चोरियां होती हैं, और साजिश से सारे काम होते हैं। गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। उसको कोई सुनने वाला नहीं है। रिश्वत का बाजार गर्म है। आज हरियाणा प्रान्त की बद से बदतर हालत है। इस हालत के अन्दर भी आज अगर कोई यह कहे कि हरियाणा प्रान्त बड़ा तरक्कीयाफ्ता मुल्क है, हरियाणा प्रान्त ने बड़ी भारी तरक्की की है, तो भगवान ही बेली है।

स्पीकर साहब, मैं एक बात की ओर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। प्रजातन्त्र के अन्दर सरकार की कभी विक्टेमाइजेशन नहीं करना चाहिए। यह ठीक ळै कि हम माइनौरिटी में हैं। हम मानते हैं। यह तो ऐडमिटिड फैक्ट है और सरकार जो चाहे, पास करा सकती है। यह बात ठीक है। अगर सरकार इस बात पर सोचे कि हमारे हाथ में डण्डा है, हमारे हाथ में ताकत है, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो यह कोई अच्छी बात नहीं है। प्रजातन्त्र के अन्दर सबसे जरूरी बात है प्रैस और प्लेटफार्म। यहां पर क्या है? प्रैस पाबन्दी, प्लेटफार्म पर पाबन्दी। पोल्हू को पकड़ लिया। किस लिए? वह नरवाना चला गया, थानेदार साहब से

मिलने के लिए। थानेदार था नहीं। बस–स्टैण्ड को चला आया। थानेदार साहब को पता लगा कि पोल्हू आया था। कहने लगे–कहां है? उन्होने कहा – अड्डे पर। जाकर पकड़ लाओं। प्राइम मिनिस्टर को 30 तारीख का दौरा था और वह कुछ करना नहीं चाहता था। हमने कहा था कि हम 5 तारीख को रोहकत के अन्दर कान्फ्रैस करेंगे। आप यह बात सुनकर हैरान होंगे कि हरियाणा की तमाम बसिज को ठहराया गया। उनमें कोई सवारी नहीं ली गई। इससे हरियाणा सरकार का बड़ा भारी नुक्सान हुआ है और यह बहुत घातक बात प्रजातन्त्र के खिलाफ हुई है। वहां पर हाजरी कितनी थी? मैं तो नहीं कहता, अखबार लिखता है। मैं तो कहता हूं कि दो–तीन लाख थी। चलो, हमारी बात न मानो, अखबार की बात तो मान लो कि एक लाख थी। यह ठीक बात थीं, गलत बात नहीं। मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रजातन्त्र के अन्दर प्रैस और प्लेटफार्म को छूट होनी चाहिए। यह ठीक है कि इख्तलाफात होते हैं, लेकिन आपकी मनमर्जी चलती है। आप 5000 ट्रक ले गए और जबरदस्ती ले गए। इनको यह अहसास नहीं कि 5 हजार ट्रकों के अन्दर कितना डीजल खर्च हुआ है? 6–7 लाख रूपए का डीजल खर्च हुआ होगा। आज किसान रोता है। उसके टयूबवैल पर ईजन है और उस ईजन को चलाने के लिए डीजल नहीं और हरियाणा की सरकार जबरदस्ती पकड़ कर डिमांस्ट्रेशन करवाती है। इनको किसान की कोई परवाह नहीं, उत्पादन की कोई परवाह नहीं और देश की कोई परवाह नहीं। इन्होंने तो इंदिरा गांधी का जलसा कामयाब कराना है, बस यह परवाह है।

हम यह नहीं चाहते कि आप ऐसा न करें, लेकिन जिस तरीके से आप करना चाहते हैं, वह तरीका गलत है, वह ढंग गलत है। लोगों को जबरदस्ती पकड़ कर लाओ, तो इसका असर क्या होता है? इसका उल्टा असर पड़ता है, क्योंकि जिस चीज को आप कुचलोगे जिस चीज को आप दबाओंगे, जिस चीज पर ज्यादती करोंगे, लोग उसके लिए रिवोल्ट करेंगे। अगर आप काम करेंगे तो लोग जरूर कहेंगे कि गलत बात थी। उकलाना के पास रास्ते में ट्रक का ऐक्सीडेंट हुआ और 5 आदमी मर गए, लेकिन ये मानते ही नहीं है। –(व्यवधान)– यह अजीब तमाशा है कि अगर कोई बोलता है, तो लाठी चलवाते हैं –(व्यवधान)–

श्री बनारसी दास गुप्त: उस रोज तो आप कह रहे थे कि 4 आदमी लाठी चार्ज से मर गए लेकिन आज आप कह रहे हैं कि ट्रक उलटने से 5 आदमी मर गए। इसमें से कौन सी बात ठीक मानें? –(व्यवधान)–

चौ. दल सिंह: स्पीहर साहब, मैं यह कहना चाहत हूं कि जो कुछ मैंने कहा है, वह रिकार्ड पर है। उसे निकलवा कर देख लें। अगर मैंने लाठी चार्ज से कहा हो, तो मैं सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। अखबार में कोई बात आ जाए, तो वह मेरी जिम्मेवारी नहीं है। एक कलकत्ता के अखबार ने तुम्हारी तारीफ कर दी। ठीक है, तुमने करवा ली होगी। अखबार में तो कल परसों आपके जैन साहब ने यों फरमाया है कि सोमवार को असैम्बली नहीं। अखवार वालों ने छाप दिया कि सोमवार को

असैम्बली नहीं, तो क्या अखबार वालों का कसूर है? किसी ने अखबार वालों को कह दिया होगा। लेकिन आप यहां का रिकार्ड निकलवा कर देख लें। स्पीच भी मौजूद है और टेप–रिकार्ड भी है। मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि उस जलसे के लिए कितनी पाबन्दी और अपने जलसे के लिए कितनी छूट। इससे सरकारी पक्ष को भी नुक्सान होता है, क्योंकि लोग यह समझते हैं कि सरकार धक्केशाही करती है। करनाल के अन्दर इन्होंने डण्डे बरसवाए। जब शिकायत लेकर दिल्ली गए तो प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार के खिलाफ बगावत करते हो और हमारे से ही रियायत चाहते हो? मैं सरकार से यह कहना चाहता हूं कि अगर वह किसान के साथ ज्यादती करती है, हरिजन के साथ ज्यादती करती है या अपने कर्मचारियों के साथ ज्यादती करती है, तो वह दिन दूर नहीं, तुम देख लेना भई, जब इलैक्शन होगा तो लोग आपको यूं कहेंगे कि तुम हमें जबरदस्ती रोहतक ले जाते थे, तुमने हमारे ऊपर जबरदस्ती लाठी मरवाई थी, तुमने जबरदस्ती हमारी नसबन्दी करी थी, तुमने हमारे ऊपर झूठा केस बनवाया था, इसलिए कोई वोट नहीं, तुम्हारी छुट्टी। यह कहेंगे सारे के सारे। आज गुस्ताखी माफ हो। आप कोई गलत कदम न उठाएं। कहीं ऐसा न हो कि आपको पछताना पड़ जाए और हमें बड़ी परेशानी उठानी पड़ जाए। –(व्यवधान)– स्पीकर साहब, एक और बड़ी अहम बात है।

एक भाई द्वारा यहां पर विद्या का जिक्र किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हरियाणा धर्म–प्रधान देश है।

हिन्दुस्तान के लोग धर्म में आस्था रखते हैं। हम यह मानते हैं कि वेद भगवान के रचे हुए ग्रन्थ हैं। हमारे वेद कहते हैं कि 'मातृमान पितृमान आचार्य मान पुरूशोवेद।' हमारे वेद क्या कहते हैं। हमारे वेद लोगों से यह कहते हैं कि माता, पिता, और गुरू की इज्जत करो और हरियाणा की सरकार के एक भाई जिन्होंने मोशन मूव किया था, उन्होंने यह बात कही कि टीचर का यह काम नहीं कि वह बच्चों को भड़काता रहे। कमाल है। ये गुरू को नहीं मानते? गुरू कौन होता है? मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक गुह की इज्जत नहीं करेंगे, तब तक हरियाणा प्रान्त के अध्यापकों का आप खुश नहीं करेंगे, आप कितनी ही जोर लगाएं, हरियाणा प्रान्त तरक्की नहीं कर सकता। उन्होंने एजीटेशन किया। यहां समझौता हुआ। उसके बाद आज तक भी विकेटमाइजेशन हो रही है। सोहन लाल जैसे शरीफ आदमी के ऊपर रेप का केस बनाना सरकार के ऊपर लानत है। कोई आदमी खुश हो ले, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि

18.00 बजे

पब्लिक खुश नहीं है। पब्लिक की आवाज है कि गलत बात नहीं होनी चाहिए –(विघ्न)– कुरूक्षेत्र के अन्दर एक महीने से तमाशा बना रखा है। पांच लड़कों को एक्सपैल कर दिया। 190 लड़कों को ब्लैक लिस्ट कर दिया। खुदाई हाथ में ले रखी है। मैं कहना चाहता हूं कि जुल्म करने वाला औरंगजेब यहां नहीं रहा, जुल्म करने वाला कोई बदमाश यहां नहीं रहा। मैं तो यह कहता हूं कि

अगर हरियाणा सरकार भी जुल्म करेगी, तो यह भी नहीं रहेगी। अगर हरियाणा की तरक्की करना चाहते हैं तो वह बच्चों की तरक्की से होगी और बच्चों की तरक्की तब होगी, जब अध्यापक खुश होंगे, जब उनकी इज्जत होगी। अगर आप उन पर झूठे मुकदमें बनाएंगे तो हरियाणा की तरक्की नहीं हो सकती। आज उनका विकटिमाइजेशन किया जा रहा है। एक मिनट में उसका ट्रांसफर होता है। आज वह यहां है, तो कल शाम दूसरी जगह उसका ट्रांसफर और परसों शाम किसी और जगह पर उसको भेज दिया जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि उससे क्या खतरा है। क्या वह बम बनाता है, क्या वह बन्दूक बनाता है? मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि हरियाणा की उन्नति के लिए सबसे जरूरी है कि कुरूक्षेत्र में जो गलत काम किया है, उसको विदड्रा करो। जिस टीचर के खिलाफ कोई कार्यवाही की है, अगर शर्म है, तो माफी मांगो। अगर आप महात्मा गांधी के सिद्धान्त पर चलने वाले हो, तो पब्लिक में जाकर माफी मांगो। महात्मा गांधी अपनी गल्ती को तसलीम करते थे और विदड्रा करते थे –(विघ्न)–

स्पीकर साहब, अब मैं चन्द सुझाव देना चाहता हूं। बिजली बोर्ड और विद्यार्थियों के बारे में सुझाव दिए हैं। अगला सुझाव मेरा यह है कि आप किसानों के साथ ज्यादती न करें। हकीकत में जितना लैंड टैक्स बनता हो, वह उससे लें, ज्यादा वसूल न करें। प्रजातन्त्र की आप धज्जियां न उड़ाओ। आई.पी.एम. साहब, जींद के अन्दर वायदा करके आए कि झांज कलां, झांज

खुर्द, बड़ौदा दरियावाला, जाजवानखेड़ी, जाजवान और रूपगढ़ में पानी देंगे, बगैर पानी के वहां के लोग पड़पते हैं। उनका भी कुछ ख्याल करो। जो वायदा किया है, उसको पूरा करो। स्पीकर साहब, जयजयवन्ती में कांग्रेस वर्करज का कैम्प लगा। जो वहां आदमी इकट्ठे हुए वे सारे चोर, ठग और ब्लैक मार्किटर्ज थे जो वहां इक्ट्ठे हुए .....

कृशि मंत्री (चौ. भजन लाल): आन ए प्वायंट आफ आर्डर। स्पीकर साहब ये जो शब्द इस्तेमाल किए हैं यह बहुत ही गलत ओर अन–पार्लियामैंटरी हैं, उन्हें हाउस की कार्यवाही से निकाल दिया जाए।

चौ. दल सिंह: मैं गलती मानता हूं और जो लफ्ज इस्तेमाल किए हैं, मैं इनको वापिस लेता हूं।

Mr. Speaker: He has withdrawn the words .....

Ch. Dal Singh: Not only I have withdrawn those words but also begged his pardon. मैं कह रहा था कि आई.पी. सी. साहब उस कैम्प में गए और कहा कि जयजवन्ती, गढ़वाली, खेड़ाबख्ता, झमोला, करेला और गतौली इन गावों का पानी दिया जाएगा। मैं उनको यह वायदा याद दिलाना चाहता हूं कि आप इन गावों को पानी दीजिए। इनके एजेन्ट साजिश करते हैं और लोगों से कहते हैं कि मिनिस्टर को बुलाकर स्कूल बनवाएंगे या सड़क बनवाएंगे या अस्पताल बनाएंगे और लोगों से यह सौदा कर लेते हैं कि इतना पैसा मिनिस्टर साहब को देना पड़ेगा जिसमें से वे

अपने लिए रिजर्व कर लेते हैं। फिर मिनिस्टर साहब जाते हैं। उनके गले में हार पड़ते हैं तब यह काम का वायदा करते हैं। इस तरह से यह सत्यानाश कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं कि यह हरियाणा की पब्लिक का पैसा है। आपको लोगों ने यहां बनाकर भेजा है। आप उनके साथ इन्साफ करें, लोगों के दुखों को दूर करें। इस प्रकार के कामों से सरकार बदनाम होती है। आपका फर्ज है कि आप काम करें, आप मिनिस्टर हैं, आपको जनता की सेवा करनी चाहिए। इतना ही कहकर मैं समाप्त करता हूं और अगर कोई गलत बात कह दी हो, तो उसके लिए माफी चाहता हूं और इस प्रस्ताव का डटकर विरोध करता हूं।

चौ. शिव राम वर्मा (निलोखेड़ी): अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाशण पर चच्रा चल रही है और इसके लिए जो धन्यवाद प्रस्ताव आया है, मैं समझता हूं कि धन्यवाद किस बात का करने के लिए प्रस्ताव आया है। किस बात का धन्यवाद? एक बात हो सकती है कि हमारे राज्यपाल * * * * होते हुए भी यहां तकलीफ उठाकर आए और उन्होंने भाशण दिया जैसा कि वह एक साल में करते हैं इसके लिए तो ठीक है लेकिन इस भाशण में तो धन्यवाद की कोई बात नहीं लगती।

श्री अध्यक्ष: गवर्नर के मुताल्लिक यह रैफ्रेंस करना ठीक नहीं है * * * * के शब्द इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। It should be deleted.

चौ. शिव राम वर्मा: इस अभिभाशण में उन्होंने सबसे पहले जो चर्चा की। उन्होंने कहा कि देश अभूतपूर्व क्रमिक वर्धमान मुद्रास्फीति की कठिन आर्थिक परिस्थिति से गुजर रहा है, जिसके कारण आयोजना तथा द्रुत विकास समस्त राश्ट्रीय प्रयास में गतिरोध पैहा हो गया है। मैं कहता हूं कि मुद्रास्फीति किस की देन है, यह किसकी नीतियों का दोश है। मैं कहना चाहता हूं कि सरकार ने वह गलत नीतियां अपनाई जिससे देश के अन्दर मुद्रास्फीति बढ़ी, ब्लैक का रूपया बढ़ा, गल्त तरीके से लोगों ने रूपया कमाया और फिर वे गलत ढंग से खर्च किया और पैसे का इतना चलन बढ़ा कि देश के अन्दर सारी जरूरत

*अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की चीजें मंहगी होती चली गई जोकि गरीब के बस के बाहर हो गई। सरकार की नीति यदि ठीक होती तो मुद्रास्फीति पर काबू पाया जा सकात था, लेकिन सरकार नहीं चाहती थी। सरकार तो खुश है कि जो गरीब हैं, वे कंगाल होते चले जाएं और जो मध्य वर्ग के लोग हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं उनको भी सरकार चाहती है कि ऐसी नीति बने कि उनमें से सौ में से पांच–सात आदमी तो लखपति, करोड़पति बने और 90–95 जो हों, वे गरीब बन जाएं, क्योंकि इस सरकार ने एक तरीका अपनाया है, जिसको यह गलत ढंग की कमाई करवाती है, उससे करोड़ों रूपया चन्दे के रूप में वसूल करती है ओर फिर उसको गरीबों के अन्दर किसी

ढंग से खर्च करके उनकी वोट को लेने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए सरकार ने जो नीति अपनाई है उसमें देश प्यार की कोई बात नहीं है, अपने प्रान्त के सुधारने की बात नहीं है। केवल एक चीज सातेन है कि कुर्सी बनी रहे। देश से और देश की जनता से कोई प्याल नहीं है, केवल अपनी कुर्सी से प्यार होने के कारण यह सारी नीतियां चल रही हैं। इसमें सुधार की बहुत आवश्यकता है। इसके लिए सरकार यदि अपनी नीतियां नहीं सुधारेगी तो फिर मैं समझता हूं कि यह अभिभाशण चाहे कितने ही लच्छेदार दे दिए जाएं और साथ ही साथ और प्रशंसा के पुल बांध दे तो भी कोई सुधार आने वाला नहीं है और इस भाशण में अपनी गलती भी मानी हे, अपनी कमियां भी मानी हैं और उनको तोड मरोड़ कर अपनी प्रशंसा करने की कोशिश की है। एक बात जो सबसे जरूरी है अपने प्रान्त के लिए इस देश की अन्न की पैदावार बढ़ाने की है, क्योंकि हमारे देश के अन्दर, यह एक कृशि प्रधान देश होते हुए भी, इसका किसान मेहनती होते हुए भी यहां हम अपनी जरूरत के लिए अन्न पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका कारण सरकार की नीतियां ही हो सकती हैं। क्यौंकि एक बार थोड़ा सा किसान की ओर ध्यान गया था, तो उस वक्त इस हरियाणा ने किसान की, पंजाब के किसान की, बल्कि सारे भारत के किसानों की मेहनत ने, इस देश को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया था। फिर इस सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण कुछ ही दिनों के बाद इस बात ने पलआ खाया, फिर देश एक उलझन में फंस गया। इसका कारण यह था कि इस प्रान्त की

सरकार ने परमात्मा का धन्यवाद नहीं किया था, किसान को शाबाश नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने अपने ही मुंह से अपनी तारीफ करनी शुरू कर दी कि हमने वह ढंग अपनाया, यह ढंग अपनाया कि जिससे हमने अनाज की पैदावार बढ़ा दी और बजाए इन्द्र महाराज भगवान के गुण गाने के इन्द्रा जी ने भजन शुरू कर दिए, इस पर भगवान नाराज हो गए और उन्होंने बारिश बन्द कर दी और बारिश बन्द होने के कारण इनके बिजली और पानी के सारे प्रयास खत्म हो गए और उसका नतीजा सबके सामने आया। अगर बारिश होती है, तो ये उछलते कूदते हैं, खुशियां मनाते है और अपनी प्रशंसा आप ही करते हैं ओर अगर फिर बारिश नही होती, तो फिर दोश भी इनको अपने ऊपर ही लेना चाहिए, वह कसूर भी फिर अपना ही मानना चाहिए। यदि देश के अन्दर कोई आपत्ति आती है तो फिर उस देश के राजा का ही दोश माना जाता है। यह शास्त्रों में लिख हुआ है, पढ़ लीजिए।

एक आवाज: पहले तो आकी सरकार भी थी।

चौ. शिव राम वर्मा: यदि सरकार का कुछ दोश होता तो परिणाम सामने आने चाहिए थे। स्पीकर साहब, इस साल पिछले साल से जयदा अनाज इस देश के अन्दर बाहर से मंगवाना पड़ा है और सरकार मंगवा भी रही है। इसका सबसे मोटा कारण जो अभी मैंने बताया है, वह है सिंचाई साधनों का न बढ़ना और दूसरा कारण यह है कि किसान को खेती की उपज का उचित मूल्य न देना है। 1968 में 76 रूपए क्विंटल गेहूं का और 51 से

53 धान का मूल्य सरकार ने तय किया था। 1968 से 73 तक 6 साला लगातार एक ही भाव रखे गए, क्योंकि तीन साल के बाद 1970 में या 1971 में अनाज की पैदावार बढ़ी और उस वक्त सरकार ने यह सोचा कि अब किसान को ठीक मूल्य न भी मिले, तो भी पैदावार तो फिर भी नहीं घटेगी ओर सरकार ने यह समझा कि अब तो सारा मामला इसी तरह से चलता रहेगा लेकिन सरकार ने यह नहीं सोचा कि किसान को जिन–जिन चीजों की आवश्यकता है, खाद की, घर की आवश्यकता की चीजों की, उनकी कीमत तो हर साल बढ़ती जा रही है, इन चीजों को उस वक्त सरकार भूल गई। लेकिन इस सरकार में जो चापलूस थे, पिटठू थे, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि किसान को अब अधिक अनाज पैदा करने की आदम पड़ गई है, अब यह पैदावार कम नहीं होगी लेकिन इस बात को वे भूल गए कि जब किसान के अन्दर ताकत ही नहीं रहेगी, तो यह पैदावार कैसे बढ़ेगी? यदि किसान का मन संतुश्ट न हुआ तो उसकी अगली फसल की पैदावार के ऊपर जरूर असर पड़ेगा और फिर देश के सामने बड़ी गम्भीर स्थिति पैदा होगी। वही सरकार सियानी होती है जो स्थिति को देखते हुए अच्छे भाव किसान को दिलवाने का प्रयत्न करती है। 6 साल तक एक ही भाव रहे और किसान अनाज मण्डियों में आने से 4 दिन पहले अनाज का भाव दुगना था लेकिन जब किसान की फसल कट कर मण्डियों में आ गई, उस दिन भाव आधे आ गए तो ऐसी बातों से किसान का मन दुखता है, किसान को सन्तुश्टि नहीं होती है। इस साल खाद के भाव भी दुगने हुए,

बिजली के रेटस भी बढ़े, डीजल के भाव बढ़े, डीजल और बिजली की सप्लाई भी कम हुई और इस बात को सरकार बिल्कुल भूल गई। इस सिलसिले में मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि यह सरकार सोचे कि जो पैदावार होती है उसके अन्दर मंहगी मेहनत खर्च होती है, मंहगी चीजें लगती हैं और इसके साथ–साथ किसान को अपने घर के लिए जो चीजे मिलती हैं, वह भी मंहगे भाव पर मिलती हैं, तो फिर किससान से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि वह पैदावार को बढ़ाता रहेगा, फिर इसका परिणाम कया हुआ कि पैदावार घटी इसके घटने में कुछ हिस्सा बारिश का न होना भी हो सकात है। इसके साथ–साथ सरकार ने यह दावा यिका कि हम बारिश के भरोसे नहीं रहेंगे ओर इस सरकार के कुछ पिट्ठू और चापलूस यह कहते फिरते हैं कि अब तो उंगली लगाने से ही पानी आ जाता है, लेकिन जो बिजली की सप्लाई है, वह तो पहले से भी कम है। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों एक ढिढोरा पीटा गया कि हरियाणा के हर गावं के अन्दर बिजली पहुंचा दी गई है, खम्भे और तारें भी पहुंचा दी गई हैं, लट्टू भी शायद जग गए हैं लेकिन इसके साथ साथ हरियाणा एक गांव को आखिरी गांव का नाम देकर वहां प्रधानमंत्री महोदया से स्विच आन करवाया गया। उसी दिन से हरियाणा प्रान्त के अन्दर बिजली की समस्या बढ़ती चली गई और उस बिजली के न होने के कारण से यह सारी स्थिति आज हमारे समोन हैं। बिजली देने के लिए इस सरकार ने जो दावे किए थे, उसको यह सरकार भूल गई कि हमने उस दावों को पूरा भी करना है या नहीं। फरीदाबाद, पानीपत,

जगाधरी मे ताप बिजली घरों का काम अभी तक आरम्भ नहीं किया गया है, क्योंकि इन्होंने यह समझ लिया कि अनाज पैदा होने लग गया है और अब इनकी क्या जरूरत है? लेकिन सरकार की अकल को मैं क्या कहूं कि हम यहां के किसान को तो उसके अनाज का भाव कम देना चाहते हैं, लेकिन जो बाहर से खरीदकर लाते हैं, वह किस भाव पर लाते है। यहा के किसान से दुगने भाव पर बाहर से अनाज लाया गया और इस साल भी शायद दुगने भाव पर आ रहा है, लेकिन जब हमारी सरकार बहार के किसानों को उनके अनाज का दुगना भाव देने के लिए तैयार है, तो यहां के किसान को उनके अनाज का दुगना भाव क्यो नही दिया जाता? जब किसान यह कहता आ रहा है कि पिछले 6 साल से दूसरी चीजों के भाव बढ़ रहे हैं, तो सरकार ने उस वक्त कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन जब सरकार ने किसान की आवाज न सुनी, तो फिर किसान ने आवाज उठाई कि दूसरी चीजों के भाव बढ़ने से रोको, हमारी रोजमरा की जरूरतों की चीजों के भाव रोको, खाद के भाव कम करो, जोकि हमारी रोज की आवश्यकता की चीज है ताकि फिर हम मंहगाई का सामना कर सके, तो उस वक्त सरकार ने किसानो को कोरा जवाब दे दिया। यहो पर कहा गया कि हम अनाज के भाव नही बढ़ंने देगे, पार्लियामैट में भी यह कहा गया कि हम बाहर के मुल्क के किसानो को ज्यादा दाम इसलिए देते है, कि उनका जीवन स्तर उंचा है और यहां कि किसानों को इसलिए कम देते है कि इनका जीवन स्तर नीचा है। यहां के किसान को अगर आप अधिक पैसा देंगे, तो वह पैदावार

बढ़ाएगा और पैदावार बढ़ने से इस देश की अपनी भलाई होगी। आज हम जो भिखारी बने फिरते हैं हम दूसरे देशों के सामने झोली फैलाए फिरते है कि दाने दो दाने दो उससे हम बच जाएंगे। यदि किसान को उचित दाम मिलेंगे तो उपज बढ़ेगी और विदेशी मुद्रा की बचत होगी। इसके साथ–साथ अगर किसान के घर पैसा आएगा तो उस पैसे का हिस्सेदार मजदूर भी होगा, और दुकानदार भी हेागा। अगर किसान की हालत सुधरेगी, तो उन लोगो की हालत भी सुधरेगी, और देश भी खुशहाल होगा। लेकिन इस सरकार ने अपनी किसानों से नहीं खरीदा। वहां पार्लियामैंट में जवाब दिया गया कि हम बाहर के किसान को ज्यादा पैसा इसलिए देते है कि उनका जीवनस्तर ऊंचा है और यहां के किसान को इसलिए पैसा कम देते है कि इसका जीवन स्तर नीचा है। यह सरकार यहां के किसान का जीवन स्तर नीचे ही रखना चाहती है।

कई आवाजें: यह आपने कहां से पढ़ा है?

चौ. शिव राम वर्मा: पिछले साल की पार्लियामैंट की प्रोसीडिंग्ज पढ़ी। आखें बन्द करने से कबूतर को बिल्ली नही छोड़ेगी। उसके लिए यत्न करना पड़ेगा। तो इस सरकार की बाहर के किसान को ज्यादा पैसा देकर अनाज लेने की नीति कहो की अक्लमंदी है और यहां के किसान को थोड़ा पैसा देना कहां की अक्कलमंदी है? तो आज भी बाहर से गेहूं मंगाने के लिए दो सौ रूपए से कम कीमत नहीं देनी पड़ेगी (–घंटी–)

श्री अध्यक्ष: प्लीज वाईड अप।

चौ. शिव राम वर्मा: स्पीकर साहब, अगर यह घंटी आप न बजाएं, तो बड़ी मेहर बानी होगी। अभी तो मैंने शुरू ही किया है।

श्री अध्यक्ष: अगर आप दोनों की तरफ से बोलना चाहते हैं बोल लो।

चौ. शिव राम वर्मा: मैं दूसरे के लिए कैसे कह सकता हूं? तो मैंने मोटे तौर पर यह बात कही थी कि किसान के लिए यदि यह सरकार सोचती तो देश की समस्या कभी की हल हो जाती। तो इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए यदि हमको देश का भला करना है तो हमें देश के अन्दर की पैदावार बढ़ानी पड़ेगी। इसके साथ–साथ मैं दूसरी बात कहना चाहूंगा कि खाने वाले को कभी सस्ती चीज नहीं मिली। सरकार किसान से गेंहू 76 रूपए क्विंटल ले और खाने वो को वही गेहू सवा सौ या डेढ़ सौ रूपए के भाव मिले। इस साल 105 रूपए क्विंटल सरकार ने लिया जिसके ऊपर सरकार को कोई खर्च नहीं हुआ और जो 105 से ऊपर खर्चा था, वह दूसरे व्यापारियों ने दिया।

समाज कल्याण तथा कराधान मंत्री (श्री श्याम चन्द): स्पीकर साहब, आन ए प्वायंट आफ आर्डर। इनको पता होना चाहिये कि 105 रूपये तो स्पोर्ट प्राइस थी कि अगर 105 से नीचे आएगी तो सरकार खरीदेगी।

चौ. शिव राम वर्मा: क्या यह प्वायंट आफ आर्डर है? ये मिनिस्टर साहब हैं इनको समझाइये। तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार 105 रूपये क्विंटल गेहूं किसान से लेकर 136 रूपये क्विंटल राशन की दुकान पर देगी। तो यह 31 रूपये क्विंटल का मुनाफा है। कौन लगा 136 के भाव पर? पता लगेगा कि खाने वाला ही उसे लेगा, तो खाने वाले को कभी सस्ता नहीं मिला है। इसलिए इस सरकार को इस बारे में भी अपनी नीतियों में सुधार लाने की बड़ी भारी आवश्यकता है। बिजली के बारे में मैंने चर्चा की, पानी के बारे में भी की –(घंटी)– यह सरकार रोज कहती है कि हमने इतने टयूबवैलों को आर बढ़ाया है, इतने कुनैक्शन और दिए हैं। लेकिन टयूबवैल चलते कितने हैं और आबपाशी कितनी होती है, कितनी पैदावार बढ़ी है यह चीज देखने की है? इस सरकार का तो वह काम है कि जैसे किसी व्यक्ति को दरिया के किनारे से उठाकर उसको बीच में छोड़ दे तो वह बेचारा न इधर का रहता है, और न उधर का तो ऐसा करना उसके साथ अन्याय है अब नलकूपों को ले लीजिए पिछले 15–16 दिनों में सारे हरियाणा में एक दो दिन से बिजली आई है, तो बताओं नलकूप क्या करेंगे। यह तो परमात्मा की कृपा हो गई कि थोडी सी वर्शा हो गई वरना तो बुरा हाल था, इसलिए सरकार को इधर भी सोचना चाहिए। –(घंटी)–

श्री अध्यक्ष: प्लीज वांइड अप।

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, अभी कुछ भी नहीं बोला हूं।

श्री अध्यक्ष: आप 20 मिनट से ज्यादा ले चुके हैं।

चौ. शिव राम वर्मा: मैं तो शायद 6.10 से लगा था।

श्री अध्यक्ष: आपने 6.05 से बोलना शुरू किया था।

चौ. शिव राम वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मेरे से पहले बोलने वाले तो करीब एक एक घंटा बोल चुके है। तो मैं आगे कहना चाहता हूं कि सिंचाई साधनों पर नई–नई योजनाओं पर धन खर्च किया गया, लेकिन फिर भी सिंचाई अैर पैदावार बढ़ी नहीं। अगर मैं यह कहूं कि विकास के नाम पर यह लूट चल रही है तो गलत नहीं होगा। इसमें सुधान लाने की आवश्यकता है, मुझे आशा है कि सरकार इस ओर ध्यान देगी। इसके साथ–साथ मैं कहना चाहूंगा कि किसान के जो भाव की बात है, वह कारखाने का और किसान के कच्चे माल के साथ पक्के माल का जो भाव है, उसमें तालमेल बैठाने की बात है, मैंने पहले क्वैश्चन आवर में भी कहा था स्वर्गीय श्री रफी अहमद किदवाई का फार्मूला था कि किसान के गन्ने का भाव चीनी के भाव के साथ मिलाकर तय करना चाहिए। ऐसा कब तक चलता रहेगा, यह सरकार कब तक इसको उचित समझती रहेगी? आज कपास के भाव घट रहे हैं, कपड़े के भाव बढ़ रहे हैं और दूसरी कोई भी चीज आप ले लीजिए ठीक भाव पर किसान को क्या मिलता है? जवाब होगा कुछ भी नही।

लेकिन जो दूसरे बीय में हैं, स्मगलर हैं, वे कितना इसमें कमाते हैं यह समझने की आवश्यकता है। इसके अन्दर पशुधन के सुधार के लिए भी एक बात आई। पशुधन का सुधार बहुत आवश्यक है, क्योंकि इसका ताल्लुक खेती के साथ जुड़ा हुआ है। परन्तु जितनी बातें होती हैं, उतने काम नहीं होते। इस हरियाणा से हर रोज हजारों पशु बीमारी और बेकारी के नाम पर बाहर जा रहे हैं। मैंने कई बार सुझाव भी दिया है कि यदि सरकार इन पशुओं को रोक कर गऊ शालाएं खोले, गो–सदन खोले और उनके अन्दर इन पशुओं का इलाज किया जाए, उनको अच्छी खुराक दी जाए, अच्छा बीज डालकर अच्छी नसल पैदा की जाए तो हरियाणा में पशुओं की नसल सुधर सकती है। लेकिन जब सोचा ही नहीं होगा तो नसल कैसे बढ़ेगी। तो पशु जो बाहर जा रहे हैं, उनको यहां रोककर रखा जाए। इसके अलावा जींद के अन्दर जो मिल्क प्लांट है .....

Mr. Speaker: The House stands adjourned till 9.30 a.m. tomorrow.

18.30 बजे

(The Sabha then adjourned* till 9.30 a.m. on Tuesday, the 7th January, 1975.)

APPENDIX

to

Haryana Vidhan Sabha Debates Vol. 1 No. 4

dated the 6th, January, 1975.

Operation of Haryana Roadways Buses

***1120. Sh. Behari Lal Balmiki**: Will the Minister Development be pleased to state –

(a) the daily average total number of kilometers operated the Haryana Roadways during the years 1972-73 and 1973-74 separately;

(b) the said daily average number of passengers carried by said Roadways during the years 1972-73 and 1973 separately; and

(c) the total income accrued to the Haryana Roadways during the years 1972-73 and 1973-74, separately?

विकास मंत्री (कर्नल महा सिंह):

(क)	1972—73	3.06 लाख किलोमीटर
	1973—74	3.59 लाख किलोमीटर

(ख)	1972–73	2.55 लाख किलोमीटर
	1973–74	3.33 लाख किलोमीटर
(ग)	1972–73	13.62 लाख किलोमीटर
	1973–74	16.45 लाख किलोमीटर